खरसिया तथा चन्द्रपुर के सिंचाई क्षेत्र में 1 लाख, 20 हजार एकड़ जमीन की सिंचाई की क्षमता में कमी आ जाएगी । इस क्षेत्र के किसानों में जबर्दस्त आक्रोश हैं । इस क्षेत्र के किसानों का कथन हैं कि वे उद्योग लगाने के विरूद्व नहीं हैं, लेकिन फसलों की कीमत पर उद्योग के पक्षधर भी नहीं हैं ।

इस क्षेत्र के किसानों ने कहा हैं कि सीपत में NTPC के द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाएगा, जिस पर NTPC ने करीब 20000 करोड़ रूपया खर्च किया हैं । किसानों के इस संकट को टालने के लिए उन्होंने मांग की हैं कि NTPC, लीलीधर नदी, हसदेव नदी, महानदी में एनीफट बनाकर तथा पाइप लाइन बिछाकर अपनी जलापूर्ति स्वंय करे, जिस पर कुछ सौ करोड़ रूपयों का खर्च आएगा । यदि ऐसा नहीं किया गया, तो इस क्षेत्र के किसानों को भविष्य में रबी फसल के लिए पानी नहीं मिल पाएगा ।

अतः किसानों की मांग हैं कि हसदेव बांगों बांध के जल संग्रहण में से NTPC को 120 MCM जल की आपूर्ति न की जाए । मेरा केन्द्र सरकार के ऊर्जा मंत्री से अनुरोध है कि वे इस आसन्न संकट का हल निकालने के लिए पहले करें ।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now, discussion on the working of the Ministry of Rural Development. The total time allotted is four hours. Shrimati Brinda Karat.

DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

SHRIMATI BRINDA KARAT (West Bengal): Thank you, Sir, for giving me the opportunity to initiate the discussion on this very important Ministry. The Ministry of Rural Development has three departments, the Department of Rural Development, the Department of Land Resources and the Department of Drinking Water Supplies, and there are three demands related to the Ministry in the Budget. Obviously, we cannot go into all the details of the demands, but I will try and highlight some of the major issues to which I would like to draw the attention of the hon. Minister and the House.

महोदय, यह मंत्रालय महत्वपूर्ण हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि अन्य मंत्रालयों की तुलना में इसके पास कुछ अधिक पैसा हैं, लेकिन इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इस मंत्रालय के जो कार्यक्षेत्र हैं और समाज के जिन तबकों के welfare के लिए या अधिकर के लिए या विकास के लिए इस मंत्रालस की स्कीम्स हैं, वे हमारे देश की बहुमत जनता के लिए हैं । कहा जाता हैं कि भारत गांवों में जिन्दा हैं, लेकिन अगर हम हकीकत को देखें, तो भारत की जो पीड़ा हैं, गम हैं, दुःख हैं, शोषण हैं, वह सब गांवों में हैं । जब हम सामाजिक उत्थान की बात करते हैं, तो उसमें भी अधिकतर इस Rural Development Ministry के Scheduled Castes and Scheduled Tribes तबकों की बात होती हैं, जो इससे पीड़ित हैं । मैं यह मानती हूं और सरकारी आंकड़े भी यही दिखाते हैं कि successive सरकारों की जो आर्थिक नीतियां रहीं हैं, जिनको उदारीकरण की नीतियों के नाम से जाना जाता हैं, हकीकत यह हैं कि यही वे समाज के तबके हैं, जो उन उदारीकरण नीतियों के सबसे अधिक शिकार बने हैं । अगर हम एक ही आकड़े को लें, एनएसएस की 492 रिपोर्ट में भूमिहीन के विषय में उनके आंकड़े को लें, एनएसएस की 492 रिपोर्ट में भूमिहीन के विषय में उनके आंकड़े को देखें, 1992 से 2003 तक जो लोग भूमिहीन हुए हैं, 22 प्रतिशत से बढ़कर 32 प्रतिशत भूमिहीन हुए हैं । इस प्रकार भूमिहीन बढ़ रहे हैं और भूमिहीनों के अधिकर कम हो रहे हैं । शरद जी संयोग से यहां बैठे हैं, आपके मंत्रालय की भी यहां पर बहस होगी । मैं यह मानती हूं कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर और अन्य मंत्रालयों की रूरल डेवलमेंट के बारे में एक comprehensive सोच रहती और उनकी नीतियों का एक तालमेल रहता तो आज यह हालत नहीं होती । ये भूमिहीन हैं, जिनमें से लगभग 60 प्रतिशत के पास कोई बीपीएल कार्ड नहीं हैं और हमें इस बात का खेद हैं कि price-rise की बहस के जवाब में आदरणीय मंत्री जी, जो Comsumer Affairs और Public Distribution के मंत्री हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि सार्वजनिक प्रणाली की हम नहीं कर सकते हैं, हम inclusive बात करते हैं, लेकिन हम exclude करते हैं और जिनको हम exclude कर रहे हैं, वह सबसे गरीब हैं ।

सर, मेरा पहल मतलब यह हैं कि जो मंत्रालय हैं, अगर उसका एक comprehensive view होता और उस comprehensive view के आधार पर अगर रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय का कार्य होता, तो मैं समझती हूं कि जो क्षेत्र

J इस मंत्रालय के कार्य से प्रभावित हैं, उसमें और सकारात्मक प्रभाव हमको देखने को मिलता † दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहती हूं, तमाम मैं details मैं जाऊंगी, लेकिन जेनरली में कहना चाहती हूं कि जहां किसानों की जो मुसीबतें हैं, देश के सामने वह बहुत सही तरीके से सामने लाए गए। किसानों की आत्महत्या हो रही हैं, किसानों की acute distress हैं, वह सामने लाए हैं, लेकिन खेद की बात हैं कि किसानों का संकट का जो प्रभाव खेत मजदूर पर पड़ रहा हैं, उन खेतों पर काम करने वालों पर पड़ रहा हैं, उसका अभी तक कोई ज़िक्र नहीं हैं। सर, आप इस बात को सुनकर हैरान होंगे कि 24 साल से खेत मजदूर की कानून का प्रस्ताव आज भी इस सदन के सामने हैं, लेकिन आज तक वह हुआ नहीं हैं। कोई नेशनल मिनिमम वेज खेत मजदूरों के लिए नहीं हैं, इसके लिए priority नहीं हैं, यही मैं कह रही हूं। हमारे national consciousness में नहीं हैं, मैं यह भी कहना चाहती हूं। अगर हम उस पूरे मंत्रालय के काम को देखें, मैं मंत्री जी को इसमें कतई दोषी नहीं मानती हूं, लेकिन एक मानसिकता का सवाल हैं। सर, माइग्रेन्ट वर्कर का जो एक पहचान हैं, हम उस पहचान की क्या बात करेंगे, जब हमारे देश के economic survey में उस माइग्रेंट वर्कर का शब्द ही शायद नहीं हैं, संख्या की बात दूर रही, प्रोग्राम की बात दूर रहीं। सर, उसी तरह हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एक और बहुत बड़ी category हैं, मैं महिलाओं के बीच काम करती हूं, हमारी महिला समिति गांव की महिलाओं के बीच काम करती हैं, हमने पिछले 10-15 साल से एक ट्रेन्ड देखा हैं कि जो गांव से पलायन होता हैं, उसमें महिलाएं और बच्चे भी पलायन कर रहे हैं, लेकिन उससे मेल माइग्रेशन जो बढ़ा हैं, उसका जो असर उस गांव की औरत के ऊपर हैं, उसकी नाजुकता बढ़ी हैं, उसकी violence के प्रति नाजुकता बढ़ी हैं। हमारे पास न जाने कितने cases हैं, जहां फीमेल हेडेड परिवार को उस सामाजिक सीढ़ी में उसका सबसे कम दर्जा हैं, अधिकतर दलित हैं या tribal हैं या फ्रेश कास्ट की हैं, फीमेल हेडेड का मतलब मैं इस रूप में लेती हूं कि पूरा परिवार उस औरत की कमाई पर निर्भर हैं, उनकी संख्या बढ़ रही हैं, लेकिन हमारी राष्ट्रीय चेतना में, राष्ट्रीय दृष्टि में उनका कोई दर्जा नहीं हैं। जब मैं रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय की स्कीम्स की बात करूंगी, तब मैं चाहूंगी कि इन तमाम सेक्शन्स के बारे में, जिनका कोई ज़िक्र नहीं हैं, किसी भी प्रोग्राम में ज़िक्र नहीं हैं, जरूर वह दर्ज किया जाए, मैं यह कहना चाहती हूं।

सर, एलोकेशन की बात पर आने के पहले मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहती हूं, जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से संबंधित हैं, वह बीपीएल सेंसस और बीपीएल सर्वे। अब यह बहुत अजीब और विचित्र बात हैं कि पॉवर्टी का estimate प्लानिंग कमीशन करता हैं, लेकिन गरीबों की पहचान रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय के सेंसस के आधार पर होती हैं और दोनों में कोई तालमेल नहीं हैं। सर, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि सन् 2002 का बी.पी.एल. सेंसश का जो शेड्यूल हैं, निश्चित रूप में मंत्री जी ने उसको पढ़ा होगा। मंत्री जी के दिल में गरीबों के लिए बहुत बड़ा स्थान हैं, मैं मानती हूं लेकिन यह हमारी समझ में नहीं आता हैं कि आज भी इस मंत्रालय ने उस बी.पी.एल. के शेड्यूल को क्यों नहीं बदला ? क्या पहचान हैं ? अगर आप उसको देखेंगे, तो हैरान होंगे। यह पूछा जाता हैं और मेरे पास वह शेड्यूल हैं। आप फूड सिक्योरिटी का लीजिए – 4 प्वाइंट्स हैं, जो मापदंड हैं, 52 प्वाइंट्स हैं। 13 सवालों के –जिसका सबसे अधिक होता हैं, वह बी.पी.एल. कैटेगरी से बाहर हैं, जिसका सबसे कम होता हैं, वह बी.पी.एल. कैटेगरी, अंत्योदय में आता है। अब सुनिए यह जो सवाल हैं, अगर आपका ज़ीरो मिलना हैं, तो यह आपको दिखाना है कि एक बार भी साल के अधिक समय जब आप नहीं खाएंगे, तब आपको शून्य मिलेगा, लेकिन अगर आप एक बार खाते हैं, लेकिन पेट भरकर नहीं खाते हैं, तब आपको एक प्वाइंट मिलेगा। अगर आप एक बार खाते हैं, साल भर दिन में एक बार खाते हैं, तो आपको दो प्वाइंट मिलेंगे, आपको ज़ीरो नहीं मिलेगा और अगर आपने यह पाप किया हैं आप अपनी मेहनत से कम से कम दो बार खा लेते हैं, तब तो आपको तीन प्वाइंट्स मिलेंगे और अगर तीन प्वाइंट्स आपको सब सवालों पर मिलेंगे, तो आप गरीबी की रेखा के नीचे कभी माने नहीं जाएंगे। मेरे पास पूरा शेड्यूल हैं, लेकिन मैं पूरा पढ़कर नहीं सुनाऊंगी। कपड़े का भी हैं- अगर आपके पास छः कपड़े हैं, तब आपकों तीन प्वाइंट्स मिलेंगे। यह हैं बी.पी.एल. सर्वे। यह बी.पी.एल. destitution सर्वे हैं। एक समय एक नारा था "गरीबी हटाओ" और यहां एक ऐसा शेड्यूल हैं कि गरीबी हटाने का मतलब हैं कि गरीबों को सरकारी आंकड़ों से पूरा ही गायब करो, ताकि उनके प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी बने ही नहीं। तो मैं यह कहती हूं कि रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय का यह जो poverty identification सर्वे हैं, यह हमारे घाव पर नमक छिड़कने वाली बात है। आज आप गरीबों को कह रहे हो, अरे, राहत की बात तो दूर रही, तुम पहले मेरे सामने आकर साबित करो कि तुम गरीब हो। एक औरत जाकर कहती हैं कि मैंने खाया नहीं हैं, लेकिन वे कहते हैं कि नहीं, हमने तो ....इंस्पैक्टर राज बड़ी कंपनियों के लिए नहीं हैं सर. इंस्पैक्टर राज तो उस गरीब परिवार के लिए हैं, सके घर पर जाकर इंस्पैक्ट करेंगे कि एक बार खाए हो, दो बार खाए हो, कितनी बार खाए हो। यह हैं ....(**व्यवधान**).... मैं yield नहीं कर रही हूं। ....(**व्यवधान**).... तो इसलिए ....(**व्यवधान**).... सर, मैं फिर भी कहना चाहती हूं कि ....(**व्यवधान**)....

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please, Mr. Aggarwal. ...*(Interruptions)...*

श्रीमती वृंदा कारत: मैं इस बात को ....(**व्यवधान**).... सर ....(**व्यवधान**)....

THE VICE-CHAIRMAN: Please, Mr. Aggarwal. ...*(Interruptions)...* प्रभा जी, बैठिए। ....(**व्यवधान**)....आप बैठिए ...पाणि जी, बैठिए। ....(**व्यवधान**).... प्लीज़ आप लोग बैठिए। ....(**व्यवधान**).... आप बैठिए Please ...*(Interruptions)...* What is this? ...*(Interruptions)...* Please take your seat. ...*(Interruptions)...* Please dont disturb. ...*(Interruptions)...*मिस्टर पाणि, आप बैठिए। ....(**व्यवधान**)....ठीक हैं, आप बैठिए। ....(**व्यवधान**).... Please take your seat, Mr. Pany. When your party's turn comes, then you can speak.

श्रीमती वृंदा कारत: मैं कहना चाहती हूं कि यह बंगाल, केरल, त्रिपुरा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का सवाल नहीं हैं। आज हम MoRD के बारे में बात कर रहे हैं और यह MoRD को शेडयूल हैं और मैं जानती हूं, मैं समझती हूं कि मंत्री जी के दिल में व्यथा ज़रूर होगी, लेकिन वे करेंगे क्या ? प्लानिंग कमीशन के भरोसे बैठे हैं। उनको कौन चुनौती दे ? मैं मंत्री महोदय से अपील करती हूं कि आप इसे देखिए। आप हमारी बात छोड़िए, स्टैडिंग कमेटी की बात हैं। स्टैडिंग कमेटी ने 2003 में यह सिफारिश दी थी Fifty-fourth Report of the Standing Committee in 2003-04 जिसमें कांग्रेस के भी साथी थे, उन्होंने क्या सिफारिश दी थी ? They expressed concern over the instruction by the Planning Commission to State Governments to restrict the number by identifying BPL families below the arbitrary cut-off level. They have said, "Avoid a truly objective and scientific method for the identification of BPL families. क्यों आप स्टैंडिंग कमेटी का कहते हैं। जब आपके फायदे का होगा, तब आप ऐक्सेप्ट करेंगे और जब आपके नुकसान का होगा आप ऐक्सेप्ट नहीं करेंगे। यह क्या मतलब हुआ ? मैं यह मांग करती हूं कि यह बीपीएल सर्वे एक धोखा हैं, बीपीएल सर्वे का आइडेंटिफिकेशन एक धोखा हैं इसको बदलना चाहिए। मैं मंत्री जी से कहती हूं कि इसको बदला जाए। अब मैं ऐलोकेशस के ऊपर आती हूं। अच्छी बात यह हैं कि 42,400 करोड़ रूपए का ऐलोकेशन तीनों डिपार्टमेंट्स के लिए हैं। इसमें पांच हजार करोड़ रूपए की बढ़ोतरी हैं, 13 परसेंट या लगभग ऐसी ही कुछ बढ़ोतरी इस पूरी मंत्रालय के लिए हैं। लेकिन अगर आप उसको देखें कि कहां से क्या हो रहा हैं तो हैरानी की बात यह हैं कि रूरल इम्प्लॉयमेंट, जो इस मंत्रालय का सबसे अधिक और मुख्य flagship programme हैं, क्या हुआ हैं कि एसजीआरवाई को अभी रूरल इम्प्लॉयमेंट गांरटी में जोड़ दिया गया हैं। बाकी जितनी भी इम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं, वे सब रूरल इम्प्लॉयमेंट गांरटी में जुड़ गयी हैं। उसके हिसाब से अगर आप देखें तो एक्चुअली जो फाइनेंस मिनिस्टरी का ऐलोकेशन हैं, इस पूरे रूरल इम्प्लॉयमेंट के लिए ,वह केवल 200 करोड़ हैं। आप तमाम रूरल इम्लॉयमेंट गांरटी स्कीम्स को देखें, एसजीआरवाई पर जो खर्च हुआ हैं, क्योंकि अब उसमें 600 डिस्ट्रिक्ट्स जुड़ गए हैं। एक और बात इसमें बड़ी अजीब हैं कि रेगा के लिए जिलों की संख्या डबल हो गयी, लेकिन जो ऐलोकेशन हैं, वह केवल 33 परसेंट बढ़ा हैं। सौ प्रतिशत डिस्ट्रिक्ट्स की बढ़ोतरी हैं, लेकिन 33 परसेंट ऐलोकेशंस की बढ़ोत्तरी हैं। यह एक सवाल हैं। आप पूर्ण रूप से रूरल इम्प्लॉयमेंट में जो ऐलोकेशन की स्थिति हैं, उसकों देखें। अगर हम सब यह मानते हैं कि रूरल अनइम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या हैं। अभी जो 61 st राउंड एनएसएस के आंकड़े आए हैं, उसके अनुसार 5.6 परसेंट मेल की बढ़ोतरी हुई हैं और फीमेल की उससे भी ज्यादा हैं। निश्चित रूप से यह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हैं। ऐग्रीकल्चरल डेज़ कम हो रहे हैं। उसमें अगर आप इस ऐलोकेशन को डीजीपी की परसंटेज निकालकर देखें तो हकीकत यह है कि expenditure for creation of rural employment as part of GDP is down from 0.36 in 2005-06 to 0..27 in 2008-09. प्रोग्राम हमारा बहुत बढ़िया हैं, लेकिन उस प्रोग्राम के लिए ऐलोकेशन, जो पूरी ग्रोथ रेट हैं, जिसको हम इन्क्लूसिव ग्रोथ रेट को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सेनगुप्ता जी यहां बैठे हैं या नहीं लेकिन वे जानते हैं कि जो गांव का बेरोज़गार हैं, उस गांव के बेरोज़गार की इनकम फ्लकचुएटिंग हैं क्योंकि अधिकतर लोग असंगठित क्षेत्र में हैं। लेकिन उसके लिए percentage of GDP,the great GDP growth of eight to nine per cent कल चिदम्बरम जी केरल में थे। उन्होंने केरल में एक भाषण दिया – Those who oppose growth are enemies of people. हमने कहा, अगर हम यह कहें कि those who have policies to include real inclusion are enemies of the people तो क्या होगा। इसलिए enemies of the people, लोग तय करेंगे। लेकिन जो आंकड़े हैं, वह मैंने आपके सामने रख दिए हैं। मैं मंत्री जी से एक स्पष्टकीरण चाहूंगी कि

आपका जो बजट डिमांड नम्बर-80 हैं, उसमें रूरल इम्प्लॉयमेंट के लिए 13320 से 40400 करोड़ दिखाया गया हैं। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने भाषण ने अपने भाषण में 16 हजार करोड़ बताया था। इसका अगर स्पष्टीकरण हो जाए तो अच्छा रहेगा। सर, अब मैं स्कीम पर आना चाहूंगी। मैं इस बात की मांग करती हूं कि एलोकेशन बढ़े ताकि मंत्री जी का हाथ और मजबूत किया जाए, मंत्री जी की स्कीम्स को और मजबूत किया जाए। इसके लिए हम वित्त मंत्री जी से भी यह डिमांड करेंगे कि रूरल डवलपमेंट के लिए जो रूरत डव्लपमेट डिपार्टमेंट ने 20 हजार करोड़ की मांग की हैं, उसका समर्थन करते हुए हम चाहते हैं वित्त मंत्री जी इसके बारे में दोबारा सोचें। सर, मैं स्कीम के बारे में आती हैं। इस मंत्रालय के अंतर्गत पांच मुख्य स्कीमें हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण स्कीम हैं। मैं दो-तीन स्कीम्ज़ को लूंगी, पहले रेगा के बारे में हैं। इसके बारे में मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं रेगा को लाने के लिए, रेगा को अमल में लाने के लिए मंत्री जी ने रेगा में जो त्रुटिया हैं उनको दूर करने के लिए एक मिशन मोड में काम किया। मैं समझती हू कि उनका यह बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, सर, मैं यह भी मानती हूं कि आज रेगा उदारीकरण की नीतियों का जो आधार हैं कि गरीबों को अपने बाजार के ऊपर छोड़ों, क्योंकि यह सब पैसा बर्बाद हो रहा हैं और यह सब बेकार की चीजें हैं। जब एक लाख करोड़ रूपया ब्लैक मनी हिन्दुस्तान की इकोनॉमी हैं, तो उन शख्सों की जुबान पर कोई एक शब्द नहीं आता हैं। लेकिन रेगा के ऊपर जो पैसा खर्च हो रहा हैं, उसको कैसे कम किया जाए, उस पर दवाब डाला जाता हैं। सर, मैं रूरल डवलपमेंट मिनिस्ट्री की कसंलटेटिव कमेटी में हूं और मैं जानती हूं कि हर मोड़ पर इस कानून को सेबोटाइज करने के लिए, कमजोर करने के लिए खुद एक ऐसी पॉवरफुल लॉबी हैं जो इस स्कीम को कमजोर करना चाहती हैं। हमारी पार्टी का शुरू से ही इस स्कीम के बारे में सकारात्मक हस्तक्षेप रहा हैं। इसको और मजबूत करने के लिए जो त्रुटियां थीं पहले दस्तावेज में, उसको बदलने के लिए, उसको और मजबूत करने के लिए हमारा एक रोल रहा है और अमल में लाने के लिए भी हमारी एक पूरी कोशिश हैं। इसलिए मैं इस स्कीम के बारे में एक सकारात्मक दृष्टि से कुछ समस्याएं रखूंगी, ताकि यह स्कीम और गरीबों के पास पहुंचे। आज तीन करोड़ गरीबों के पास पहुंची हैं, मैंने देखा हैं कि मंत्रालय का एसेस्मेंट इस साल चार करोड़ या साढ़े चार करोड़ या पांच करोड़ तक का हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं, मुबारकवाद देती हूं। लेकिन उसके लिए जो प्रावधान की जरूरत है, मैं उसके बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहती हूं। रेगा की सबसे बड़ी समस्या यह हैं कि अधिकतर लोगों को न्यूनतम वेतन प्राप्त नहीं हो रहा हैं और लोगों को न्यूनतम वेतन इसलिए नहीं मिल रहा हैं क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी नॉर्म्स हैं वे बहुत ही हाई हैं। प्रोडक्टिविटी नार्म्स अगर सौ क्यूबेक फीट एक दिन के अर्थ वर्क में किया जाएगा, मैंने किसी इंजीनियर से पूछा कि मिट्टी में कितना होगा ? उन्होंने कहा कि 1600 के.जी. से 2000 के.जी. तक। एक महिला को कहते हैं कि अगर आप 100 क्यूबेक फीट- 1600 से 2000 के.जी. मिट्टी उठाओगे तभी आपको न्यूनतम वेतन मिलेगा और अगर नहीं करोग तो न्यूनतम वेतन नहीं मिलेगा। मैं समझती हूं कि अगर यह नियम रहे तो रेगा राहत के बजाए सस्ते श्रम का एक सोर्स बनेगा, जो हम नहीं चाहते। इसलिए हमने बार-बार कहा कि प्रोडक्टिविटी नॉर्म्स को नीचे कीजिए। मंत्री जी ने उस मांग का साथ दिया और एक सर्क्युलर भी निकाला कि टाइम बाउंड स्टडीज कीजिए और 6 स्टेट में करके गरीबों पर कुछ फर्क पड़ा हैं। लेकिन आज भी मिनिमम वेज नहीं मिल रहा हैं। मैंने पिछली बार भी इस सदन में यह सवाल उठाया, मंत्री जी नाराज हो गए थे। उन्होंने कहा कि चिट्ठी दीजिए, हम उसका जवाब देंगे। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि यह क्या हैं, 14 जनवरी का एक नोटिफिकेशन हैं। it is an amendment to schedule I of the act.

"The working days of an adult worker shall be so arranged that inclusive of intervals of rest, if any,...."—these words are added there if any

....it shall not spread over more than twelve hours on any day." That is fine because sometimes, workers work in the morning; they break for noon and they work in the afternoon because it is too hot in the afternoon. That is okay. But please note the words 'if any.

Then, the other amendment is:

"The schedule of rates of wages for various unskilled labourers shall be so fixed that an adult person working for nine hours would normally earn a wage equal to the wage rate,"

At present, under Schedule I of the Act, it is seven hours; seven hours excluding one hour of lunch-break; seven hours plus one hour—eight hours सर, अभी इन्होंने 9 आवर्स किया। उस दिन मैंने जब मंत्री जी से पूछा, तो उन्होंने कहा-नहीं। इसमें रेस्ट पीरिएड भी हैं, रेस्ट पीरिएड आप कितना देंगे, एक घंटा देंगे। मान लीजिए आप एक घंटा रेस्ट पीरिएड दें, आधा घंटा होता है, सर आईएलओ का कंर्वेशन क्या कहता हैं। आईएलओ का कंरवेंशन जिसकी भारत सरकार सिग्नेट्री हैंः Eight hours including lunch-hour break;that means seven hours. इसलिए मैं जानती हूं कि यह कहां से आ रहा हैं? इसका उस लॉबी से दबाव आ रहा हैं, मैं चाहूंगी कि मंत्री जी इसकी हकीकत बतायेंगे। मेरे पास यह खबर हैं कि बार-बार वह लॉबी इस पर जोर दे रहे हैं, भाई, तुम इतने पैसे खर्च कर रहे हो, मिनीमम वेज़ प्रदेशों का बढ़ गया हैं, काम नहीं हो रहा हैं, इसलिए काम बढ़ाओं और जो मिनीमम वेज की बढ़ोत्तरी हैं, वह अपने आप कम हो जायेगी, यह हालत हैं। इसलिए मैं समझती हूं कि यह जो नोटिफिकेशन हैं, वह इस एक्ट की स्प्रिट को बर्बाद करता हैं इसको वापस लेना चाहिए।

दूसरी बात, जिस पर बहुत बड़ी प्राब्लम REGA की हैं, फाइनेंसियल एलोकेशन की हैं। वित्त मंत्री जी ने कहा-कोई बात नहीं, जितनी मांग होगी, हम पैसे देंगे। कहां से देंगे, बजट से बाहर देंगे, सप्लीमेंट्री में देगे, यह अलग बात हैं, वह बता सकते हैं। लेकिन जो फाइनेंशियल एलोकेशन का तरीका हैं, मैं समझती हूं कि वह गलत हैं। क्यों गलत हैं ? अब एक स्टेट में डायरेक्टली सेंटर से डिस्ट्रिक्ट को भेजा जाता हैं और डिस्ट्रिक्ट को बराबर भेजा जाता हैं। मान लीजिए कि 50 करोड़ देने हैं और पांच डिस्ट्रिक्ट्स को देने हैं, तो डायरेक्टली पांच डिस्ट्रिक्ट्स को वे बांटकर दिए जाते हैं। चूंकि यह डिमांड आधारित कानून हैं, अगर किसी एक डिस्ट्रिक्ट में, मान लीजिए आज के महीने में हमारा ज्यादा काम हैं और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में क्योंकि weather conditions are different; everything is different. It is demand based. Districts will not have the same demand. One district may have more than the other. But one district cannot transfer to the other district अब हमारे पास कई मिसालें ऐसी हैं जहां एक डिस्ट्रिक्ट के पास पैसा नहीं था, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स जहां डिमांड नहीं हैं, वह पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाये, इसलिए जिला परिषद को लोन के हिसाब से वह देना पड़ा।

सर, मेरा मानना यह हैं कि फाइनेंशियल एलोकेशन स्टेट के साथ कंसल्ट करके सही तरीके से स्टेट्स को दें, तो स्टेट्स उसे डिमांड आधारित कर सकती हैं। इसका फायदा होगा, लेकिन इसके लिए पैस अधिक होने चाहिए, पाइपलाइन में पैसे होने चाहिए, अगर पाइपलाइन में पैसे नहीं हैं और अचानक डिमांड आ जाती हैं, तो पंचायत घबरायेगी। पंचायत कहेगी कि भइया, अगर हम तुम्हें काम दें और मेरे पास पैसा नहीं हैं, तो कहां से हम तुम्हारा वेतन देंगे हमारे ऊपर डंडा गिरेगा। इसलिए हो सकता हैं कि पंचायत उसको काम ही न दे। यह जो एक हालत यहां पर हैं, इसलिए मैं यह कहती हूं कि फाइनेंशियल एलोकेशन का जो तरीका हैं, उसको आप थोड़ा बदल दीजिए। मैं समझती हूं कि इसका बहुत फायदा होगा। तीसरी बात हैं। हम लोगों ने बार-बार कहा हैं कि अर्थ वर्क main हैं, अर्थ वर्क dry arid zones में लागू होता हैं। लेकिन जिन zones में हमारे देश में humid, semi-humid conditions हैं, जहां हायर रेनफॉल हैं, वहां पूरे रेनफॉल के समय अगर आप इस कानून को लागू करेंगे, तो आप कोई काम नहीं दे सकते हैं। काम की जो स्कीम्स हैं, उनमें निश्चित रूप से और फ्लेक्सीबिलिटी होनी चाहिए, यह हम लोगों ने डिमांड की। मैं एक बार फिर कहना चाहती हूं कि मिनिमम वेज अगर टॉस्क रेट के बजाय टाइम रेट होता है, तो इससे हमारे मज़दूरों को बहुत फायदा होता हैं। मैं चाहती हूं कि मंत्री जी इसके बारे में थोड़ा विचार करें।

सर, मैं SHG और SGSY के बारे में भी कहना चाहती हूं कि SHY और SGSY बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं। ये सैल्फ एम्प्लॉइमेंट आधारित स्कीम्स हैं। पिछले दस साल के अनुभव के आधार पर एनडीए की सरकार के समय और इस सरकार के समय, मंत्रालय की यह कोशिश रही हैं कि सैल्फ हैल्प ग्रुप्स के आधार पर वह SGSY को चलाए। हालांकि इंडिविजिअल कम्पोनेंट्स भी हैं, तो मैं समझती हैं कि यह स्कीम बहुत बेहत्तर स्कीम हैं। इस स्कीम के आधार पर, अधिकतर महिलाएं SGSY के सैल्फ हैल्फ ग्रुप्स में हैं, अगर वह स्कीम स्टेट और सैंटर दोनो मिलकर सही तरीके से चलाएं,तो मैं समझती हूं कि इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल हो सकता हैं। सर, इसमें प्रॉब्लम क्या हैं? आज भी स्टेंडिग कमेटी की रिपोर्ट टेबल पर रखी गई। मैंने लोक सभा की स्टेंडिग कमेटी की रिपोर्ट से देखा हैं कि सैल्फ हैल्प ग्रुप्स बन गए हैं, लेकिन सैल्फ हैल्प ग्रुप्स को लोन और पैसे देने के लिए एचिवमेंट बहुत ही कम हुआ हैं। मेरे ख्याल से 30 या 40 प्रतिशत ही हुआ है। अभी लोन्स के ये हालात हैं, तो SHG बन गए, महिलाएं अपने पैसे सेफ कर रही हैं, लेकिन लोन नहीं मिल

1.00 P.M.

रहा हैं। जब लोन नहीं मिल रहा हैं, तो मंत्रालय की तरफ भी जो रिवॉल्विग फंड हैं, उसमें भी एक बहुत बड़ी कमी आ रही हैं। अगर आप आंकड़ों को देखें, तो यह प्रोग्राम 2000 से शुरू हुआ हैं। आप यदि 2000 को देखें तो दिसम्बर, 2007 तक लगभग 47 लाख SHG बन गए हैं, 93 लाख स्वरोजगारियों को कुछ मदद दी हैं, 19 हजार, 3 सौ करोड़। अगर उसको व्यक्तिगत आधार पर, हर साल कितना पैसा मिला, यदि वह हिसाब लगाएं, तो कुल मिलाकर 2 हजार रूपए का हिसाब निकलता हैं, वह व्यक्ति, पर साल, पिछले दसा साल की एवरेज में। सर, 2000 के लोन से और 2000 की मदद से सभी जानते हैं कि गरीबी रेखा से ऊपर उठाने वाली यह स्कीम कभी कार्यान्वित नहीं हो सकती। इसलिए मैं इसमें अपने तीन सवाल सुझाव के रूप में रखना चाहती हूं। पहला यह हैं कि हमने अपने अनुभव से आन्ध्र प्रदेश में, जो SHG मूवमेंट का पॉयनरी स्टेट रहा हैं, हमने वहां एक सर्वेक्षण किया। हमने उस सर्वेक्षण में यह देखा कि जो SC,ST,SHG हैं, उसके अधिकतर ग्रुप्स खत्म हो गए, बंद हो गए क्योंकि वे औरतें इतनी संकट में हैं। कि उनके पास बीस रूपए, चालीस रूपए बचाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। हमारे पास यहां तक केसेज आए हैं कि वह औरत महाज़न से पैसे लेकर, SHG की तरफ से बचत के 6 महीने के पैसे नहीं दे पाए, महाज़न पैसे लेकर, SHG की उन्होंने पूर्ति की हैं, यह हालत हैं। इसलिए मैं यह सुझाव देना चाहती हूं कि जो SC,ST और बहुत गरीब औरतों को जो SHG हैं, अगर इस स्कीम को और व्यापक बनाकर, हम सेविंग्स की शर्त न लगाएं और अगर हम डायरेक्टली लिंकेज कराएं, तो यह महिलाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अगर आप सबसे गरीब औरतों की SGSY ग्रुप्स के लिए सेविंग की शर्त रखेंगे, तो वे सेविंग नहीं कर सकतीं। अगर वे पेट काटकर सेविंग करेंगी, तो क्या फायदा होगा, इसलिए मैं चाहती हूं कि आप इसके बारे में थोड़ा सोचें।

सर, दूसरी बात यह हैं कि आज हमारे देश में रूरल बैंकिंग सिस्टम, निजीकरण चलते हुए भी सब चौपट हैं और SGSY बैंक लोन्स, जो सबसे मुख्य सवाल हैं, बैंक लिंकेजिज सबसे कमजोर हैं, SGSY की स्कीम में RBI ने गाइडलाइंस दी, सब कुछ किया और फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक मॉनिटरिंग कमेटी है, यह भी मैं जानती हूं। लेकिन पता नहीं क्यों, जब गरीबों की स्कीम को सख्ती से लागू करने का सवाल आता हैं, तब उनके हाथ-पैर कमजोर हो जाते हैं और कहते हैं कि हम क्या करें, गाइडलाइंस तो दे दी हैं, लेकिन अमल में नहीं आ रही हैं। इसलिए आज बैंक लिंकेजिज SHG के लिए जो अधिकार हैं, इस स्कीम के तहत वह कतई नहीं हो रहा हैं। इसलिए bank linkage मजबूत करें, यह हम चाहते हैं। अभी छः लाख गांवों में commercial banks की केवल तीस हजार branches हैं। आप सोचिए कि अगर एक औरत को लोन लेना हैं, पैसों की व्यवस्था करनी हैं, तो वह कहां, कितनी दूर जाएगी। उसके आने-जाने के खर्चे में ही उसका आधा पैसा खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको कैसे और मजबूत करें, यह एक देखने वाली बात हैं।

सर, SHGs के फेडेरेशन का एक सवाल हैं। उसको बहुत लाभ हुआ हैं। इसलिए federating SHG को थोड़ा expand करें। इसके लिए स्टेट्स को और मदद दें, यह हम चाहेंगे।

मैं एक और बात कहना चाहूंगी, क्योंकि मंत्री जी एक ऐसी पार्टी से सम्बद्व हैं, जिस पार्टी के रेल मंत्री जी हैं। रेल मंत्री जी के पास तमाम रेलवे स्टेशंस हैं। अभी जब औरतें कुछ चीजें तैयार करती हैं। तो उनका retail outlet क्या होगा ? अभी हमने रेल मंत्रालय की बहस में देखा कि तमाम रेलवे स्टेशंस में मॉल बनाने जा रहे हैं, बड़ी-बड़ी दुकानें देंगे। मैं यह request करती हूं कि अगर तमाम रेलवे स्टेशंस पर SHG GROUPS के products को बेचने के लिए retail outlets की जगह दी जाती हैं और अगर मंत्री जी लालू जी से बात करके यह पॉलिसी के रूप में करवा लेते हैं, तो मैं समझती हूं कि यह बहुत ही अच्छा होगा। मैं यह भी कहती हूं , क्योंकि हम पैसे दे रहे हैं, हर प्रदेश सरकार मार्केटिंग के लिए कोशिश कर रही हैं, बहुत सारी सरकारें कोशिश कर रही हैं, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने मंत्रालय की जो जरूरतें हैं यूनिफॉर्म्स के लिए, खाने के लिए, बहुत सारी जो demands हैं जिन्हें वे मार्केट्स से लेते हैं, अगर वे SHG को demand देकर कुछ सालों के लिए guaranteed market तय करते हैं, तो इन गरीब औरतों का बहुत फायदा होगा मैं विशेष कर नॉर्थ-ईस्ट के लिए कहना चाहती हूं, क्योंकि नॉर्थ-ईस्ट एक ऐसा इलाका हैं, जो बिल्कुल cut-off हैं। अभी जब मैं त्रिपुरा गई थी, तो SHG की महिलाओं- Sir, I have got three schemes left. सर, जब मैंने त्रिपुरा का देखा-because these are very relevant issues. If I am talking irrelevant things, I can sit down. सर, त्रिपुरा का जो एक सवाल हैं, मैंने देखा कि वहां कम मार्केट्स मौजूद हैं। उसको बाहर भेजन के लिए जो एक सब्सिडी की जरूरत हैं, मैं समझती हूं कि यह पूरे नॉर्थ-ईस्ट क्षेत्र के लिए होगा, उसके लिए भी अपनी स्कीम में थोड़ा flexible होकर अगर आप geographical location देकर कुछ मदद कर सकते हैं, तो इसका बहुत फायदा होगा।

सर, अब मैं भारत निर्माण के ऊपर आती हूं। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की तीन स्कीम्स हैं, जो भारत निर्माण के अन्तर्गत partially आती हैं। उसमें और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं। वे हैं- हाउसिंग, रूरल सड़क और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। आप सब इस बात को मानेंगे कि ये तीनों सवाल भारत निर्माण से तो जुड़े हैं ही, लेकिन हमारी जिन्दगी को और उसकी क्वालिटी को सुधारने के लिए ये तीनों चीजें बहुत अनिवार्य हैं। मैं जानती हूं कि एक औरत, जो गांव में हैं, जब पानी नहीं होता हैं, तो वह दो-तीन घंटे unpaid work के रूप में अपने परिवार की पानी की जरूरतों को पूरा करती हैं। अगर आप पूरे देश भर के इन श्रम के घंटों को जोड़ेगें, तो आप देखेंगे कि उन औरतों का कितना जबर्दस्त शोषण हैं, क्योंकि गांव के पास पानी का स्रोत न होने के कारण दूर जाने के लिए उनके ऊपर कितना जबर्दस्त बोझ हैं।

मैं समझती हूं कि आईएवाई, इन्दिरा आवास योजना, एक बहुत ही अच्छी स्कीम हैं। पार्टी कोई भी रहे, लेकिन इसको तमाम सरकारों ने अमल में लाने की कोशिश की हैं। मैं समझती हूं कि इस बार हमारे बजट में plains के लिए और पहाड़ों के लिए घरों के लिए पैसों की जो बढ़ोत्तरी की गई हैं, यह बहुत स्वागत योग्य हैं। लेकिन अगर हम देखें कि स्टील और सीमेंट की cartels, इन सबको देखते हुए जितनी महंगाई बढ़ रही हैं, अगर उतने में घर बन सकता हैं, तो यह एक सवाल जरूर रह जाता हैं, क्योंकि अभी भी घरों को बनाने के लिए जितने पैसों की जरूरत हैं, बढ़ोत्तरी के बावजूद भी मैं समझती हूं कि यह नाकाफी हैं। लेकिन अगर आप टार्गेट्स को देखते हैं, तो unfortunately टार्गेट्स बहुत ही चिन्ताजनक हैं। अगर आप तीनों को देखें तो हम लोग रूरल हाउसिंग का केवल 51-% टार्गेट ही पूरा कर पाए हैं। अगर आप ग्रामीण सड़क योजना की ओर देखें, जो इतनी इम्पॉटेंट हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि उसका केवल 25% टार्गेट ही पूरा हो पाया हैं। अगर आप पानी की सप्लाई को देखें तो उसका भी केवल 52% टार्गेट ही पूरा हो पाया।

यह ठीक हैं कि इसमें प्रदेश सरकारों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हैं, इसे मैं कम करके नहीं आंकती हूं, लेकिन प्रदेश सरकारों के भी कुछ टार्गेट्स हैं, कुछ मॉनिटरिंग हैं और मैं यह जानती हूं कि मंत्री जी ने उन टार्गेट्स को बढ़ाने की बहुत कोशिश भी की हैं। लेकिन एक कमी तो रही ही हैं, आपको यह भी देखना होगा कि उन स्कीम्स के अन्दर भी कहीं कोई कमी तो नहीं हैं।

सर, मिसाल के तौर पर मैं हाउसिंग की बात करती हूं। आज हमारे देश में बहुत अधिक संख्या में गरीबों के पास कोई जमीन नहीं हैं कि वे उस पर अपने लिए घर बना सकें। बहुत सारे प्रदेशों में आप जाकर देखेंगे, कभी-कभी तो हम स्वंय उनसे जा कर पूछते भी हैं कि इन्दिरा आवास योजना का घर कहां बना हैं, तो पता लगता हैं कि वह गांव से कहीं बहुत दूरी पर बना हैं, जहां वे रह नहीं सकते। कुछ लोगों के पास जानवर इत्यादि भी हैं, उनके पास और तो कुछ हैं भी नहीं, उन्होंने उन जानवरों को भी वहां रखने की कोशिश की, लेकिन गांव से इतनी दूरी पर होने के कारण, उसमें भी वह कामयाब नहीं हो पाए। इस तरह वह घर अभी केवल एक फ्रेम बन कर रह गया हैं, वह घर, घर नहीं रहा हैं। ऐसा क्यों हुआ हैं? क्योंकि जमीन नहीं हैं।

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि इस पूरी इंदिरा आवास योजना की स्कीम में, विशेषकर जहां SCs का सवाल हैं, जिनकी संख्या भूमिहीनों में सबसे अधिक हैं, क्या इस स्कीम की अन्दर क्लोज़ मॉनिटरिंग के साथ हम यह भी जोड़ सकते हैं कि जिनके पास कोई जमीन नहीं हैं, सरकार उसी स्कीम के पैसों के अन्दर ही उनके लिए जमीन खरीद कर दे, जिस पर उनके लिए घर बनाया जा सकता हैं। अगर यह हो जाता हैं तो जमीन और घर, दोनों की समस्या दूर हो सकती हैं, क्योंकि बगैर जमीन के घर का कोई अर्थ नहीं होगा।

अभी मैंने आपको PMGSY के बारे में बताया। सर, वहां हो क्या रहा हैं कि जो सड़कों की मेंटेनेंस हैं, उसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकारों के ऊपर हैं। केन्द्र की ओर से सड़क बन कर तैयार हो जाती हैं, लेकिन प्रदेश सरकार के पास इतने पैसे ही नहीं हैं, इसलिए उनका मेंटेनेंस नहीं हो पाता, नतीजा यह होता हैं कि पांच साल के अन्दर वह समाप्त हो जाती हैं। इसलिए इस स्कीम को बढ़ाया जाए, जिसके तहत सड़क बनाने के बाद कम से कम कुछ सालों के लिए मेंटेनेंस का एक हिस्सा केन्द्र सरकार स्वयं दे। मैं समझती हूं कि यह बहुत ही जरूरी हैं।

जहां तक टोटल सैनिटेशन का सवाल हैं, This is also a very good scheme. हमने देखा हैं कि विशेषक्र महिलाओं के लिए जब शौच के लिए स्थान नहीं होता हैं, तो उनके आत्मसम्मान को कितनी चोट पहुंचती है, इसलिए घर में एक शौचालय अवश्य हो, इसका प्रबंध भी किया जाना चाहिए। लेकिन मिनिस्टर साहब से मेरा एक सवाल भी है कि ICDS के लिए जहां पहले 9000 करोड़ रूपये था, उसे कम करके 5000 करोड़ रूपये कर दिया गया,इसलिए मैं

चाहती हूं ...(समय की घंटी) Sir, I have just got this one thing left. मैं जानना चाहती हूं कि ऐसा क्यों किया गया हैं, इसको बदलने की जरूरत हैं। अगर हम समस्या को देखते हैं तो जो पैसा अभी इसके लिए दिया जा रहा हैं, वह नाकाफी हैं। इसलिए मैं यह कहती हूं कि हमें भारत निर्माण करना हैं, न कि भारत नुकसान। भारत निर्माण के कार्यक्रम को सही रूप में अमल में लाने के लिए और अधिक पैसे की जरूरत हैं, साथ ही स्टेट गवर्नमेंट के साथ तालमेल मजबूत किए जाने की जरूरत हैं, ऐसा मेरा मानना हैं।

सर, इनका जो अन्तिम डिपार्टमेंट हैं, वह लैंड रिसोर्सिज़ का हैं। लैंड रिसोर्सिज़ के लिए अभी 2500 रूपए दिए गए हैं, इसमें 900 करोड़ रूपये का इन्क्रीज हैं। लेकिन मैं कुछ सवाल यहां रखना चाहती हूं, शायद हमारे यहां और भी जो समझदार या जानकार सांसद हैं, वे इसके बारे में कुछ बता सकें। अभी एक रिपोर्ट आई हैं, 31st Report of the Department relating to the Demands for Grants, उन्होंने एक आंकड़ा दिया हैं, It is really amazing that between the years 2000 and 2005, these has been a reduction of wastelands of about 8.58 million hectares. इसका मतलब यह हैं कि जो वेस्ट लैंड हैं, जिस पर कुछ नहीं हो सकता था, उसमें 8.58 मिलियन हैक्टेयर की कमी हुई हैं। मैं यह नहीं समझ पा रही हूं कि यह कौन सा जादू हैं, क्योंकि अगर आप सरकार के आंकड़े देखें तो सरकार की तरफ से उस प्रकार की कोई स्कीम या पहल नहीं हुई, जिसमें 8.58 मिलियन हैक्टेयर्स वेस्ट लैंड कम हुई हो। अगर 8.58 मिलियन हैक्टेयर्स कम हुई हैं और यह वेस्ट लैंड अभी ऐसी उपजाऊ जमीन बन गई हैं या उस पर कुछ बन सकता हैं, तो सर, यह जमीन कहां गई, किसके पास गई ? अभी हमारे पास ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बहुत-सारी प्रदेश सरकारें भूमिहीनों को वेस्ट लैंड डेवलप करके जमीन देने के बजाय, जो पहले अर्थ था कि इन लैंड्स के ऊपर लैंड रिफॉर्म्स होंगे, वेस्ट लैंड को डेवलप करके भूमिहीनों को बांटों, लेकिन लैंड रिफॉर्म्स खत्म हो गया और डेवलप्ड वेस्ट लैंड किसको दी जा रही हैं? रिपोर्ट्स हैं कि बड़े-बड़े कॉरपोरेट हाउसेज को ये वेस्ट लैंड्स दी जा रही हैं। ये कहां हैं, क्या हैं, क्या उसकी जानकारी मंत्री जी के पास हैं, वह कम-से-कम हमारे सामने आनी चाहिए।

सर,दूसरी बात कि अगर लैंड रिफॉर्म्स में देखेंगे, तो जो हैरानी की बात हैं कि मैंने पिछले 10 सालों की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट्स देखीं हैं। हर बार वह पूछते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स का क्या हुआ, कितनी जमीनें लैंड रिफॉर्म्स में दी गई, कहां हैं लैंड रिफॉर्म्स का पूरा वह प्रोग्राम, जो एक राष्टीय मिशन के रूप में था, लेकिन यहां से कोई जवाब नहीं आता हैं। सर, लैंड एक स्टेट सब्जैक्ट हैं, यह बिल्कुल सही बात हैं, लेकिन कम-से-कम उसकी जानकारी दी जाए कि उसमें क्या हो रहा हैं,कहां हो रहा हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी बहुत-सारी जगहों पर जमीनें है, उनकी क्या पोजिशन है, वह जरूर देनी चाहिए। ....(समय की घंटी).... आंध्र प्रदेश की एक मिसाल हैं। वहा होमलेसनेस के खिलाफ एक जबर्दस्त् संघर्ष हुआ था। उसके बारे में भी एक अनुभव सामने आता हैं कि यह जो जमीन का सुधार या भूमि-सुधार का कार्यक्रम हैं, उसके बारे में सरकार को बहुत जोर देकर जवाब देना चाहिए।

मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूं। वह जैटरीफा के बारे में हैं

कहते हैं कि वेस्ट लैंड पर होगा, लेकिन साथ-साथ जो marginal peasants हैं या गरीब किसान हैं, उनकी जमीनों को लेकर भी सरकार उनको उत्साहित कर रही हैं कि आप भी जैटरोफा का कल्टिवेशन करिए। यह Bio-diesel के लिए सरकार का प्रोग्राम हैं और अभी प्रोग्राम में बताया गया कि इसे हम in mission mode करना चाहते हैं, लेकिन जब हम सरकारी आंकड़े देखते हैं तो वहां कोई डेटा नहीं हैं। कहां सक्सेस हुआ हैं, कहां सक्सेस नहीं हुआ, कौन-से-देश में जैटरीफा के आधार पर उसका क्या कुछ social cost impact assessment हैं या नहीं हैं? मैं सिर्फ कॉशन करना चाहती हूं कि अगर हम किसानों को उत्साहित कर रहे हैं कि आप जैटरीफा का कल्टिवेशन करें, तो उसकी गांरटी भी होना चाहिए। हम किसान को कितने साल की गांरटी दंगे, यह न हो कि बाकी कॉमर्शियल क्रॉप्स की आत्महत्या हो रही हैं। मैं सिर्फ cautionary note कहना चाहती हूं कि अगर हम जैटरीफा का कल्टिवेशन इस पैमान पर करें और उसका कोई MSP नहीं, उसका कोई डेटा बेस नहीं, उसकी कोई वैज्ञानिक जानकारी नहीं, लेकिन हम किसानों को कह रहे हैं कि तुम इसको करो, तो मैं समझती हूं कि इसको हमें थोड़ा कॉशसली करना चाहिए। सर, इसीलिए मैं चाहती हूं कि इसके बारे में मंत्री जी हमें थोड़ा बताएं कि 1500 करोड़ रूपए का कॉरपस किस रूप में होगा ? यह मैं बताना चाहती हूं।....(**व्यवधान**)....

उपसभाध्यक्ष (प्रो.पी.जे.कुरियन)**:** All points हो गये।

श्रीमती वृंदा कारत: सर, इसीलिए मैं कहना चाहती हूं कि अगर हम सम्पूर्ण रूप् में रूरल डेवलपमेंट को देखें, तो उदारीकरण की नीतियों के करण आज गांव के गरीब बहुत पीछे हैं। गांव के गरीब बहुत शोषित हैं। मंत्रालय की तरफ से जो किया जा रहा हैं, वह उस गरीबी के सागर के लिए बिन्दु-मात्र हैं।

सर, मैं मंत्री जी की कोशिशों को नकारना नहीं चाहती हूं, लेकिन मैं उनसे यह अनुरोध जरूर करूंगी कि इन नीतियों के खिलाफ जो हमारा संघर्ष हैं, इन नीतियों का जो किला और दुर्ग है, उसके खिलाफ भी मंत्री जी हमारे साथ आवाज उठाएंगे। यह उम्मीद करते हुए,मैं अपनी बात समाप्त करती हू। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): The House is adjourned for lunch till 2 P.M.

The House then adjourned for lunch at fifteen minutes past one of the clock.

The House reassembled at two of the clock after lunch.

(MR. VICE-CHAIRMAN PROF. P.J. KURIEN in the Chair.)

DR. E.M. SUDARSANANATCHIAPPAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak. Sir, really, I am proud of having participated in this debate. For the first time the fund from the Government of India for the Rural Development Ministry has come nearer to the top second, next to the Defence Ministry. No doubut, one day it may also overtake the first one and will be having first rank so that the entire India can develop on a fast track. When the NDA Government was ruling, they were allotting very meagre amount for the rural development. Take for example, for 2001-02, they allotted about Rs. 11,000 crores, for 2002-03, they allotted Rs. 18,203 crores, and for 2003-04, they allotted Rs. 19,228 crores. Immediately after assuming power, the UPA Government under the guidance of Madam Sonia Gandhi and great leadership of Dr. Manmohan Singh, it could raise the allotment for rural development to Rs. 18,167 crores (?) and immediately next year Rs. 27,489 crores were allotted. For 2006-07, Rs. 39982 crores were allotted. Sir, in 2007-08, Rs. 36,560 crores were allotted. Now it has galloped to Rs. 49,450 crores. So much of money is now pumped towards development. Sir, right from the days of Independence, Mahatma Gandhi was telling that you have to remember the Gram Rajya, that is, Ram Rajya. If you develop villages and the poor man who is living in the countryside, that development of India will be the real one and that will be *Suswraj.* It has been the approach of our Five year Plans. Even after developing irrigation and new methods of agriculture, the poverty in the rural areas could not be attacked. But Indira Gandhi brought the 20-Point Programme and she made the poor as the target group so that they could cross the poverty line. Therefore, she brought a great programme, the national Rural Employment Guarantee Scheme. Through that programme, every person can get employment and community assets can be created through that fund. Subsequently, it was developed into Rural Employment Guarantee Scheme Programme (REGP), where an assurance was given for hundred days to an individual who is ready to work, who is ready to use his physical energy for creation of assets, was implemented. But Sir, even though the Government of India at the National level allocated some money and programmes, it has to go through the system which we have created in the Constitution, *i.e.* the State Governments. When it goes to the State Governments, it has to percolate into the villages and into the hands of the poor people. We could not succeed there. Just like an overhead tank, which is filled up with water has to go down to the pipeline; somebody has to open the pipe. Then, that pipe has to bring water to the roads and also to the roadside and to the houses. Then, only the water, which is filled up in the overhead tanks, can be useful, Similarly, the Central Government has allotted money but nobody is there to open the tap so

that water can go down to the streets and also to the houses. Then, it happened. Then State Governments have to have the onerous duty of bringing money to the ordinary person. Then, only Madam, Indira Gandhi brought this system of having Rural Employment Guarantee Scheme Programme at that time. Subsequently, when Rajiv Gandhi became the Prime Minister, he went to the villages and found first hand information, of how one rupee, which is sent from the Central Government, reaches as 15 paise to the villages. Now, in Orissa, even now, only 10 paise is going. How that money goes, where it goes, where that 90 paise has gone was a question raised by Rajiv Gandhiji. Then, only he found that Panchayati Raj system has to be started and the people who are living in poverty, who are living in the villages have to be empowered by giving power to them. He has done it. I was at that time a Mandal Chairman, *i.e.* Panchayati Chairman at that time. I could see how the Panchayat Presidents were very happy to receive a draft in their name from Central Government by the name of Rajiv Gandhi. That Rs. 2 lakh is sent according to the population, Rs. 15 lakh is sent according to the population and the villages can sit and decide for which purpose this money can be utilised. That was the empowerment given by Shri Rajiv Gandhi and he wanted to make it as part of the Constitution itself, he made an effort to amend the Constitution so that the three-tier system should be in existence. But, that was not accepted by certain States and also certain parties. Therefore, he met with a failure but the subsequent Governments — even though it was not fully as efficient as Rajiv Gandhi — did not enact it but it was enacted in some way by creating a four tier system, *i.e.* the village level Panchayat *i.e.* the Zilla Panchayat, and intermediate level and the Panchayat level. But, now this three-tier system is in existence. Now, the system is, Sir, how much money the State Governments are allotting for rural development? They are fully depending upon the Central Government aids. They want to see that the money has to come from overhead tanks. They need not dig their own pipes there itself. They need not have their bore wells there itself. They don't want to have their own well there itself. They want to get the money from the overhead tanks. Somebody has to pump the money and the, they can spend from that. Sir, that is the situation now. Now, we have implemented lot of schemes in the rural areas, they are massive agricultural programmes. Such are the programmes. That was a very important programme on which the ordinary agriculturist can cultivate his own land and the money ...*(Interruptioons)...* utilised from the Central Government fund... *(Interruptions)...* and the money can be utilised from the Central Government for ordinary peasants in remote villages. He could enjoy that money. That exchequers' expenditure can be utilised for cultivating his own land, for reclaiming his own land. He can get very good irrigation facilities through that method. He can dig it in his own land. This is all was done during Shri Rajiv Gandhi's period. Sir, during that period, Rs. 1 lakh was given to people belonging to Dalit communities for getting a motor pump set so that they can pump water and irrigate their own land. If, in a community, ten people are united together, they can also avail of this facility. That was the vision of Shri Rajiv Gandhiji. Of course, everything was done through the Government orders. When the Government changed and a new Government took over the office, it ignored rural development. They never cared about the rural people. They never cared about development. They never cared about the poverty alleviation programmes. They were worried only to construct a 'big road' and sell it to contractors. Take for example, they enacted the Road Cess Act, 2000, and, through this legislation, they collected money from everybody and spent a certain percentage of money for the development of roads only in urban areas. They never thought that the Act should have a provision for rural areas and certain amount of money should be given for the development of villages. They never thought about it. They never allocated money for rural development. Finally, there was one programme. I don't want to hide that. There was a

scheme — Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. If a village is having a population of 500 that village is connected with another village with road. That was implemented when the NDA was in power. But, subsequently, that programme has not ended up well. Now we have the Bharat Nirman Programme by the UPA Government. Through this programme, the Government is connecting all villages with proper roads. Be that as it may, now the villages are connected with roads. There is sanitation and the necessary funds have also been allocated by the Central Government for this purpose. If there is no school in a village, school is constructed under the SSA. The NDA Government conceived the SSA. But, they could not fulfil the obligations. The UPA Government has done excellently in implementing this programme not only by constructing schools everywhere, but also through various other measures. But, these Schemes have been implemented by the State Governments ...*(Interruptions)*... Kindly, don't interrupt. Your Orissa State Government may be bad. I am not worried. I am only saying what is happening in villages ...*(Interruptions)*... Sir, I am not yielding ...*(Interruptions)*... At the same time, this money...

श्री रूद्रनाराण पाणि (उड़ीसा): सर, गुजरात के माननीय सदस्य ने कुछ कहा,लेकिन माननीय वक्ता श्री नाच्चीयप्पन जी बोल रहे हैं उड़ीसा गवर्नमेंट । यह क्या तरीका हैं ?

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN: I am telling you this, because you are doubting the present Government.

श्री रूद्रनारायण पाणि: माननी य सदस्य श्री नाच्चीयप्पन शायद दूसरे माननीय सदस्यों को पहचानते नहीं हैं, सर, नाच्चीयप्पन जी इतने पुराने सदस्य हैं, इन्होंने वर्तमान वित्त् मंत्री, श्री चिदम्बरम जी को चुनाव में हराया था । मेरा कहना यह हैं कि माननीय सदस्य को यह ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा सदस्य किस स्टेट से आता हैं ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI V. N ARAYAN ASAMY): Mr. Pany, if you want to say anything, you say when your turn comes.

SHRI RUDRA NARAYAN PANY: Sir, if he speaks something against, the hon. Member has to respond to that statement, not my State.

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN: Thank you Mr. Pani for recollecting past things.

Sir, I was saying that the villages are connected with roads and where there are no sanitary facilities or school buildings, they are provided under the SSA.

There is also a new scheme for giving old age pension in the name of Indira Gandhi Old Age Pension Scheme where the Government of India provides Rs. 200 per month and the State Governments provide matching grants which comes to Rs. 400 per month for a family. In the same manner, every destitute is getting 10 kg. of rice or wheat for his or her food. So, these are the new things that are happening. Many houses are being constructed under the IAY Sir, about 1.7 crore houses have been constructed throughout the country. I can give you the exact figures. Sir, huge money is being spent under IAY. Sir, 1.7 crore houses are built and Rs. 1,89,898.56 crores spent for this purpose. All this huge money was spent for the rural poor. They have got houses; they have got schools; they have got agricultural land; they have got roads; they have got water facilities; rural health schemes are "here, everything is there but there is no money in the hands of the poor people. They don't have employment. They can't earn their livelihood. A family with all that prestige, who is ready to toil, they don't have employment opportunities. When we talk about the Rural Employment Guarantee Scheme, that scheme has been misused by the contractors by writing false names and putting

the impressions of all their fingers and thumbs of hands and legs and getting the money. The benefit of this scheme had never reached to the ordinary man. The Governments had come and gone. They changed the Government orders; they even changed Jawaharlal's name and Indira's name when they came to power. That was the mind of the Government. That means they are not worried about the common man. But here, Madam Sonia Gandhi talked about the rural poor, who need work, who want to have income by toiling. That's why Madam Sonia Gandhi had brought the Rural Employment Guarantee Scheme, for the first time, in the history of India and in the whole history of the world. It is for the first time when statutory support is given for a guaranteed income of hundred days for a citizen who is ready to work for the nation for creating assets. She has guaranteed that minimum employment. That is a great thing which has happened in the history of India. We have to honour Madam Sonia Gandhi for bringing forward such an enactment. But that enactment, in the first instance, could be implemented only in 200 districts. And, one of such beneficiary districts is my own district. I have seen with my own eyes how people are happy over earning Rs. 80 to Rs. 100. In Tamil Nadu, the famous Government of DMK is ruling the State. They have brought forward a scheme for providing one kilogram of good rice for Rs. 2/-. Now, since the poor people are able to earn Rs. 80-100 per day, they can easily purchase rice for the entire family. The State of Andhra Pradesh has also brought forward the same scheme. We have promised to bring the same scheme in the State of Karnataka also once we win the elections in due course. And, I am sure the BJP will be thrown out. They know it. Therefore, the scheme has made a great impact. With Rs. 80 in the hands of the poor, they have got the purchasing power. Since the rice is available for Rs. 2 per Kg., they can easily purchase 10 Kg. of rice for Rs. 20/-. The entire family can have very good meal daily thrice. They are joyous that they are having an assured job, just like a Government servant can say that he has got an assured job. Here is a security job. The security is given. Not only that, they are even insured. If anything happens to him, his family will be paid Rs. 5,000 to Rs. 50,000. That is the social security scheme brought forward by Madam Sonia Gandhi through the Government of Dr. Manmohan Singh. That has now been achieved. Crores of people are getting that benefit. The people are happy. The purchasing power of the ordinary man, the *aam aadmi* has, now, increased.

We have also got another programme for the old-age people. If they can't work, what will happen to them? At least, with this scheme, they will get an assured income of Rs. 400/- per month. The DMK Government is giving Rs. 200/-, the Central Government is also giving Rs. 200/-, but Tamil Nadu is giving Rs. 400/-. Anybody who is 65 or above and who is below poverty line, he or she gets an assured income of Rs. 400/- per month. That is the situation, now, in Tamil Nadu. The migration from Tamil Nadu has always been very heavy to the neighbouring States and foreign countries. But, now, it has stopped. People are coming back to their own places. They want to have their own habitation in their own village. They need not go anywhere else or getting the daily wages. So, this is the situation prevailing, now, in Tamil Nadu.

At the same time, on 18th April, a young man who was brought up in a very civilized manner, in a very disciplined manner, went to the villages of Jhansi and met the *dalit* families. He asked, "Why are you suffering? Why is there poverty? Why are you not able to get food? We have got the Rural Employment Guarantee Scheme, and this particular district is covered under the Scheme. Therefore, you can get the benefit of the Scheme. If you are ready to work, you will get a minimum wage of Rs. 100 per day in Uttar Pradesh. You can get it. So, why are you not getting it? This is the question which the young man asked the people. What

was the result of that? All the people of that area went behind him. That young man went to the Divisional Commissioner and asked him why he did not implement the scheme. What was the result? Just like Pandit Jawahar Lai Nehru was beaten by the police, four fellows tried to stop the young man who is now called Yuvraj. He is really a Yuvraj. He is going to be a Raja in future. He brought the matter to the notice of the common man. What did that common man say to the Press? He said, "Sir, for the first time, we entered into the Divisional Commissioner's Office. In my entire life, this is the first time when I could go inside the Divisional Commissioner's Office. This is the first time that I could say that I have got a security of job by getting Rs. 100 per day. That is why, I am demanding this from the rulers. I have got this as a right." This is the Press Report. Why are they afraid of it? Why are they saying that you go and look at the price rise? This is the work of Mr. P. Chidambaram. But Yuvraj has taken up the work of going deep into the villages and finding out the programmes that have not been implemented. If he wants, he can become a Minister tomorrow. He can even take charge of the Rural Development Ministry. Already Shri Raghuvansh Prasad Singhji is doing a wonderful job in that Ministry. He can visit that office and find out why they have not been implemented. He has not done it. He has made it as *Siddhartha,* a Budha, he went to the villages and saw to it that the poor people had to be carried forward. As a leader, he has done it. But how do other people, who claim that they are saviours of everybody, think? Shri Rajiv Gandhi's son, Rahul Gandhi, has done it as a Member of Parliament. He did it. He has shown to the poor people that here the programme is not being implemented properly. This is the programme where we have not put any restriction. The funds are available on demand. If you demand more money, we are ready to give it. That was the proposition. That was the law. When there is a demand for that, people are not being allowed to enjoy the fruit of the Scheme. The money which is to be spent on the poor people, does not reach them. That is the situation.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please conclude now. *(Interruptions)* Please conclude.

DR. E.M. SUDARSANANATCHIAPPAN: Sir, I am concluding. My request is that the Central Road Fund Act should be amended so that certain amount should be apportioned for the development of roads in rural areas. I also request that the three-tier system of governance at the Panchayat level, that is, at the district level, at the intermediate level and also at the village level, should be implemented. There was previously a programme. Under that programme, we used to give 25 per cent to the district level. That was the Sampoorna Grameen Rozgar Yojana. Under that, 75 per cent is given by the Government of India and 25 per cent is given by the State Governments. Under that Scheme, the District Panchayats used to get 20 per cent, and the intermediate level Panchayat used to get 30 per cent and the village Panchayat used to get 50 per cent. Foodgrains were given by the FCI through the Central Government. This Scheme has to be further spread throughout the nation. Just like other programmes, like the Rural Employment Guarantee Scheme, this should also be implemented so that all the three tiers have a role to play. They are elected by the people and they have to come forward.

Finally, I want to stress on one point. The Rural Employment Guarantee Scheme is a very, very important Scheme. There is a categorisation of schemes by which the people can get benefited. Even the Dalits, the Scheduled Tribes, people who are to be benefited by the Indira Awas Yojana Schemes, and also the people who are to be rehabilitated, are entitled to get the fund or labour for their own lands to be developed. That is what the Scheme is all about. Many of the States have implemented it. The Tamil Nadu Government has done in all

other fields except this one. Therefore, I request that this scheme, which is meant for *dalits,* should be implemented throughout India and that money should reach the ordinary people to develop their lands, so that, they could have good agricultural prospects, they could get good harvest by developing their own lands through the funds of the Rural Employment Guarantee Scheme. Thank you, Sir.

श्री अमर सिंह (उत्तर प्रदेश): सर, एक मिनट। अभी-अभी माननीय सदस्य ने आने वाले हिंदुस्तान के मुस्तकबिल और राजा की घोषणा की है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं हैं। यह उनका अधिकार हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि रघुवंश प्रसाद सिंह जी ग्रामीण विकास मंत्री हैं और आज इस चर्चा का विषय यह नहीं हैं कि आने वाले हिंदुस्तान का मुस्तकबिल और राजा कौन होगा, बल्कि चर्चा का विषय यह हैं कि आम आदमी ....(**व्यवधान**)....

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No, no, Amar Singhji, when your turn comes, you can speak what you want to, not now.

SHRI BALBIR PUNJ (Orissa): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for having provided me with an opportunity to speak on a very important subject, that is, the rural development. Sir, when we talk of rural development, virtually, we talk of about 70 per cent of India.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI UDAY PRATAP SINGH) in the Chair],

Sir, in terms of human resources, rural development means about 70 per cent of India. Maybe, in economic terms, the rural India contributes only about 17-20 per cent of the GDP, but, in terms of number of people who are employed, the number of people who reside in the rural India accounts for almost 70 per cent. Sir, we have been a free country for more than 60 years. If you go to the villages, you don't find any qualitative change in the life of the villagers or of the villages. I think one of the reasons is that we as a political class have never taken rural development as something very serious. There has been very superficial attention to rural India only in terms of votes. People have seen rural India mostly as a vote bank. I thought since it is a very important subject, the level of discussion in the House would be of a very high order. 1 would like to compliment Shrimati Brinda Karat that though I don't agree with her, she did initiate the discussion at a certain level. But the subsequent speaker, Mr. Natchiappan, reduced the entire discussion as to the salvation of the country depends on one family and one individual. This is totally unacceptable in a democracy. ...*(Interruptions)...*

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL (Gujarat): How does it ...*(Interruptions)...*

श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश): आप अपना बोलिए। ....(**व्यवधान**)....

SHRI BALBIR PUNJ: I will definitely comment on what he said. ...*(Interruptions)...*

DR. K. KESHAVA RAO (Andhra Pradesh): He started with the Prime Minister, but he did not reduce the ...*(Interruptions)...*

SHRI BALBIR PUNJ: Sir, I am not yielding and I must say that I condemn this thing with the entire emphasis at my command that somebody should be referred to as. *Yuvraj* in a democratic set up. It is a shameful thing ...*(Interruptions)...*

उपसभाध्यक्ष (श्री उदय प्रताप सिंह): एक मिनट....बैठिए....बैठिए।....(**व्यवधान**)....

SHRIMATI VIPLOVE THAK.UR: How can you say that? ...*(Interruptions)...*

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL: You can use the word, "Maharaja"; we don't mind. ...*(Interruptions)...* He is the Member of other House. ...*(Interruptions)...*

उपसभाध्यक्ष (श्री उदय प्रताप सिंह)**:** एक मिनट वृंदा जी बोलेंगी। ....(**व्यवधान**)....एक मिनट सुनिए।

श्रीमती वृंदा कारत: सर,मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूं कि हम पूरे संसार में सबसे बड़े लोकतंत्र माने जाते हैं। अभी नेपाल में चुनाव हुए, उन्होंने राजा, महाराजा, युवराज, सब कुछ को यह समझकर कि ये सामंतशाही तौर-तरीके हैं, उनको समाप्त करके एक जनवादी प्रणाली को चुना हैं। हिन्दुस्तान पिछले साठ साल से जनवादी प्रणाली पर चल रहा हैं इसलिए हम अपने नेता की इज्जत जरूरत करते हैं, लेकिन इस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल एक जनवादी देश में करना कहां तक उचित हैं ? ....(**व्यवधान**)....

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN: He can't say this. ...*(Interruptions)...*

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, the NDA leaders...*(Interruptions)...* Sir, the BJP leaders are propageting that Advani is going to be the future Prime Minister. ...*(Interruptions)...* They are saying so. ...*(Interruptions)...*

उपसभाध्यक्ष (श्री उदय प्रताप सिंह)**:** एक मिनट सुनिए। ....(**व्यवधान**)....आप लोग सुनिए ....(**व्यवधान**)....

श्री विप्लव ठाकुर: अनपार्लियामेंटरी लेंगुएज एक्सेप्ट ....(**व्यवधान**)....

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: आप अभी राजस्थान में उसको राजमाता कहते हो। ....(**व्यवधान**)....क्या बात करते हो ? ....(**व्यवधान**)....महाराजा कहते हो। ....(**व्यवधान**)....अपनी पार्टी में सभी ....(**व्यवधान**)....आप लोग आज भी महाराजा कहते हो। ....(**व्यवधान**)....आज भी कहते हो।....(**व्यवधान**)....

उपसभाध्यक्ष (श्री उदय प्रताप सिंह)**:** मैं हाउस से अपील करता हूं कि बहस इस बात पर हो रही हैं कि हिन्दुस्तान के गांवों के विकास के संबंध में किसकी क्या योजना है और क्या किसका विचार हैं....(**व्यवधान**).... वे अपनी पार्टी में किसी को कह रहे हैं, वे देश के युवराज तो नहीं कह रहे। अगर वे अपनी पार्टी कह रहे हैं तो कहने दीजिए, आप अपनी बात रखिए। अगर देश के लिए कह रहे होते तो ....(**व्यवधान**)....

SHRI BALBIR PUNJ: Mr. Vice-Chairman, Sir, I have a submission to make. If there is a *Yuvraj,* there has to be a *Rajmata,* there has to be a *Maharani* and there has to be a *Maharaja* ...*(Interruptions)...* This is totally unacceptable. ...*(Interruptions)...*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: आपके यहां महाराजा हैं? ....(**व्यवधान**).... राजमाता किसको कहते हैं, बताइए। ....(**व्यवधान**)....

SHRI BALBIR PUNJ: Mr. Vice-Chairman, Sir, as per your instruction... *(Interruptions)..*

SHRI V. NARAYANASAMY: Speak on the subject. ...*(Interruptions)...*

`**श्री प्रवीण राष्ट्रपाल**: महारानी को ....(**व्यवधान**)....

उपसभाध्यक्ष (श्री उदय प्रताप सिंह)**:** आपका वक्त आए तो आप बता दीजिए। ....(**व्यवधान**)....बहस को चलने दीजिए, जब आपका मौका आए तो आप बता दीजिए। तब आप अपनी आपत्ति दर्ज कर दीजिए। ....(**व्यवधान**)....

श्री रघुनंदन शर्मा(मध्य प्रदेश)**:** वे सामंतशाही और परिवारवाद का समर्थन कर रहे हैं और लोकतंत्र की निंदा कर रहे हैं तो उन्हें करने दीजिए। ....(**व्यवधान**)....

SHRI BALBIR PUNJ: Sir, as per your instruction, I will restrict this *'Yuvraj'* issue and move further ...*(Interruptions)...* Sir, do we remove rural poverty by marching into a Divisional Commissioner's Office? Is this the recipe? Is this the way to end rural poverty? If that were so, it is so easy; each one of us can march into a Commissioner's Office, Divisional Commissioner's Office, even the Chief Minister's Office. All such steps trivialise the whole issue and ...*(Interruptions)...*

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, if you permit me, there is a point of information.

SHRl BALBIR PUNJ: Sir, I am not yielding. ...*(Interruptions)*... Mr. Narayariasamy, I am not yielding. ...*(Interruptions)*...

SHRl V. NARAYANASAMY: Sir, I would like to seek one information from the hon. Member. I want to know whether any Member of Parliament is prohibited from going to a Regional Divisional Commissioner's Office or to a Collector's Office to go and give a representation. In a democratic country, a Member of Parliament can go, even an ordinary person can go and give a petition for looking into the grievances of the people. What is he talking about? ...*(Interruptions)*...

SHRI BALBIR PUNJ: Sir, I totally concede Mr. Narayanasamy's point that each one of us can march. But can we treat it as something very historical as it was recorded in the house? Is it a historical development that a Member of Parliament. ...*(Interruptions)*... This is exactly what I said that anybody can do it. But they started this step only to trivialise it. ...*(Interruptions)*...

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL: If it is not historical, why are you talking about it? ... *(Interruptions)*...

SHRI BALBIR PUNJ: It is because it has been mentioned by the hon. Member of Parliament who preceded me. ...*(Interruptions)*...

DR. E.M. SUDARSANANATCHIAPPAN: If you accept it, accept it. Otherwise, do'nt accept it. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAMA CHANDRA KHUNTIA (Orissa): If they cannot think about NREG Scheme, what they will talk about NREG Scheme? ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI UDAY PRATAP SINGH): Mr. Punj, is it your maiden speech?

SHRI BALBIR PUNJ: No; Sir. It is my second term. It is my maiden speech in the second term.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI UDAY PRATAP SINGH): Had it been your maiden speech, 1 would have asked them to contain. ...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA (Jharkhand): Sir, it is a maiden speech of his second term. *(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री उदय प्रताप सिंह)**:** आप इतने विद्वान हैं कि आप ऐसे ही बोल सकते हैं । आप इन विवादास्पद बातों से हटकर बोलिए । ....(**व्यवधान**)....

श्री बलवीर पुंज: मेरे से पूर्व वक्ता ने इतनी बार इस बारे में कहा कि कितना ऐतिहासिक कदम था जब राहुल गांधी गए और इस तरह से गरीबों की समस्याएं दूर हो गई । मैं तो केवल इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि इस तरह के कदमों से समस्याएं दूर नहीं होती । यह बेसिकली इतनी जो गंभीर समस्या हैं कि ग्रामीण विकास नहीं हो रहा हैं, गांवों में गरीबी बढ़ रही हैं, उसका ट्रिविएलाइजेशन होता हैं, उस गंभीर समस्या को बड़े हल्के तरीके से लिया जाता हैं । इसको एतिहासिक बताना और करने वाले को युवराज बताना, यह प्रजातंत्र का मखौल हैं, मजाक हैं । ....(**व्यवधान**)....मैं केवल इतना निवेदन कर रहा था । If one were to go through the speeches of the Treasury Benches, he has given the impression as if each of the Prime Ministers — I shall not take names, but they all belong to one particular family — has done the utmost for the removal of rural poverty and they have

done their best to develop rural India. If that were so, Sir, in the last 60 years, we should have seen some change in rural India. But we find that the situation both in terms of infrastructure and employement, has only worsened. As they say in Hindi ज्यों-ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता गया । जितनी एक के बाद एक स्कीम देखी । ....(**व्यवधान**)....

उपसभाध्यक्ष (श्री उदय प्रताप सिंह): जब आपका समय आए, तब बोलिएगा । ....(**व्यवधान**)....Please, do not disturb. आप खड़े होंगे तो ये डिस्टर्व होंगे । ....(**व्यवधान**)....

SHRI BALBIR PUNJ: Mr. Chairman Sir, my friends from the other side are only contradicting their leader, their *yuvraj.* Their *yuvraj* has also made the same statement as I have, that there has been no change in the villages of, at least, Uttar Pradesh. And if that is true of Uttar Pradesh, it is also true of the rest of the country. So, what I am saying is, I am only repeating what your *yuvraj* and your leader has said, that there has been no change in the situation at all in the villages of Uttar Pradesh. As I have said earlier, Uttar Pradesh is no different from Bihar, Bengal or Gujarat. Most of rural India continues to be the way it was.

Sir, the problem is, when we talk of economy, we only think in terms of the Sensex , we think in terms of the stock market and we think in terms of the corporates. Sir, all the listed companies of the Sensex account for only one per cent of the GDP and the entire stock market, the 500 prominent companies which account for almost 90 per cent of the stock market, contribute less than four per cent to the GDP. Our entire focus is only on that four per cent and we forget about the rest of the 96 per cent of the economy.

Sir, I have got with me a report from the National Commission for Enterprises in the Unorganised Sector. The report pertains to the period 2004-05. It says that 92 per cent of the 457 million people were employed as agricultural labourers, farmers or petty vendors. That means, about 92 per cent of the workforce in this country is (a) in the unorganised sector, and (b) we are not concerned about them. Even when my friends from the Left spoke, their focus was, by and large, on the organized labour and 92 per cent of the 457 million, that is, more then 40 crore people who are employed, do not figure in our scheme of things. Of course, there are minimum wages but we all know to what extent they are implemented. We have the labour laws but since the labour force is unorganised, the labour laws are never implemented. Sir, I was talking about the share of the attention which this stock market gets. One development which flows out of the stock market and which affects the rural poor is happening.

Mr. Vice-Chairman, Sir, in the entire country, huge islands of "foreign lands" are appearing. There are islands of "foreign lands" and, this is a very serious matter. The corporates are buying huge tracts of land. Shrimati Karat referred to about 8 million hectares of wasteland disappearing. It did not disappear. It has been appropriated mostly by the corporates. There are huge tracts of lands that have been taken over by mysterious buyers and it goes on all along Haryana, Rajasthan and Gujarat border. Sir, we all know that stocks control these corporates, and, by and large, the stocks are held by financial institutions, foreign financial institutions.

Sir, see the linkage, you have the corporates taking over huge tracts of land; corporates are controlled by stocks; stocks, in turn, are controlled by the FIIs, and, with the result you have land available within the country, which is not under foreign domination but is surely under foreign ownership.

The land may be in India but we cannot set our foot on it, and, as a result, the prices of real estate have gone up. And, when the prices of real estates go up, that means, prices within

rural India also go up. What are the implications of it for rural India? Sir, the implication is that the corporates come and offer a very fancy price for a piece of land. When the poor farmer who is struggling, who cannot make his both ends meet, who cannot meet his family obligations, sees the fancy price and the packet of money, he cannot resist the temptation, and, therefore, sells the land. Land is not just a livelihood in this country; it is a culture, it is a tradition and it is a way of life. As a result, he gets divorced from all that which he has carried on for generations, and, there comes a situation where a person who had probably five to ten acres of land — he may have a crore or so in his hand — becomes landless and becomes jobless. The man has never seen such huge money. He does not know what to do with it. In two, three, four, five years, the money is spent, tan ^ ^t ^trat $ and he isagain pushed to poverty. I think, the Government must pay attention towards this acquisition of land by corporates, particularly, controlled by foreign funds.

Mr. Vice-Chairman, Sir, as far as UPA Government is concerned, the month of February, 2006 is very historic because it was the time when the National Rural Employment Guarantee Act came into being and about 200 of India's most backward District-- were covered under it. Last year, it was extended to cover another 130 Districts, and, now, as per the new provisions, from April 1,2008, all the the 600 Districts and odd are covered under this. This has been the plank of the UPA to attack poverty within the country.

Sir, I would not deny the marginal utility of this programme in fighting poverty. You know that it is not the first time that you have such a scheme. You had the Food for Work Programme earlier. And, even before that, there have been schemes, which have been aimed at rural poor, providing them with employment. The schemes have failed on two counts basically.

One, as it was mentioned, there is corruption, the pipeline, which carries water from the overhead tank to the bottom, leaks so many times and at so many places that sometimes people say that only 10-15 per cent reaches them. And the situation is no better today.

Two, the coverage area, the implementation. I was told that only 34 days' employment was possibe against the target of 100 days. Figures may vary. I am not looking at the figures.

But there are two problems. One is leakage within the pipeline. Second is the claim that the scheme is being implemented more honestly than the previous schemes. Nobody will buy it. People know by experience that there are huge leakages.

The assets, which get created because of the schemes, are not long-lasting. You cannot remove poverty honestly by asking people to dig a pit today and fill it up tomorrow.

I will enumerate the basic problems of the villages. Sir, our people are hard-working. They are enterprising. It is our failure that we have not been able to give them the infrastructure through which they can help themselves. You go to any village in any part of the country and you will see that, by and large, they get power supply for 2-3 hours in a day. Maybe four hours.

The situation is slightly different in Gujarat. I do not mention it because it is a BJP-ruleid State. It is an example by itself. You have the entire rural area there connected by a three-phase connection and almost 24-hour power supply is there. This was one of the reasons why inspite of the stiff opposition from some of our friends, Narendra Modi won a landslide victory again.

Sir, you go to the rest of the country. The rural areas have power supply only for 2-5 hours. Now if there is no power, there cannot be any industry; there cannot be any enterprise; and no doctor will go and work in a village in which you get only 2-3 hours of power. In fact, there are villages in Bihar, in so many other parts of the country, where the power will come either once in a week or once in ten days. What sort of education you can impart in such a place? What sort of medical facility you can provide there? What sort of industry you can set up in a place which has no power? So, no power means no development and with the result the chances of economic resurgence, economic development in a power-starved area are nil in spite of all the planning or schemes you might have.

My request to the hon. Minister and to the Government will be to give power to the rural areas and you empower them. It is not enough to give them fish, teach them how to catch a fish. It is not enough to give them work, empower them so that they can make use of their hardworking faculties and also their entrepreneurial skills.

Sir, the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana is connecting villages to the main arteries, to the main roads. It is key to the rural development. I will request the hon. Minister to lay special emphasis on it, make the funds available, and monitor the schemes, so that all the six lakh-odd villages we have in the country get connected to the main roads. When you connect a village to the main road, you virtually help the villages to completely transform their lives, because better connectivity means they can take their agricultural output to the nearest market without a problem. They can buy inputs. They can go for education and medical facilities and they become easily accessible. So, the road connectivity, apart from power, is the key to rural development.

Three, thanks to the NDA Government and the efforts made by Atal Bihari Vajpayee Government, the telephone connectivity has improved a lot and even that will act like a catalytic agent in the improvement of life in the rural areas. So, you give these three things. First is power. Give specialised package for power to the rural areas. Second is road connectivity and thrid is telephonic connectivity. With these things, I am sure the people can help themselves.

Sir, I want to speak something about rural poverty. A sample of about 19,000 rural households in the 62nd round of NSS carried out in 2005-06 had made 2-3 very interesting observations. One was that in the rural population, they are spending less than Rs. 12 per head per day. Less than Rs. 12 per head per day! Now, if in 2005-06, it was less than Rs. 12, I don't think the figure is very different even today. 12 *tm,* 3 w ft 'fr^n t? Nobody can live on it had nobody lives. People sleep on empty stomach. Sir, when you talk of people living below poverty line, there is a marker of 2100 calories in urban areas and 2400 calories in rural areas and it is linked to the prices prevailing in 1973-74. So, when you want to calculate in modern terms, you add inflation. But, this is a misnomer. This is quite a misleading statement. It misleads people because by providing for inflation, you cannot upgrade that figure of 1973-74 to today's. So, my request to the hon. Minister would be to update the definition of'poverty' and people who are living below poverty line. One of the major problems of the rural poor is that 60 to 70 per cent of their income is spent only on food. The income is so less that about 70 per cent of the income is spent only on food. Then, what you are left with is very little.

उपसभाध्यक्ष(श्री उदय प्रताप सिंह)**:** माननीय सदस्य, आपकी पार्टी को 43 मिनट दिए गए है, जिसमें आप 40 मिनट से ज्यादा बोल चुके हैं। अगर आप अपनी पार्टी के अन्य सदस्यों को समय न छोड़ना चाहें, तो आप और बोल सकते हैं।

SHRI BALBIR PUNJ: Sir, I will conclude in a minute. I didn't realise that. So, if you have a situation where a person is forced to spend more than 60 to 70 per cent of his income on food alone, he has no option because his income is very less. It leaves very little money with him to either spend on education or on clothes or on his medical treatment. So, we need to change the entire scenario.

Sir, in the concluding remarks, I would like to say that a discussion on poverty, a discussion on rural India, should be taken seriously. And we should not trivialise it by invoking the name of leader X or leader Y and all the good work which they have done. If somebody had done really good work, there would have been no rural poverty. *(Interruptions)* Thank you very much, Sir.

श्री शरद यादव (बिहार): उपसभाध्यक्ष जी, ग्रामीण विकास पर जो बहस हुई, इस बहस में श्रीमती वृंदा कारत जी ने इसके हर हिस्से को खंड-खंड करके बताने का काम किया । उनके बाद मैंने कांग्रेस पाटी के मित्रों को भी सुना, श्री बलबीर पुंज जी ने भी बताया कि ग्रामीण विकास के लिए और जो वंचित समाज हैं, उनके लिए किस-किस तरह से, कैसे काम हों । 60 बरस की आजादी में ये सब लोग निरन्तर अपने भाषण में यहां यह कह रहे हैं कि उनकी हालत बहुत खराब हैं और उसे कैसे सुधारा जाए, इसके लिए भी उन्होंने कई सुझाव दिए ।

उपसभाध्यक्ष महोदय,मैं कहना चाहता हूं कि आज जिस मुकाम पर हम खड़े हैं, यह बहस 60 बरस से हो रही है । लगभग 34 बरस से तो मैं स्वयं भी इस सदन में इन सवालों को उठाता रहा हू, इन पर अपने दर्द और तकलीफ को रखता रहा हूं । यहां पर बहुत से नामवर सदस्य रहे हैं, जिन्होंने अपने-अपने तरीके से यहां पर बोलने का काम किया हैं। लेकिन जो कुछ भी बोला गया, वह कभी —भी आचरण में नहीं उतरा, जमीन पर नहीं उतरा । यह सभा बोली की हैं और यह दुनिया भी बोली की हैं, गोली की नहीं हैं । लेकिन देश भर की तरफ से यहां की बोली में जो भी बोला जा रहा हैं, उसका इतना कम असर हैं कि गरीब की गरीबी बढ़ती जाती हैं, उसकी लाचारी, बेबसी और गुर्बत भी बढ़ती जा रही हैं । यहां पर भी भाषण निरन्तर चलता रहता हैं । कभी-कभी तो मन में यह आता हैं कि या तो यह धरती फटे या फिर कोई इंकलाब हो । अभी बलबीर पुंज जी कह रहे थे कि बिजली दो और इम्पावर करो ।

महोदय,मैं कहना चाहता हूं कि जो भी लोग ग्रामीण इलाकों से आए हुए हैं, उन्होंने मां-बाप, भाई-बहन को देखा होगा या उनसे सुना होगा । मैं तो अपनी मेहतारी को जानता हूं, जिसके जीवन भर में यदि कोई कष्ट था, कोई तकलीफ थी, तो वह मौसम को लेकर थी । सुबह से शाम तक वह मौसम के बारे में चिन्तित रहती थी, खास तौर पर उसकी चिन्ता पानी को लेकर थी ।

मित्रों, इस देश में आप जहां पानी ले गए हो, वहां चाहे हमारी सरकार हो, चाहे इनकी सरकार हो या फिर पुरानी सरकार हो, उसके चलते कोई सुधार नहीं हुआ हैं, हालांकि भाषण बहुत हुए, कार्यक्रम बहुत बने, नीतियां बहुत बनी, प्रोग्राम बहुत बने । अभी एक गारंटी स्कीम REGA बनी हैं, लेकिन यह भी रेंग-रेंग कर चल रही हैं । मंत्री महोदय इस बात को याद रखें कि हम लोगों की जमात में हमारे आपसी रिश्ते बड़े नहीं होते, खून के रिश्ते बड़े नहीं होते, सिद्ध्तं और नीति के रिश्ते बड़े होते हैं । मैं और वह एक ही स्कूल के लोग हैं और एक ही पार्टी में हमने बरसों काम किया हैं, लेकिन महोदय, सबसे बड़ी बात यह हैं कि हमारे बोलने में और हमारी बात के जमीन पर जाने में, क्रियान्वित होने में, कितना भारी अंतर हैं, इसे बयान नहीं किया जा सकता हैं ।

हमारे मित्रों ने, वृंदा कारत जी ने, बलबीर पुंज जी ने और वह जो कांग्रेस पार्टी के मित्र हैं, उन्होंने इसे बयान किया। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि वह जिस तहज़ीब, संस्कृति और तबद्दुम की बात करते हैं, अभी यहां महात्मा बुद्व का नाम भी लिया गया । मित्रों, उन्होंने अपनी धरती को कितना कुछ दिया । दुनिया में कोई भी चमड़ी से बाहर नहीं गया या आपके 33 करोड़ देवी-देवताओं में से कोई नहीं छलका, लेकिन वे बुद्व चमड़ी से बाहर चले गए । वह बड़े आदमी थे । उन्होंने कहा, "धम्मम् शरणं गच्छामि, संघम् शरणं गच्छामि, बुद्वम् शरणं गच्छामि" । उन्होंने कहा कि पहले जनता की शरणं में जाओ, उसके बाद संगठन की शरण में जाओ और तीसरे नम्बर पर व्यक्ति की शरण में जाना । इस देश में कितने कीर्तन हो रहे हैं, हर रास्ते और हर चौराहे पर इतने महापुरूषें के बुत लग गए हैं, उनमें महात्मा गांधी और अन्य सबके बुत लगे हैं, लेकिन जितने बुल लग रहे हैं, उतना ही इस देश में कंगाली और गरीबी बढ़ती जा रही हैं । इंसान की लाचारी बढ़ती जा

3.00 RM.

रही हैं। दो दुनिया बन गई हैं। सम्पन्न् दुनिया बननी चाहिए,मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकि सम्पन्न् दुनिया हदयहीन हो जाए, उसकी संवदनाएं बिल्कुल डेथ कर जाएं, मृत हो जाएं, वह देश नहीं चलता। आजादी के दौर में हमारे जितने नेता थे, आजादी के बाद भी 20-30 सालों तक उनका, खास कर के, मन और उनकी नीयत तो साफ थे। उनको डर तो था, तकलीफ तो थी, लेकिन आज का जो सम्मन्न समाज हैं—मेरे मित्र जो कह रहे थे, एक कांग्रेस पार्टी के एक पदाधिकारी का ज़िक्र कर रहे थे। कैसा पाखंडी और कैसा दोहरा हमारा चरित्र हैं कि एक जगह हम गरीब और लाचार आदमी की जिन्दगी देखने जाते हैं, इसलिए देखने जाते हैं कि हमारा दिल तैयार हो जाए, मतलब कि हमको बोध हो जाए, सम्बोध हो जाए, बोध हो जाए, तो उसको सम्बोध कराएं, फिर सम लक्ष्य के लिए लग लाएं, इसलिए हम जाते हैं। लेकिन हमारा देश अजीब हैं। बुंदेलखंड के लोग सब तरह से, पानी, धूप, आदि हर तरफ की चीज़ों से बेजार हैं, हम उनके बीच भी जाते हैं और दूसरे दिन हम आई.पी.एल. में भी शिरकत करते हैं। यकीन नहीं होता। एक आदमी की बात नहीं हैं। यह अकेले एक आदमी की बात नहीं हैं। ....(**व्यवधान**).... आप उनको क्यों बता रहे हैं ? पूरा देश ऐसा हैं। उनको क्या बताएंगे, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं उनसे कह रहा हूं कि हृदय को ठीक रखें। प्रेम और ममता होनी चाहिए। मेरी पक्की राय हैं कि समता के बगैर सम्पन्नता- सम्पन्ता पहले आएगी। समता और सम्पन्नता दोनों एक साथ जुड़ी हुई हैं। मुल्क सम्पन्न होगा तो समता आएगी। मै उसमें नहीं कह रहा हूं, जो मेरे मित्र हैं, जिनके ऊपर लोग इशारा कर रहे हैं, मैं उनकी भी आलोचना नहीं कर रहा हूं मैं तो उनसे कह रहा हूं कि आपका हृदय, हमारा भी हृदय--- महात्मा जी कहते थे कि इस देश का ....(**व्यवधान**)....

श्री राजीव शुक्ल (महाराष्ट्र): बुंदेलखंड जाकर क्रिकेट मैच देखने जाने में क्या हर्ज हैं? ....(**व्यवधान**)....

श्री शरद यादव: आप क्यों इतना परेशान हैं ? ....(**व्यवधान**)....आप इतनी जल्दी क्यों परेशान हो गए ? ....(**व्यवधान**).... क्या आपको नम्बर बढ़ाना हैं ....(**व्यवधान**)....

श्री राजीव शुक्ल: मुझे नम्बर नहीं बढ़ाना हैं ....(**व्यवधान**)....

श्री शरद यादव: आप क्या बात कर रहे हैं ....(**व्यवधान**)....मैं वह नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ....(**व्यवधान**)....

श्री राजीव शुक्ल(महाराष्ट्र): जो उदाहरण आपने दिया ....(**व्यवधान**)....

श्री रूद्रनाराण पाणि: उससे क्या होता हैं ? ....(**व्यवधान**)....कभी एन.डी.ए. कभी यू.पी.ए. ....(**व्यवधान**)....

श्री राजीव शुक्ल: आपने जो उदाहरण दिया ....(**व्यवधान**)....जो इशारे किए गए,उसकी वजह से हम कह रहे हैं ....(**व्यवधान**)....बुंदेलखंड में क्रिकेट मैच देखने ....(**व्यवधान**)....

श्री रवि शंकर प्रसाद (बिहार): राजीव जी, क्या संसद में व्यंग्य का समय खत्म हो गया ? ....(**व्यवधान**)....व्यंग्य का समय खत्म हो गया क्या ? ....(**व्यवधान**)....क्या उनको व्यंग्य करने का अधिकार भी नहीं हैं, ...(**व्यवधान**)....क्या मतलब हैं, इसका ? ....(**व्यवधान**)....इसका क्या मतलब हैं? ....(**व्यवधान**)....

श्री अमर सिंह: घर में तो एक हैं, संसद में अलग-अलग ? ....(**व्यवधान**)....

श्री राजीव शुक्ल: उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ....(**व्यवधान**)....

SHRIMATI JAYABACHCHAN(^R^t): Good performance ...*(Interruptions)...* Good performance ...*(Interruptions)...*

श्री राजीव शुक्ल : बुंदेलखंड के ....(**व्यवधान**)....उससे गरीबों के प्रति आस्था नहीं खत्म हो जाती।

श्री शरद यादव: राजीव शुक्ल जी हमारे मित्र हैं। यदि उनको यह लगा हैं कि मैंने ठीक बात नहीं कही हैं तो मैं फिर दोहराता हूं, लेकिन वह बात नहीं दोहराउंगा।

मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में हमारे एक बड़े पुरखा पैदा हुए, जिनका नाम महात्मा गांधी था। हम महात्मा गांधी जी का नाम लेते हैं और हर चौराहे पर उनका बुत लगाते हैं। महात्मा गांधी कोई बुत नहीं थे, एक विचार थे। मैं अकेले अपनी बात नहीं कह रहा हूं। उनके लिए नहीं कह रहा हूं। उनके बारे में मैं अपी बात वापस कर लेता हूं, चूंकि उनको

नम्बर बढ़ाने के लिए बोलना पड़ेगा। उनका नाम लेने के साथ बहुत से लोग खड़े होंगे – आप तो मेरे मित्र हैं, इसलिए खड़े हो गए, दूसरा भी कोई खड़ा हो सकता था। मेरा अपराध यह हो गया कि मैंने उनका उदाहरण दिया कि देश भर में सारा पाखंड इसी तरह चला हुआ हैं। इस देश के सदन में हम जितने लोग बैठे हैं, हमारे जीवन पाखंड से भरे हुए हैं। महात्मा जी का जीवन था, जिनके लिए हम रोज कहते हैं कि वह हमारे राष्ट्रपिता थे। क्या आप उनके जीवन की कोई एक घटना बता सकते हैं कि उनके आचरण में इस तरह का कोई दोहरा चरित्र हो ? कहीं बात सकते हैं आप ? इस सदन में मधु दंडवते जी रहे हैं। कभी आप बता सकते हैं कि उनके चरित्र में दोहरापन था ? यहां डा. लोहिया भी रहे हैं। क्या आप यह बता सकते हैं कि उनके जीवन में इस तरह की कोई चीज थी? वह भी क्रिकेट देखने जाते थे, लेकिन चुपचाप जाते थे, घोषणा कर के नहीं जाते थे। ....(**व्यवधान**)....मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं किसी की आलोचना करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। ....(**व्यवधान**).... ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? मेरा निवेदन यह हैं कि मेरे अन्दर कमी यह हैं कि यदि आप मुझे टोकेंगे, तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, डिरेल हो जाऊंगा। इसलिए आपसे मेरी विनती हैं, क्योंकि मुझे कम समय मिला हैं। यदि आप सुन लें तो ठीक रहेगा। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। पूरे देश का जो चरित्र हैं, वह पांखड से भरा हुआ हैं। इसीलिए मैंने कहा कि हमने दो दुनिया बना ली। दो दुनिया बनाने और सम्पन्नता आने से मुझे कोई ऐतराज़ नहीं हैं। वह सम्पन्नता जो हैं, वह पूरे समूचे – मैं अकेले इंसान की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें जंगल हैं, पेड़-पौधे हैं, जानवर हैं, इंसान को ह्रदय हैं, जुबान हैं, होश हैं और बुद्धि हैं, लेकिन इसका मतलब बेजुबान लोगों की तबाही और बर्बादी नहीं हो सकतीं।

श्री शरद यादवः इसलिए जैसा उनका ह्रदय था, वैसा सबके पास होना चाहिए। यही मैंने निवेदन किया कि इस सदन में कुछ लोग 60 बरस से बोल रहे हैं। इस सदन में बहुत से ऐसे शानदार लोग थे, जिनके चरित्र दोहरे नहीं थे, जिनके चरित्र एक थे।

महोदय, गरीबी पर बात करते हुए श्री बलबीर पुंज जी ने जो कहा, मैं उनकी बात मैं संशोधन करना चाहता हूं। आजादी के बाद जहां भी आप पानी ले गए, वहां से गरीबी उठी हैं, गरीबी मिटी हैं। चाहे अंग्रेजों का जमाना रहा हो या आजाद हिन्दुस्तान की सरकार का जमाना रहा हो, किसी भी सरकार ने जहां खेत से पानी जोड़ा हैं, वहां सम्पन्नता बढ़ी हैं। मैं आज से दस दिन पहले गावं गया था। वहां पहले नहर नहीं थी, एक तवा नदी हैं, जो नर्मदा नदी में जाकर मिलती हैं। यहां जब तवा पर नहर बन गई, मेरे बचपन के जो मित्र थे धूरी, बिलोरी, में इन सबके घर गया तो देखा कि सबके घर बढ़िया बन गये थे। 200 रूपए रोज की मजदूरी हो गई। प्रताप सिंह कैरो था कांग्रेस पार्टी का, मैं अभिनन्दन करता हूं उस आदमी का, जब सब कारखाने लेकर गए, वो पानी लेकर आया, भाखड़ा नांगल। पंजाब ने खेत से पानी को पहले जोड़ा वहां स्कूल बाद में गया, सड़क बाद में गई, अस्पताल बाद में गया, लेकिन पहले पानी वहां गया, उसके बाद वह सड़क खींचकर ले गया, स्कूल खींचकर ले गया। याद रखना कि पंजाब के इंसानों के चेहरों पर पानी भी पानी जमीन में डालने से आया। यह जो रूरल डेवलपमेंट स्कीम हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में बहुत स्कीम्स चलीं। मैं कहना चाहता हूं कि हर सरकार ने रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत पैसा दिया हैं गरीब देश के होते हुए भी पैसा दिया गया, लेकिन वह पैसा गली-गली, गांव-गांव, ठिकाने पर लुटता हैं। चाहे यह गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की दिया जाने वाला अनाज हो, वह लुट जाता हैं। यह जो IRDA की स्कीम हैं, श्रीमती वृंदा कारत जी बहुत देर तक माथा मारती रहीं, उन्हें एक बात और कहनी चाहिए थी उसमें कि तब तक आप ठीक नहीं हो सकते हो, उनकी सब बातें सच था। यह ऐसी महिला हैं कि जब मैं मंत्री और जब लोग भूख से मर रहे थे तो इन्होंने ऐसा सुझाव दिया कि मैं भी हिल गया था। मैं मानता हूं कि उनका सुझाव बहुत अच्छा हैं, लेकिन इस देश में कहा जाता हैं कि घर चंगा तो कठौती में गंगा। हम सब तरफ से अगर ठीक से देखें तो हर आदमी अपने घर के लिए देखता हैं। हिन्दुस्तान का पूरा समाज खंड-खंड हैं, लेकिन उस खंड-खंड समाज में भी यदि कोई एक अच्छी चीज निकलती हैं तो यह परिवार हैं। हमारे यहां कहावत हैं मन चंगा तो कठोती में गंगा। महोदय, मन किसी रिक्शे वाले का ठीक नहीं रह सकता, किसी मिट्टी तोड़ने वोले का मन चंगा नहीं होगा, जिसका घर चंगा हैं, उसका मन चंगा होगा। यहां घर बनाते हैं गांव से लेकर शहर तक ऐसे लोग हैं। अगर पिछले 60 बरस का सारा रूरल डेवलपमेंट का पैसा अगर लग गया होता, तो आज कुछ और बात होती। रघुवंश प्रसाद जी, आप सच्चाई से लगे हैं, लेकिन यदि आपको यह स्कीम स्कसैस करनी हैं तो आप मुख्य मंत्रियों को बुलाइए, उनके अनुभव लीजिए, आप MPs को बुला लीजिए, आपने बुलाया हैं, उनको बुलाकर इसे घेरिए, यह जमीन पर कैसे जाए, यह देखिए। आपके अकेले के प्रयास से यह जमीन पर नहीं जाएगी। सारे देश में गरीबी की रेखा से नीचे 23,000 करोड़ रूपए का अनाज आप दे रहे हैं, यह हमारी सरकार ने भी दिया हैं, आप भी दे रहे हैं। श्री देवेगौड़ा से लेकर आज तक सब लोग दे रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी का पेट खाली हैं। विदेशों से हमने अपने यहां जोकरों को ऐसा बिठाकर रखा हैं कि मैं क्या बताऊं, वे कैलोरी लगा रहे हैं, वे

ऐसे पैरामीटर बना रहे हैं कि सब यूरोप से पढ़कर आ रहे हैं। कौन इनसे माथा मारे। हमने देश को कहां पहुंचा दिया हैं। अरे भाई, जिसको दो जून खाना न मिले, वह गरीब हैं। कौन सी चीज देख रहे हैं ? अनुभव की बात हैं कि जिसके पास खाना नहीं हैं, वह गरीब हैं। मैं कोई क्राइटीरिया नहीं बताता, गरीबी का क्राइटीरिया तो वहीं हैं। सम्पन्नता का कोई मापदंड है तो वह यही है कि उसको जो जून की रोटी ठीक से मिले, इस पैरामीटर को अपने देसी लिहाज से क्यों नहीं बनाना चाहिए। महात्मा जी ने 32 में लिखा था कि लखनऊ और दिल्ली में जो सरकारें आई हैं वे कहेंगी कि हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया,लेकिन उनकी बात मत सुनना। एक किलोमीटर चलना,गुजरात में बनिहार कहते हैं मजदूर को, तुम एक किलोमीटर चलोगे तो तुमको अंतिम आदमी, गरीब आदमी, बनिहारी आदमी मिल जाएगा, यदि उसकी हालत में बदलाव नहीं हुआ हैं तो दिल्ली की सरकार असत्य बोल रही हैं, उसको उसी दिन से उखाड़ने का काम करना। उसको उखाड़ने का काम करना। आज देख लो, गरीब कहां खड़ा हैं? इस समय श्री अर्जुन सेनगुप्त यहां हैं, कहते हैं कि 78 परसेंट आदमी 20 रूपए पर हैं और दूसरी तरफ सरकार कहती हैं कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 27 परसेंट हैं, वे कह रहे हैं कि 78 परसेंट हैं। तो ये दो जीभों से क्यों बोल रहे हैं, एक सरकार दो जीभों से क्यों बोल रही हैं दो जीभों से तो सांप बोलता हैं। इसलिए में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में जो रूरल डेवलपमेंट के कार्यक्रम हैं- चाहे इंदिरा आवास हो, चाहे कोई और स्कीम हो, जिसका वृंदा जी ने ज़िक्र किया, उन स्कीमों का यदि कबाड़ा हुआ हैं, बरबादी हुई हैं, तो उसका कारण यही हैं कि इस देश में जो तंत्र हैं, वह तंत्र सड़ गया हैं, वह इतना भ्रष्ट हैं कि वह सब खा जाता हैं, सब चर जाता हैं। मोटे-मोटे, मजबूत लोग गांवों में बैठे हैं, एक का मकान ऊंचा बनता हैं, मज़बूत बनता हैं और बाकी सबको वह सफाचट कर देता हैं, बरबाद कर देता हैं।

अभी हमारे कुछ मित्र वोट की बात कर रहे हैं थे, वोट तो कीमती चीज हैं। यहीं पर नेपाल हैं, दक्षिण एशिया में ऐसा कमाल कहीं नहीं हुआ कि राजशाही हार गई, सामंतशाही हार गई, परिवारबाद तबाह और बरबाद हो गया, बाज़ार ने घुटने टेक दिए। जो लोग हथियार लेकर लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने अच्छा फैसला किया कि उन्होंने बैलट पेपर पकड़ा। कुछ लोग कह रहे हैं कि बैलट पेपर पकड़ने के बाद भी उन पर शक कर रहे हैं। फिर आप आंध्र प्रदेश में नक्सलवादियों से बात क्यों कर रहे हो, आप कश्मीर में हथियार वाले लोगों से बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो कि जिन्होंने हथियार उठाए हैं, वे मुख्य धारा में आएं। मैं तो निराश था, लेकिन नेपाल में जो बदलाव आया हैं, वह गरीब लोगों की वजह से आया हैं, वे गरीब लोग ठीक चलें, यह मैं आशा करता हूं, कहीं वे हमारे रास्ते पर न चले जांए, वरना उनकी तबाही होगी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि वहां जो हुआ है, वहां जो चमक आई है, इतिहास ने जो करवट वहां बदली हैं, वह देखने लायक हैं। भारत में जो रहने वाले लोग है, जो सामंतवाद से प्रभावित हैं, तो हर तरह से राजा-रानी का नाम बड़ गौरव से लेते हैं, राजा साहब, रानी साहिबा, अब लोगों को चिंता हैं कि वहां के राजा का क्या होगा। मुझसे एक पत्रकार पूछ रहा था मैंने कहा कि वह एक आदमी हैं, क्यों माथा मार रहे हो कि उसका क्या भविष्य होगा, इसके बजाय हमसे यह पूछो कि नेपाल का क्या भविष्य होगा ? मैं निश्चित तौर पर आपसे कहना चाहता हूं कि रघुवंश बाबू, आपको यह मौका मिला हैं, यह जो रूरल इम्प्लॉयमेंट गांरटी स्कीम हैं, यह सबसे ज्यादा भ्रष्टचार की चपेट में जाएगी, जैसा पहले सारे विकास के काम भ्रष्टाचार की चपेट में चले गए। यदि विकास के काम ठीक होते, तो गांव सोने के होते और सड़कें चांदी की हो सकती थीं, क्योंकि इतना पैसा गांवों की तरफ गया हैं, लेकिन वह पैसा लुट गया है, वह पैसा लोगों ने लूट लिया। यह भारतीय समाज सड़ा हुआ हैं, इसमें कदम-कदम पर लूट हैं, कदम-कदम पर अन्याय हैं, कदम-कदम पर जुर्म है, हम कभी इस अन्याय को दूर का काम नहीं करते। यह जाति-व्यवस्था जो है, मैं कहता हूं कि आप mathematically लगा लीजिए, ऊंची जाति से लेकर नीची जाति तक जैसे-जैसे आप जाओगे, गरीबी वैसे-वैसे बढ़ती जाएगी, लेकिन इसके बारे में हम कुछ सोचने के लिए तैयार नहीं हैं। आज भारतीय समाज में जो विसंगति है, रोग हैं- बीमारी हैं, उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं, केवल वोट के बारे में सोचते हैं, वोट के बगैर देश और दुनिया नहीं चल सकती, लेकिन गरीब की कोई नहीं सुनता। हम लोग आज यहां नहीं बैठे होते, यदि यह बैलट पेपर उनके हाथ में नहीं होता। महात्मा गांधी और आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों ने यह बैलट पेपर उनके हाथ में दिया हैं। मेरा यकीन हैं कि यदि गरीब आदमी के लिए कोई रास्ता निकलेगा, यदि उसकी जिंदगी बनेगी और संवरेगी, तो यह बैलट पेपर के कारण ही संवरेगी। इस कार्य में इसका खूबसूरती से इस्तेमाल किया जा सकता हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं रघुवंश बाबू जी से कहता हूं कि यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगा, मैं देखकर आया हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस स्कीम में बहुत सुधार करने की जरूरत हैं, आप सबको बुलाइए, नहीं तो आप खुद जाइए, जाकर

अगर एक आदमी खड़ा हो जाता हैं, तो देश आज़ाद हो जाता हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी यह रोजगार गारंटी स्कीम सफल हो, इसके लिए मैं आपको शुभकामना देता हूं, लेकिन में आपसे फिर कहता हूं कि आज यह देश भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ हैं, इसको घेरने की जरूरत हैं, सब पार्टियां घेरे, सब लोग घेरें। अगर यह काम हो जाए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं हैं, सब रास्ते निकलेंगे, हम बाज़ार से भी और दूसरी समस्याओं से भी निपटने का काम करेंगे। आपने मुझे इस विषय पर बोलने का समय दिया ,इसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री बृजभूषण तिवारी(उत्तर प्रदेश)ः उपसभाध्यक्ष महोदय, जैसा कि वृंदा जी ने इस महत्वपूर्ण मंत्रालय के ग्रांट पर अपनी बहस की शुरूआत की और उन्होंने जिन मौलिक मुद्दों की तरफ इशारा किया, मैं उनको इसके लिए बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं। यह बहस बहुत अच्छे तरीके से हो रही हैं और लोगों ने अपनी चिंताएं भी व्यक्त की हैं। माननीय शरद यादव जी ने बहुत ही व्यापक संदर्भ में इस विषय को रखा और उन्होंने इसे माना और मैं भी उनसे पूरी तरह से सहमत हूं कि हमारा पूरा राजनैतिक जीवन हैं, आचारण हैं, वह पाखण्डपूर्ण हैं। संवेदनाएं हमारी खत्म होती जा रही है और अब ये संवेदनाएं, संवेदनाएं नहीं रह गई, सबसे बड़ी बात यह हो गई कि हम संवेदनाओं का व्यापार करने लगे हैं। यही कारण हैं कि गरीबों के प्रति, गांव के प्रति, किसान के प्रति जो हमारे अंदर आग पैदा होनी चाहिए थी, जो हमारे अंदर संवेदना पैदा होनी चाहिए थी, वह नहीं पैदा हुई। आज जो ग्रामीण विकास की बात हम करते हैं, इस ग्रामीण विकास का मतलब केवल ग्रामीण विकास का नहीं है, यह पूरे देश के विकास का मतलब हैं, गांव के ऊपर ही पूरा देश खड़ा हैं। गांधी जी ने उस जमाने में कहा था कि देश की आत्मा गांव में निवास करती हैं। उन्होंने बहुत ही साफ तौर पर कहा था कि गांव भारत की जड़ में हैं वह शहर साम्राज्यवादियों की बनावट हैं, यह उनका निर्माण किया हुआ है, क्योंकि यह जो शहर पनपते हैं, यह गांव के शोषण के आधार पर, गांव के लूट के आधार पर पनपते हैं और इसीलिए गांधी जी ने बहुत ही स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर सचमुच देश को आगे बढ़ना हैं, देश को संपन्न होना है, देश को समृद्वशाली बनना हैं, तो इसके लिए जरूरी हैं कि हमें गांव का विकास करना पड़ेगा, गांव में स्वराज स्थापित करना पड़ेगा, परन्तु हमने जो विकास का ढांचा अख्तियार किया, विकास का जो ढांचा अपनाया, वह शहर के लिए था, वह उद्योग के लिए था और हमारी सारी जो आस्था है, हमारा जो विश्वास है, वह हमारा विश्वास कभी भी गांव पर, कभी भी गरीब पर नहीं रहा हैं। हमारा विश्वास रहा हैं, अगर हमें देश को आगे बढ़ाना हैं, दुनिया की पंचायत में हमें अपनी हाजिरी दर्ज करानी हैं तो हमें चमक-दमक से आगे बढ़ना पड़ेगा और उस प्रगति का रास्ता केवल उद्योग के जरिए, केवल शहरों के जरिए हो सकता हैं। गांधी जी ने एक बार कहा कि हम कोई बहुत विद्वान नहीं हैं, हम बहुत साधारण आदमी हैं, आम आदमी हैं, परन्तु हमारी आस्था, हमारा विश्वास चूंकि चरखे में हैं, हमारा विश्वास चूंकि गांव में हैं, इसलिए हम उस बात को बहुत ही द्दढ़ता के साथ कहते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने एक जगह कहा कि हमारे मित्र जो हमसे कई गुणा ज्यादा विद्वान थे, उनसे हमारी बड़ी चर्चा हुई और उस चर्चा के बाद ही जो " हिन्द स्वराज" नाम की किताब है, वह " हिन्द स्वराज" नाम की किताब को उसी तरीके से लिखा, जिस तरीके से उनकी चर्चा हुई थी। गांधी जी और उस जमाने में जो नेता थे, कांग्रेस पार्टी के जो देश के नेता थे पं. जवाहर लाल नेहरू उनमें वैचारिक मतभेद था। एक जगह गांधी जी ने इस बात को बहुत ही स्पष्ट किया कि वह चाहते थे कि हमारा और नेहरू का मतभेद जग-जाहिर हो, मालूम हो कि हम देश को आग बढ़ाने का क्या रास्ता चाहते हैं और नेहरू जी देश को आगे बढ़ाने को क्या रास्ता चाहते हैं। आज हम देख रहे हैं कि जो ढांचा हमने शुरू किया था, जिस ढांचे पर हमने देश को आग बढ़ाने की कोशिश की थी, आज उसका नतीजा क्या हैं। आज विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा हैं कि दुनिया में जितने गरीब हैं, उनमें से ज्यादा गरीब भारत में रहते हैं और उनमें से तीन-चौथाई गरीब गांवों में रहते हैं। आज गांवों में जिस तरीके से, जिस व्यापक पैमाने पर पलान हो रहा हैं, जिस व्यापक पैमान पर ग्रामीण युवकों के अंदर असंतोष है, गुस्सा हैं, उसका कारण क्या हैं ? उसका कारण यह है कि आज गांवों में न तो रोज़ी रह गई, न रोज़गार रह गया है, वहां कमाई का कोई साधन नहीं रहा। गांव उजड़ते चले जा रहे हैं और उसका मूल कारण क्या हैं ? उसका मूल कारण यह हैं कि गांवों के ऊपर, ग्रामीण विकास के ऊपर हमें जितना धन आवंटित करना चाहिए, वह धन हमने आवंटित नहीं किया। हमने जितना धन आधुनिक उद्योगों पर, सेवा क्षेत्र पर, बड़े-बड़े शहरों की संरचना के निर्माण के ऊपर खर्च किया, एक मोट हिसाब से पूरे जो निवेश हुए है, उन निवेशों के अनुपात में कृषि और ग्रामीण विकास पर एक प्रतिशत का निवेश हुआ है। अगर हम प्रति व्यक्ति का हिसाब लगाएं, तो एक और एक हज़ार का फर्क आता है। अगर इतना बड़ा फर्क होगा, तो कैसे हम संसाधन जुटाएंगे और वह संसाधन हम नहीं जुटा पाएंगे, तो गांवों का विकास कैसे होगा ? गांवों के विकास के लिए आवश्यक है कि सड़क हो, गांवों के विकास के लिए आवश्यक है कि वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था हो, कि वहां पर बिजली हो, ऊर्जा हो, वहां पर पढ़ाई का इंतजाम हो, क्योंकि अगर हमें देश से गरीबी खत्म करनी है और जब हम यह मानते हैं कि देश

में गरीबों का तीन-चौथाई हिस्सा गांवों में है, तो गरीबी खत्म करने की जो हमारी Strategy होगी, वह दोहरी strategy होगी। एक तरफ तो हमें ऐसे विकास के ढांचे को तैयार करना होगा, जो लेबर यानी श्रम प्रधान हो और उसी के साथ-साथ जो हमारा मानव संसाधन है, उसके विकास की बातें करनी होगी। लेबर इंटेंसिव ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ हूमन कैपिटल, ये दोनों बातें हमको करनी पड़ेंगी, तब यह होगा, परंतु हम क्या देखते हैं ? हम यह देखते हैं कि लगातार, जो अभी डा. पटनायक एक बहुत विद्वान अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि 1989-90 में सकल घरेलू उत्पाद का सकल विकास खर्च 14.5 प्रतिशत था, वह 2005 में घटकर 5.9 प्रतिशत हो गया, यानी 30,000 करोड़ रूपए का नुकसान प्रति वर्ष हुआ। यह हमारे निवेश की कमी के कारण हुआ। उसी के साथ-साथ केंद्रीय बजट का आकलन करने वाली एक गैर सरकारी संस्था है- सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेस एकाउंटेबिलिटी, उसने भी कहा है कि 2008-09 का जो बजट पेश हुआ है, उसमें ग्रामीण विकास में जो धन आवंटित किया गया है, उसमें कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की गई है, उसमें stagnancy है, जैसे-तैसे ही उसमें प्रावधान किया गया है। तो एक तो सबसे बड़ा प्रश्न यह हैं कि हमारा जो बजटीय प्रावधान है, उसमें हम कोई परिवर्तन ही नहीं करना चाहते, क्योंकि जो हमारी ग्रामीण विकास की समस्याएं है और उस ग्रामीण विकास में हिंदुस्तान की आबादी का जो इतना बड़ा हिस्सा शामिल हैं, उसकी आवश्यकताओं को, उसकी जरूरतों को देखते हुए, यह जो आवंटित धन है, उसकी राशि बहुत ही कम है। दूसरी बात यह है कि हमारी प्राथमिकताएं ही नहीं हैं। अभी 11 वीं पंचवर्षीय योजना का जो approach paper पेश किया गया, उसमें भी जितना ज़ोर देना चाहिए उतना ज़ोर हमने ग्रामीण क्षेत्र पर नहीं दिया। इतना ही नहीं, प्रधान मंत्री के नेतृत्व में जो हाई लैवल कमेटी गठित की गई, उसमें भी ग्रामीण उत्पादकता और सेवा संरक्षा को ग्रामीण विकास में दर्जा नहीं दिया गया। केवल सड़क निर्माण करने से या केवल शुद्ध पीने का पानी देने से ही ग्रामीण विकास नहीं होता। उसके लिए आवश्यकता यह है कि हम प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, ग्रामीण क्षेत्र में हम उत्पादकता कैसे बढ़ाएं ? खेती की उत्पादकता, लेबर की उत्पादकता, छोटे-छोटे उद्योग धंधे उजड़ गए हैं। अर्जुन सेनगुप्त ने स्वंय अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 58 लाख यूनिट्स हैं जिनमें पांच से लेकर दस आदमी तक लगते हैं। 5 से लेकर 10 लाख तक की पूंजी उसमें लगती हैं। लेकिन आज उन यूनिट्स की क्या हालत हैं ? जब हम ग्रामीण विकास की बात करते है तो उसमें सरंचना के साथ-साथ विपणन भी है, मार्केटिंग भी है, इसके अतिरिक्त हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं है, शिक्षा की सुविधाएं है, इन सबके बारे में जो हमारी सर्वागीण दृष्टि होनी चाहिए। जब तक हम उस सर्वागीण दृष्टि को नही रखेंगे, तब तक ग्रामीण विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन इसमें भी सरकार की जो सोच है, वही सरकार की नीतियों को कार्यान्वित करने वाली जो एजेंसी है, उनकी भी दृष्टि हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि हमारी सोच में खोट है, हमारी आस्था में खोट है। गांधी जी ने कहा था, हमारे जितने बड़े नेता है, उन्होंने भी कहा था कि अगर हमें विकास करना है तो हम विकास उधार चिंतन से और उधार पूंजी से नहीं कर सकते। विदेशी पूंजी की आवश्यकता है लेकिन जैसे इंजन चलाने के लिए furnace oil की आवश्यकता है, उसी प्रकार से विदेशी पूंजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन विदेशी पूंजी के बल पर हम अगर अपने पूरे विकास के ढांचे को, विकास की प्रक्रिया को तेज करना चाहेंगे तो उसका नतीजा आज हमारे सामने है कि हम खाने के भी मोहताज हैं, बेरोजगारों की संख्या निंरतर बढ़ती जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में भी, शहरी क्षेत्र में भी, संगठित क्षेत्र में भी और असंगठित क्षेत्र में भी जो हमारे उद्योग है, उन उद्योगों के उत्पादन में निरंतर कमी आ रही है आज महंगाई की मार इतनी विकट हो गयी है, उसका कारण क्या हैं? उसका कारण यह है कि जो आर्थिक प्रगति है, जो आर्थिक उत्पादकता है, वह निरंतर कम हो रही हैं। यह हमारी समस्या का मूल कारण हैं। इसलिए हमें पहले अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। हमें यह विचार करना पड़ेगा और दृढ़ता के साथ यह बात कहनी पड़ेगी। इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन लोगों की है जो सत्ता में बैठे हुए हैं। हम लोग समाजवादी हैं, गांधी जी समाजवादी नहीं थे, लेकिन गांधी जी ने भी कहा था कि जो राजा है, जो सम्पन्न आदमी है, उसकी जो आवश्यकताएं है और जो गरीब से गरीब आदमी है, निर्धन से निर्धन आदमी है, उसकी जो आवश्यकताएं है, अगर उसकी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा सकती तो व्यवस्था किसी काम की नहीं हैं। हम लोग भी यही कहते हैं। हमने नेता लोहिया जी भी यही कहते थे कि बिना समता के सम्पन्नता असंभव है, हो ही नही सकती। कुछ लोग सोचते थे कि पहले सम्पन्नता हासिल कर लें। दुनिया उसी रास्ते पर चली, हिन्दुस्तान भी उसी रास्ते पर चला पर हम देखते हैं कि सम्पन्नता कि कितनी विकृतियां आज हमारे समाज में, आज हमारी संस्कृति में, आज हमारी सोच में दिखायी पड़ती हैं। इसलिए समता के बिना सम्पन्नता असंभव है और सम्पन्नता के बिना समता निरर्थक हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने कई प्रकार की नीतियां चलायीं, कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए लेकिन उन कार्यक्रमों का नतीजा कुछ नहीं निकला। 60 साल तब अरबों-अरब रूपया हमने इस प्रकार के कार्यक्रमों पर खर्च किया लेकिन अगर हम ग्राउंड रिएलिटी देखें, तो जो गांव के लोग है, उनके जीवन में- चाहे सामाजिक जीवन हो या आर्थिक जीवन हो- उसमें किसी प्रकार का सुधार हमें देखेने को नहीं मिला। उसका कारण एक

तो माइंड सेटअप और दूसरा जो कॉफीडेंस है, वह कॉफीडेंस नहीं हैं । तीसरा, जो सहृदयता होनी चाहिए, जो संवदेना होनी चाहिए, गांव के प्रति, गरीब के प्रति जो sincerity होनी चाहिए, वह sincerity नहीं हैं । जो राजनीतिकर्मी हैं, वे राजनीतिकर्मी आम जनता से जुड़ने के बजाय अपने नेता और उस नेता के परिवार की खुशामद करते हैं और अपनी तरक्की के नाते कीर्तन मंडली में शामिल रहते हैं । महोदय, एक सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुद्व जल का है । अभी शरद जी ने कहा कि पानी की समस्या है । आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम शुद्व पीने का पानी भी मुहैया नहीं करा पा रहे हैं । आप दूध-दही की बात छोड़ दीजिए,कैलोरीज़ की बात छोड़ दीजिए । जो हमारे विकास के लिए,हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है, हम उसका भी इंतजाम नहीं कर पाए हैं और इतना ही नहीं 2007 और 2008 में अनुमानित आबंटन 9632 करोड़ के मुकाबले ....(**व्यवधान**)

श्री शरद यादव: तिवारी जी, एक मिनट । आप जो कह रहे हैं मैं उसमें एड करना चाहता हूं । पानी की कमी गरीब के लिए हैं । आजकल इस देश में बोतल बंद पानी 15-20 रूपए में मिल रहा हैं और दूध 9 रूपए हैं । तो पानी की कमी भी आजकल उसी गरीब को हैं जिसकी आप चर्चा कर रहे है ।

श्री बृज भूषण तिवारी: तो हम यह कहना चाहते हैं कि 2007-2008 में अनुमानित आबंटन 9632 करोड़ रूपया हैं और उसको केवल 6500 करोड़ रूपया ही आबंटित किया गया । इस प्रकार हमारी आवश्यकता 9632 करोड़ की हैं और आबंटित किया गया है 6500 करोड़ । जैसा कि शरद जी ने कहा कि आज हमारे देश में पीने के पानी का बहुत बड़ा उद्योग हैं । सवा सौ करोड़ से भी ज्यादा का यह उद्योग फल-फूल रहा हैं और जैसे-जैसे पानी के व्यापार का निजीकरण हो रहा हैं वैसे-वैसे सरकारें अपनी जिम्मेदारियों से विरत होती जा रही हैं । उसका सबसे बड़ा संकट यह आ गया हैं कि पानी का जल स्तर है-भूगर्भ, वह निंरतर गिरता जा रहा हैं । अगर हमारे पानी का जल स्तर गिर गया तो हमारे टैंक सूख जाएंगे, हमारे तालाब सूख जाएंगे, हमारी नदियां सूख जाएंगी । उसका सबसे बड़ा कारण यह हैं कि तमाम बहुराष्ट्रीय कम्पनियां जो पानी के व्यापार में शामिल हो गई हैं उनके दोहन के कारण इतना बड़ा संकट पैदा हो गया हैं । स्टेंडिंग कमेटी ने मांग की थी कि इस प्रकार की कोई प्लानिंग होनी चाहिए, राज्य सरकारों को एक कानून बनाना चाहिए जो जमीन के नीचे के पानी का शोषण करते है, जो उसका इस्तेमाल करते है, उस पर रोक लगनी चाहिए । अब उसी के साथ-साथ .....(**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष(श्री उदय प्रताप सिंह): अभी आप कितना समय और लेंगे?

श्री बृज भूषण तिवारी: दो मिनट दे दीजिए । इसी के साथ ही साथ जो पानी की गुणवत्ता है वह भी बहुत महत्वपूर्ण हैं । जिस तरीके से गांवों में नल गाढ़ दिए जाते हैं और जल निगम का यह इस विभाग का काम केवल नल गाढ़ना है, मगर नल के पानी की गुणवत्ता क्या है, उसके बारे में कोई जांच-पड़ताल नहीं की जाती हैं । आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सरकारी रिपोर्ट के हिसाब से देश में दो लाख तैंतिस हजार तीन सौ चौतिस ग्राम पंचायतें है और इनमें से सौलह हजार आठ सौ अस्सी के पास ही फील्ड टैस्ट किट है, जिसके द्वारा मौके पर जाकर पानी की गुणवत्ता की जांच की जा सकती हैं । तो आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि पानी की गुणवत्ता की जांच हर ग्राम में कैसी होगी । दूसरे, यह जो राष्ट्रीय रोजगार गांरटी योजना है, इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, बहुत कुछ कहा गया हैं । मैं केवल कम्पट्रोलर आडिटर जनरल की रिपोर्ट का कुछ अंश सदन के सामने रखना चाहता हूंः

The main deficiency was the lack of adequate administrative and technical manpower at the Block and Gram Panchayat level. The lack of manpower adversely affected the preparation of plans, scrutiny, approval, monitoring and measurement of works, and maintenance of the stipulated records at the block and Gram Panchayat level. Besides affecting the implementation of the scheme and the provision of employment, this also impacted adversely on transparency and made it difficult to verify the provision of the legal guarantee of 100 days of employment on demand. Planning was inadequately delayed which resulted in poor progress of works. Systems work, financial management and tracking were deficient with numerous instances of diversion, misutilisation and delay in transfer of States' share. Maintenance of records at the block and Gram Panchayat level was extremely poor and the status of monitoring, evaluation and social audit was also not up to the mark यह सीएजी की रिपोर्ट मैंने सदन के सामने रखी हैं । इससे साफ हो "

जाता हैं कि यह इतनी अच्छी योजना है, जिसके प्रति हमारे माननीय मंत्री जी बहुत ही सीरियस और बहुत ही संवदेनशील हैं, परन्तु जो हमारी नौकरशाही हैं, जो हमारा मांइडसेट हैं, जिसके बारे में मैंने कहा हैं कि जब हमारी आस्था ही नहीं है, हमारा विश्वास ही नहीं है, हमारी किसी प्रकार की संवदेना और सहृदयता ही गरीब और गांव के प्रति नहीं है, तो कोई भी अच्छी से अच्छी योजना या स्कीम चलाई जाये, वह सफल नहीं हो सकती। जो हमारा टारगेट है, जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम हासिल नहीं कर सकते। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI S. ANBALAGAN (Tamil Nadu): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for having given me this opportunity.

On behalf of my party, AIADMK, I wish to put forth my views on the discussion with regard to the working of the Ministry of Rural Development.

First of all, Sir, I would like to state that the benefit of the various Schemes which have been brought forward by this Government for the welfare and development of rural masses across the country is not reaching the poor and the down-trodden. I feel that there is a lacuna in the implementation of these schemes.

Then, I would further like to state that most of the schemes which the Government is implementing have already been initiated and implemented successfully by our founder leader and the former Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. M.G Ramachandran, in the name of the 'Self-Sufficiency Scheme" allocating Rs. one crore for each panchayat union of all districts of Tamil Nadu to provide basic amenities like water, electricity, sanitation and proper roads, construction of school buildings with particular emphasis on the welfare of Schedule Castes and Schedule Tribes. The scheme was successfully continued during the tenure of the General Secretary of AIADMK Party and the former Chief Minister of Tamil Nadu, *Amma,* for the welfare of rural masses. Now, on similar basis, the Central Government is formulating scheme for rural development. Tamil Nadu is a forerunner and a standing example of successful implementation of such schemes. Now, the funds allocated by the Central Government are routed through the State Government. But, in several cases, it has not reached the rural masses and they are diverted for the State-sponsored schemes resulting in failure of the schemes.

Sir, *Bharat Nirman* is one of the initiatives taken by the Government to improve the economic and social infrastructure of the rural areas of the country. It has six components, namely, irrigation, roads, water supply, housing, rural electrification and rural telecom connectivity. The total investment under the *Bharat Nirman* to be made during the last four years, i.e., from 2005 to 2009, has been.estimated as Rs. 1,74,000 crores. But these projects are not properly monitored by the Central Government, thus resulting in under-development of various areas.

Similarly, the National Rural Health Mission, for which Rs. 11,010 crores has been allocated for improving the basic amenities of health care and sanitation, is not working at a desirable rate in the rural areas and it needs to be attended to on a war-footing. The infrastructure is not improving. The Central Government should regularly call for the reports from the States and make surprise inspection visits to the States to get the first-hand assessment of the on-going schemes. This will help in streamlining the better implementation of the various schemes.

Sir, then there is another important matter. It is related to water scarcity. Though the Government is implementing various schemes for providing potable water to each and every

hamlet of our country, it is not getting the desired success rate. There are many villages in our country which have been water-starved for years now. People have to travel long distances to fetch drinking water. The previous Government had set up a committee to look into the possibility of inter-linking of major rivers to solve the water shortage across the country. The committee has already submitted its report. After assuming power in 2004, the UPA Government has not taken any action on this report. The Government should come forward with some effective proposal to solve the drinking water problem across the country on top priority.

Sir, the National Rural Employment Guarantee Scheme has been extended to each and every district in the States to provide a minimum of 100 man-days of employment in a financial year to members from each family to do unskilled manual work and generate income for their families. The Government has also earmarked Rs. 12,000 crores in the Plan allocation to implement this scheme. The State Government of Tamil Nadu has been given a sanction of Rs. 2000 crores for this scheme to be implemented. I would like to mention that our founder leader and former Chief Minister, Dr. M.G.R. and *Amma* have already implemented the scheme to provide jobs and income to poor people across the State. Now, the plan to provide minimum 100 days of work for unskilled workers from each family is not attracting poor people as the minimum wage of Rs. 80/- per day is not sufficient for the family to have two square meals a day. As a result, the scheme is not being implemented properly. If the Government makes arrangements to conduct surprise inspections during implementation of the scheme, they would get alarming reports about the misuse of funds so allocated.

Then, Sir, most of the villages and municipalities lack in basic amenities such as sanitation, healthcare, road-connectivity and proper educational institutions. Government should take steps on a war-footing to provide these basic facilities so that the rural poor can, at least, have the basic amenities of life. I hope the Government will look into my suggestions while taking up the implementation of the ongoing schemes.

SHRIMATI SUPRIYA SULE (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman Sir, I stand here not to criticise any of these schemes which the Government of India has put forward for the benefit of all the rural people of this country. We appreciate all the schemes. When I work in the field, I do not go by any report; I go purely by the experience that we all have in the field, either through Collectors or Gram Panchayat members or elected Members of the State Legislatures. We have realize that there is, as I Think in many of these discussions a lot of senior Members have mentioned, a huge gap between planning and implementation of the various schemes. I have very little time; so, I am going to quickly run through a few recommendations or demands that we have towards the Minister.

Sir, first, we appreciate the rural development machinery; whether it is the rural roads, the employment schemes or the flagship programmes like the Sarva Shiksha Abhiyan, the MRHM, these are all done by RDD in every conrer of this country and we appreciate all the effort that this department puts in. To highlight some of the programmes, one is the Haryali Programme for drought-prone areas, which is run by the Gram Panchayat. The Water Conservation Programme is done in phases. Normally, even the community participates in this programme. Unfortunately, the funding never comes in time. When all these water conservation programmes are implemented, if they are not done in all the phases, then you have to start from the beginning again. Normally, the funding for the first phase comes and the funding for the second phase gets delayed. If that happens, we have to start right from scratch again, So, it is a completely meaningless process and too much money is lost. The

other programme for water conservation, which is right now lagging, is the DPAP programme. Sir, 1 want to quote from a report. According to the Fifth Allocation Batch, that was done in 1999, in a lot of programmes, even today, payments were delayed. Up to the third level, it has been done, but the fourth and the fifth are not done and I think the Government has taken the stand that they have no intention of completing it. Sir, if this happens, whatever has been spent on the first, second and the third phase is just going to be a waste. Whatever the reasons have been, this may be some sort of a punishment to the State Governments for not completing the projects on time, but it is eventually the people of the States that are going to suffer, not any Gram Panchayat. So, I request you if you could get all these allocations in place. I also request you to increase the amount from Rs. 3000 per hectare, given the cost of everything escalating, under the new policy which you are planning to review. I think that has to be substantially increased because water conservation is a very serious issue which the Government of India has taken up. I would like to highlight the Indo-German Watershed Programme which, in Maharashtra, we are implementing through NABARD and which has given good results. In spite of all of us doing different work in different areas, if any of these DPAP, Haryali or IGWP could come together, I am sure a lot of money and energy will be saved. The other flagship programme which we compliment, as many of the speakers before me have done, is the NREG programme. I would just like to highlight issues relating to the State where I come from. The problem with the NREG in my State in that 50 per cent of the money is spent by the Panchayati Raj institutions. What happens with the Gram Panchayats is that they do not have the expertise and all the 4 per cent, which is allotted to them for the technical experts, is only given at the end of the project. So, if the budget is of Rs. 1 crore, Rs. 4 lakh is only given at the end which is totally meaningless because we need the experts right from the beginning. So, the 4 per cent should be allotted to them right from the beginning. The other big problem in Maharashtra is that it is very hard for us to get more than 50 people for this NREG which is your norm. So, 1 think you have to consider and relax this. I am sure it is very difficult for you because these are national programmes, but we have to relax it because NREG is not doing very well in the State where I come from. The other norm which is there is About 60 per cent water conservation. Sir, Maharashtra has done a lot of work in conservation and a lot of this money comes from either through EGS or the forest funding. So, a lot of conservation work is already being done in our State. So, it is very hard for us to give 60 per cent allocation only for water allocation. So, these norms have to be relaxed if you really want to reach out to all the people in our State. We compliment you for the sanitation programme, that is, the Nirmal Gram Yojana, and I am proud to say that Maharashtra is one of the top States which is doing exceptionally well in Nirmal Gram Yojana. But we need to even work for preventive measures. Today when we talk about NRHM, we really talk about sanitation. Sanitation is the biggest problem. So, we appreciate the new initiatives you have taken for preventive measures of waste water management and solid waste management. But unless clear guidelines for this programme are in place, which the Centre has planned, it is not getting implemented in any States. So, there has to be some more detailed plan for sanitation. The road programme is doing well. The other programme in which my State is lagging behind is the water supply. Sir, a lot of parts of Maharashtra do not have good water supply and the deadline for the completion of this programme is 2008-09. I don't think it is possible for us to achieve it in Maharashtra, not in Maharashtra, but in many parts of the country. So, we will have to relax this norm and take this programme to 2009-10 in areas where it is weaker. There is Swajaldhara Yojana where Maharashtra Government has asked for a lot of money. About Rs. 102 crore have already been given, but the demand is not being released and there may be expansions required. So, I think, that should be

considered. Now, I just run through my demands without getting into any details. Sir, there is one kiosk for six villages for the Common Service Centre Programme which is running in Maharashtra. It is impossible for so many Gram Panchayats, because Gram Panchayats' size in Maharashtra varies. So, we request the Government to have one Kiosk per Gram Panchayat and that is the only way which is really going to benefit the Coverage. It will reduce the work of our teachers and our Anganwadi workers, if this kiosk is used for multi-purposes and making all the various reports. The point which Brindaji also covered is about BPL. In BPL what we all think is that benchmark is 19 per cent. Sir, in parts of the country some villages are big, some are small, some are weaker and some are poorer. So, 19 per cent cannot be a benchmark of any survey. So, it has to be relaxed and we are looking for a very hopeful solution from you. The last and the longest point is about Self-Help Group. There are a few demands which we all have. At present, the interest rate is 9 to 12 per cent. We urge you that it has to come down to 4 per cent. Otherwise, women cannot sustain themselves. Second is that Zila Parishad has to give some sort of a market outlet to these women to display if they have to grow their small culture and survive in this competitive market. There is training faculty by the RDD but for the marketing, quality and packaging, there has to be more funding available. Today, it is only 15 rupees. Today, you get nothing in 15 rupees. Sir, right now, the RDD department is giving 15 rupees for Two days of training for one person. Government agencies are doing it but there is no quality for even the trainers who are coming. The whole allocation is totally meaningless because it is not giving good results.

Sir, another thing is that the loans have to be reviewed. Lot of women in the SHG do not get loans, fresh loans because their husbands have got loans which they have not repaid. We will have to rethink and review all these and make all these loans available like the Grameen Bank has done in Bangladesh.

Last thing is about octroi exemption. Sir, since for SEZs and all these programmes, the Government of India is giving all kinds of relaxations whether it is octroi, taxes, VAT. Sir, in this way, the SHG products can be encouraged, and, if they have to have a level playing field, you have to relax these norms, maybe also through railway, transportation etc. I think, sir, all these norms have to be relaxed if the Government is truly committed to strengthening the SHG environment which is really growing everyday in the country. Sir, I think, these women really need a boost, and, moreover, these norms have to be relaxed forever. Give us a five or ten year programmes. Once we stand on our own feet, we are willing to be on a level playing field with all these malls. Probably, SHG will have its own malls and we will be happy to pay VAT or a tax or any kind of octroi to the Government of India. Thank you.

उपसभाध्यक्ष (श्री उदय प्रताप सिंह)**:** सदस्यगण, पांच बजे मंत्री जी को उत्तर देना हैं और अभी 6 वक्ता और हैं, तो मैं आप से यही चाहूंगा कि आप अपने निर्धारित समय में अपनी आवश्यक बातें कह दें। श्री प्रवीण राष्ट्रपाल जी।

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL: Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to thank my Party for having selected me to speak on this important subject of rural development. Sir, the debate was very rightly started by Comrade Brinda Karat. Sometimes she does not help us. Instead of helping Congress, she is helping somebody who is criticizing XYZ. But I don't want to get into the details. We can discuss it outside.

Sir, today morning, a beautiful question was asked, which, I think, cannot be answered by any Minister. The question was: when will we become a 'developed country[1] from a 'developing country'? According to me, if we want to become developed, we must improve rural development and give priority to rural areas, rural population in this country. And, for that, we must improve our agricultural yield, improve the vegetable quality, improve varieties of

fruits and improve the health of our livestock. We must have healthy livestock. We must have very good agricultural yield. We must have the best vegetables. We must produce varieties of fruits. The quality of milk products should also improve. The water resources should be sufficient. The small-scale industries, which are in crores in numbers, should be revived and made viable because these are mostly there in the rural India. Last but not the least, I would also like to mention about human resources, Sir, seventy per cent of the population is in rural India. It is hardly one or two States where there is 35 or 36 per cent urban population and the remaining 65 per cent is in the rural population. Taking the total figure as a whole, out of 127 crore population as on date, seventy per cent population is in rural India.

Mr. Vice-Chairman, Sir, the Father of the Nation once said, "India lives in villages". I was very much impressed by my senior colleague Mr. Sharad Yadav's references to Mahatma Gandhi. But I was totally disappointed when he justified the Maoist revolution in Nepal. Sir, I have great respect for Lohia but I cannot understand how a follower of Lohia, how a follower of Ambedkar, how a follower of Mahatma Gandhi can justify the Maoist revolution in Nepal. Here, we say it as 'naxalwadi' and we are worried, we are fighting against naxalism. There was a little confusion about the whole thing. Sir, I have read Lohia, and, in fact, if we want to remove disparities in this country, only one sentence of Lohia will be sufficientउन्होंने ऐसा कहा था कि प्रजा और राजसत्ता वर्ग की भाषा,भूषा,भवन और भोजन एक सा होना चाहिए,प्रजा जो कपड़ा पहनती है, वही कपड़ा राजा पहने, राजा यानी मिनिस्टर । लेकिन, आज क्या हो रहा हैं? मेरा अहमदाबाद में एक घर है, मैं थोड़ा हिन्दी में बोलूंगा तो और अच्छा रहेगा, दिल्ली में भी घर हैं क्योंकि मैं एम.पी. हूं । मेरा अहमदाबाद में एक दो कमरे वाला छोटा सा घर है, दिल्ली में भी एक घर है, क्योंकि मैं एम.पी.हूं, लेकिन हिन्दूस्तान के सब शहरों में मेरा घर नहीं है लेकिन, हिन्दुस्तान में जो सिनेमा में काम करने वाले लोग हैं या क्रिकेट वाले जो लोग हैं, बड़े-बड़े लोग हैं, उनमें कुछ हमारे दोस्त भी हैं, मिनिस्टर लोग हैं, उनका एक घर होता हैं, फिर एक फार्म हाऊस होता है, जहां एक जमाने में खेती होती थी, वहां अब बगीचा हो गया है और वहां वे Sunday के दिन जाते हैं । गुजरात में हमारा एक दोस्त हैं जिसने शादी नहीं की, लेकिन उसके पास चार dedroom हैं मैंने बोला ये bed हैं या bed हैं । बिना शादी वाले आदमी को चार bedroom क्यों चाहिए । शरद साहब की बात मुझे अच्छी लगी कि हमको डिस्पैरिटी रिमूव करनी है, गरीबी हटाने के लिए डिस्पैरिटी रिमूव करनी होगी

Coming to the issue of Shri Raghuvansh Prasad's Ministry, I congratulate him because whenever I have gone to his Ministry, he always met me, he is always available. But I will recommend cutting the salary of his secretary, not his personal secretary, but the Secretary, the Joint Secretary, etc. Whenever 1 want to meet them, they are never available, and I have brought today documentary evidence with me. 1 mean, this will not work. You must cut their salary. 1 have got a letter. When I attended a consultative committee of this Ministry, 1 spoke on behalf of Uttar Pradesh and Gujarat. I had actually worked in the area of rural development. I have travelled,. Sir, 17 districts of Uttar Pradesh for monitoring whether the Rural Employment Guarantee Scheme is properly implemented or not. But, as an MP from Gujarat, when I was invited for the meeting, I told the hon. Minister and officers, some 50 officers were there, that the State-level monitoring Committee in Gujarat had not met for the last two years. Now, I am a member of the State-level monitoring committee of Gujarat and there are MPs from BJP also. Six MPs from Delhi are members of the committee, 8 MLAs are members of the State-level Committee. It is known as monitoring and vigilance committee of Gujarat. I have got copies of the order of Shri Raghuvansh Prasad when I met him. He appointed me also. Originally I was not a member. He cannot appoint me in Uttar Pradesh. But, he appointed me. After that letter, I wrote a letter to the Chief Secretary; I wrote a letter to his Joint Secretary. The copy is here. One, Anita Sharma is his Joint Secretary. I wrote and asked what

4.00 P.M.

is this. A vigilance and monitoring committee is appointed. My letter is dated, I will give you the date of my letter also so that the Minister can take action against the concerned officer because politicians are very much criticised in this country and bureaucrats are eating fruits of the Pay Commission. My letter is dated 7th February, 2008.

SHRIMATI BRINDA KARAT: She is a good officer.

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL: May be. The letter is dated 7th February, 2008. My another letter is dated 20th February, 2008. Now, 1 am coming to the core issue. I wrote a letter to the hon. Prime Minister about how to improve this particular scheme of National Rural Employment Guarantee. I must thank the hon. Prime Minister. My letter was sent to the Department and a result, the Department prepared a two-page note and it was sent to the hon. Prime Minister, and a reply was sent to me also. I must thank the Department. I have got a copy of that. Now, what was my suggestion? This is the original Act of the NREG. Now, if you open page 21 of the Act, what type of works can be done under the NREG? Eleven items are there and one of the items is 'any other work that may be notified by the Central Government in consultation with the State Government'. This is not done anywhere in the country. There are various other works which can be done from home. For example, manufacturing of soap, manufacturing of agarbatti, manufacturing of toys, cultivation of flowers, and preparing gur. There are many things which women can do from home. My suggestion is the KVIC. The Central Government should give material to women at home. After the product is ready, they should collect it from their home and pay them the money.

Now the only work which is being done all over the country under the NREGA is desilting of tanks. I know that tanks all over the country are desilted every six months. Whether they do it or not, that I do not know. This is how the money of this nation is siphoned off by the Indian bureaucrats. This is my charge. I charge them. Crores of rupees are spent in the work. The Act says that eleven types of works are there. They are not implementing them. I want the reply from the hon. Minister.

Another aspect towards which I want to draw the attention of the entire House is this. This Scheme is being implemented by an Act of Parliament. But what is the minimum wage? In Gujarat, it is Rs. 50. In Tamil Nadu, it is Rs. 100. In Punjab, it is Rs. 110. In Goa, it is either Rs. 110 or Rs. 120. It varies from State to State.

Mr. Raghuvansh Prasad, I want your kind attention. Why cannot we have a uniform minimum wage for the one who is doing work under the NREGA? I have recently collected this information for minimum wages. It is given at the rate of agriculture minimum wage of the respective State. Why should it be agriculture minimum wage of the respective State? When I am doing some work under the NREGA, it is not necessarily an agriculture work. It is given by the private employer. We must have a minimum uniform wage of either Rs. 100 or Rs. 150.1 do not understand why we are not fighting for it. One State is giving Rs. 50 for a work. In another State, for the same work, he is getting Rs. 100. Why is this disparity in the Central Act?

The third issue is regarding payment. According to my information, and my colleagues from Andhra Pradesh would support me, the payment of wages under the NREGA there it is made through post offices. It is a very good scheme. Entire fear of corruption and taking away the money is removed. Why cannot this be implemented all over the country? That is another important issue. So, my request is that instead of doing traditional work of desilting of tank, we must see what other work can also be given to them. What was the main purpose

of introducing the NREGA? The main purpose was to stop migration of poor people from rural India to urban India. People migrate from Uttar Pradesh, Bihar, and Andhra Pradesh, which are very big States, to cities of Kolkata or Mumbai or Delhi. They are going there and staying in jhopar *patties* and slums. They are living in very bad condition. If people can get employment in their own villages or in their own districts, they will not migrate.

Now, there are certain specific instructions that more and more employment may be given to women. There are certain instructions in the Act itself that the creche facility should be provided at the worksite. There should be facility for first-aid. There should be facility for drinking water. All these things are not kept anywhere.

Another thing, which I want to bring to his kind notice, is that no Monitoring Committee has met in many States. Let the House know this. What are the percentages of administrative expenditure? The limit in the Act is four per cent. I have got information about a State Government which has spent 20 per cent of the money for administrative expenditure. Now who is to take account of this? Another thing is, the promise of unemployment allowance. Name a single State where the unemployment allowance is paid till today. We would like to have a figure from the hon. Minister.

श्री बनवारी लाल कंछल (उत्तर प्रदेश): उत्तर प्रदेश में होता हैं।

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL: That information we want. इसका मतलब हैं कि आपने employment provide नहीं किया हैं। But, why was it not paid? It was not paid because the condition in the Act is that unemployment allowance will be paid by the State. It will not come out of the Central fund. This is a good condition, but, at the same time, no State Government would pay unemployment allowance. वे लोग बहाना भी करेंगे कि नहीं देंगे। In Uttar Pradesh itself, when I was working last year and when I asked as to why have you not given unemployment allowance, he has not demanded, अनपढ़ आदमी ने लिखित अर्जी कर दिया हैं। वह ग्राम सभी प्रमुख को सलाम करता है तो काम नहीं देता हैं, उसने application नहीं दिया। जब application देने के बाद जब 15 दिन हो गया तो आपने दिया तो उसने बोला कि उसने अर्जी नहीं दिया। Then, the parties have to print forms, which is done in one State, which is not done in other States. So, that is a very serious issue. But, there are two important schemes— the Total Sanitation Campaign and the National Rural Health Mission. *(Interruptions)* This is in different Ministry. But, rural sanitation is one of the best schemes. The hon. Prime Minister, after taking over, issued a circular in the month of May, 2005 itself saying that there should not be scavenging anywhere in the country. आदमी, आदमी का मैला नहीं उठाएगा।। There is the 1993 Act prohibiting manual scavenging. I am sorry to say that the practice goes on not in this or that States, but, in my own State. I will not talk about other States. गुजरात में आज भी आदमी का मैला आदमी उठाता हैं।

श्री भरतसिंह प्रभातसिंह परमार(गुजरात): गुजरात में नहीं हो रहा हैं।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : मैं बोलता हूं कि हो रहा हैं।। I have proved in you supreme Court. सुप्रीम कोर्ट में affidavit file किया हैं। मेरे साथ में आओ, मैं इस राज्य की बात करता हूं, और मैं उत्तर प्रदेश की भी बात करूंगा। आज मेरे साथ में कानपुर में आओ। कानपुर शहर के अंदर आज भी scavenger आदमी का मैला माथे पर उठा रहा हैं।। I have actually visited when I went there for three days. गुजरात में रानपुर में हो रहा है, मानसा में हो रहा हैं और दस जगह मैं बताऊं, आप मेरे साथ में आना ....(**व्यवधान**)..... ।

श्री अमर सिंह: आपने कहा कि कानपुर में मैला माथे पर उठाया जाता है, इसलिए मैंने एक अनुरोध किया कि अब तक आपकी सहयोगी रही मायावती जी

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: कौन किसका सहयोगी हैं I But the main problem Dr. Raghuvansh Prasadji is that the money which we are giving for constructing that small unit of sanitation is not sufficient. In that money, you cannot have a sanitary unit at your home. So, I am requesting the hon. Minister to please revise the norms of the size of the sanitary unit. If our villages are clean, people will also be improved in their mindset and people would like to go to villages. Some of the urban people do not go to villages only because of two problems — drinking water and sanitation facility. Even if they go, they will never stay. That is the problem which we all are facing. Drinking water is another problem. We have a programme either by this Ministry or that Ministry स्वजलधारा I हमारे और राज्यों में यह जो हो गया है कि वह स्वजलधारा का प्रोग्राम राज्याभिषेक करके दूसरे नाम से करवा दिया हैं I I want the hon. Minister to take action against those State Governments which are changing the names of the Central Government schemes. Now, one colleague from Tamil Nadu was talking about the scheme which was being implemented by their Chief Minister in the past, and we are discussing the rural development scheme at the present. Let us not do like this. What is important is that the rural India should improve. Small-scale industries, cottage and village industries, all these departments should join together, and under the supervision of the Rural Development Ministry, we should see that in the coming days, we are able to have employment and education for the entire rural population. Maximum technical institutes should be constructed in the rural areas, maximum IITs, maximum agricultural universities can be near rural India so that benefit can go to the rural people.

With these words, I thank you very much, Mr. Vice-Chairman, Sir, for allowing me to speak.

DR. GYAN PRAKASH PILANIA (Rajasthan): Grateful thanks to you, Sir. This is all agreed that rural development is of core importance to India, and if there is no rural development, there is no real development of the country. यह सब बिलकुल सही हैं । रूरल डेवलपमेंट नहीं होगा, तो वास्तव में भारत का डेवलपमेंट नहीं होगा,लेकिन इस समय मान्यवर, जो हालात हैं रूरल इंडिया के, वे हाल-बेहाल हैं और किसान की व्यथा-कथा अनंत हैं सिर्फ आशा की एक ही किरण हैं I A Minister of the calibre of Dr. Raghuvansh Prasad Singh, a Minister of his dedication, integrity, unbending rectitude, is the only hope. मैं इन्हीं को आशा की किरण मानता हूं और जैसा शरद यादव जी ने कहा था कि अगर मिनिस्टर की सोच में खोट न हो, आस्था में खोट न हो और सरलता में खोट न हो, तो काम बन सकता हैं । यह वह व्यक्ति है, जिसकी न सोच में खोट है न आस्था में खोट है और न सरलता में खोट है, लेकिन फिर भी, ज्यो-ज्यों दवा की, मर्ज़ बढ़ता गया I And way to hell is paved with best intentions. किस्सा क्या है, यह चिंतन और मनन का सवाल हैं । श्रीमती वृंदा ने बहुत अच्छा आगाज़ किया आज की इस चिंतन सभा का, आज के इस डिसकशन का । बलबीर पुंज जी ने बहुत सारगर्भित सुझाव दिए, अन्य ने भी बहुत अच्छे सुझाव दिए । शरद यादव जी ने तो बड़ा भावुक भाषण दिया और हम सब रोमांचित हो गए, लेकिन उन्होंने भाषण का पटाक्षेप किया,"या धरती फटे या इंकलाब हो", ये दोनों ही होंगे । ये न होने पर भी हमें प्रयत्न करना हैं कि रूरल इंडिया का किसी तरह से विकास हो । इस समय देश के दो हिस्से हैं, एक तो है भारत और एक हैं इंडिया । Poor भारत,rich India, dark भारत, shining India एंव वंचित भारत, भूखा भारत और अभावग्रस्त भारत- इस भारत की मैं बात करूंगा और इस भारत के बारे में ही मेरा ख्याल हैं कि रूरल डेवलपमेंट का concept उदय हुआ हैं । मान्यवर, मैं उस अंतिम व्यक्ति की बात करूंगा,जो गांवों में रहता है और शाम को तेल की कुप्पी जलाता है, जिसके लिए केरोसीन जीवन-मरण का प्रश्न है, उसके यहां बिजली नहीं पहुंचती हैं आप अपने statistics में कुछ कहिए, मगर ऐसे हज़ारों गांव अभी है, जहां बिजली बिलकुल नहीं पहुंचती । उनका डेवलपमेंट कैसे हो ? मैं उस व्यक्ति की बात करूंगा, जो पोखर में अपनी भैंस के साथ पानी पीता है और प्यास बुझाता है। उसके पास कोई नलके का,सेनिटेशन का पानी नहीं है, पानी की बोतल तो उसने देखी ही नहीं है कि कैसी होती हैं । मैं उस व्यक्ति की बात करूंगा जो गोबर के थेपड़ों से, कंडों से चुल्हा जलाता है, एलपीजी उसके लिए नहीं हैं । अंत में उस व्यक्ति की बात करूंगा जो कर्ज में पैदा हुआ, कर्ज में जिया और कर्ज में मरा । न उसे समय पर बी ज मिलता है, न पानी मिलता है और न ही खाद मिलती हैं । भूख से उसका दिन-रात का रिश्ता हैं । उस ग्रामीण का विकास कैसे हो, वह कैसे तरक्की करे । ऐसा किसान जो

जन्मजात धरती से लगाव रखता है,जिसे हम धरतीपुत्र कहते हैं, उसकी और अधिक प्रशंसा करें तो हम उसे अन्नदाता भी कहते हैं। आज वह खेती से दूर क्यों भाग रहा है, यह भी एक प्रश्न रूरल डेवलपमेंट के जो रहबर अधिष्ठाता यहां बैठे हैं, उनके सोचने का है । चाहे यह एग्रीकल्चर का मामला हो, लेकिन rural development minus agriculture is nearly nil. योजना आयोग के अनुसार देश के चालीस फीसदी किसान खेती से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और 27 फीसदी किसान खेती को फायदे का कारोबार नहीं मानते लेकिन चूंकि वे दूसरा कोई धंधा जानते नहीं है, उनके पास कोई इलाज नहीं है इसलिए वे खेती से चिपके हुए हैं । ये हालात क्यों पैदा हुए और उस गरीब की किस्मत कैसे बदले, इस पर सोचने की जरूरत हैं । मैं उसकी भी बात करूंगा जिसको आप कभी तो अन्त्योदय का खिताब दे देते हैं, कभी बीपीएल कहते हैं, कभी उसको a man last in the queue कहते हैं लेकिन वह ऐसा है,जिसके पास connectivity बिल्कुल नहीं हैं । मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा- connectivity का मतलब यह हैं कि पीने को सही पानी नहीं हैं । इरीगेशन की बात तो बाद में आती हैं- पीने के लिए पानी नहीं हैं । घर में रोशनी के लिए बिजली नहीं है, आने जाने के लिए सड़क नहीं हैं । हम connectivity और टेलीफोन की लम्बी चौड़ी बातें करते हैं लेकिन वह सब उसके पास नहीं हैं । अस्पताल जाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता हैं । वह अस्पताल जाने के बजाय बुखार में तपना पसंद करता हैं । अगर कैंसर जैसी बीमारी हो जाए तो मरना मंजूर है, क्योंकि घर बिकने पर भी कैंसर का इलाज नहीं होगा । उस गरीब की मैं बात कर रहा हूं । स्कूल बहुत दूर हैं । अगर हैं भी तो एक ही टीचर है जो कभी आता है, कभी नहीं आता हैं । शिक्षा का क्या स्तर होगा ? हाउसिंग के नाम पर एक झोंपड़ी हैं । बहुत बड़ा हुआ तो कहीं कच्चा मकान हो सकता है वरना झोंपड़ी हैं । वह उसके लिए हाउसिंग हैं । सेनिटेशन की बातें हम करते हैं, वह लोटा लेकर पाखाने के लिए जंगल में ही जाता है । ये modern concepts of living उस भारत के लिए नहीं है,उस भारत के लिए हम क्या करेंगे ? इस पर चिंतन होना चाहिए। मामले को सुधारने का कोई बहुत आसान तरीका नहीं हैं । इसके विषय में अगर आप आज्ञा दें तो स्वामीनाथन जी ने क्या कहा, मैं वह exact कोट कर दूं । उनके अनुसार, "कृषि हमारे देश की रीढ़ हैं । देश की बहुसंख्यक आबादी की रोज़ी-रोटी का इंतजाम इसी से होता हैं । 73 फीसदी लोग 5 लाख 72 हजार गांवों में रहते हैं । कृषि की सालाना विकास दर जो 1990-96 में 3.5 प्रतिशत के ऊपर पहुंच गयी थी, अगले पांच साल में वह 1.5 प्रतिशत के आस-पास पहुंच गयी । इस वक्त वह 2.2 हैं । " अंतिम बात बड़ी मार्मिक हैं । पंजाब जो हमारी गेहूं की, धान की, खाद्य उत्पादन की बास्केट है,उसके लिए कहा है कि "पंजाब में तो तीन हेक्टेयर से ज्यादा जमीन के मालिकों की आमदनी भारत सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तनख्वाह से भी कम हो गयी है ।" यह तब कहा था जब ये पे रिवीज़न नहीं हुआ था । तो उस आदमी के हालात बड़े खराब हैं और उस आदमी की बात मैं कर रहा हूं जिसके यहां अब खेतों में खुदकुशी की फसल उगती हैं और वह आत्म-हत्या करता है,60 हजारका ऋण मुक्ति या ऋण माफी का हुकमनामा जारी होने के बाद भी । इसके बा भी विदर्भ में 15-4-08 तक 120 किसानों के द्वारा खुदकुशी की गई है, यह अखबारों में छपा हुआ एक फैक्ट मैं अर्ज कर रहा हूं । वह व्यक्ति जो हर आधे घंटे में खुदकुशी करता हैं, वे व्यक्ति जो 17 हजार खुदकुशी साल भर में करते हैं, वे व्यक्ति जिन्होंने दस साल में डेढ़ लाख खुदकुशियां की । 2006 में आंकड़ों के मुताबिक इस व्यक्ति ने जिसकी मैं रूरल डवलपमेंट की बात कर रहा हूं, वह 17 हजार 60 लोगों ने आत्म हत्याएं की और आनन्द यह है कि महामहिम प्रेजीडेंट के भाषण में किसानों की खुदकुशी का कोई ज़िक्र नहीं हैं । मैं पार्टीजन बात नहीं करना चाहता, लेकिन इसका मुझे दर्द हुआ है किसान का एक बेटा होने के नाते देश में इतना बड़ा जलजला और हर साल ऐवरेज 17 हजार किसान खुदकुशी करें और इसका प्रेजीडेंट के भाषण में ज़िक्र तक न हो । राष्ट्र के महामहिम के भाषण में यह आश्चर्य की बात है, निंदा की बात मैं नहीं करना चाहूंगा, महामहिम के बारे में कौन निंदा की जुर्रत कर सकता है, जुबान काट दें । खैर इसको छोड़िए, दर्द जरूर हैं मैं अपने फफोले दिखा रहा हूं। मैं केवल कृषि के बारे में बात नहीं कर रहा हूं स्वामीनाथन ने कहा कि कृषि विश्व में सबसे जोखिम भरा धंधा हैं । पं.जवाहर लाल नेहरू ने तीस साल पहले कहा था all things can wait but not agriculture. मैं मान्यवर,इतना ही कहूंगा all things can wait but nor rural development रूरल डवलपमेंट को आप जैसा महारथी जो अर्जुन से ज्यादा क्षमता रखता है, आगे बढ़ाएगा, मुझे इसमें ज्यादा संदेह नहीं हैं । एन.आर.ई.जी.एस. एक ऐतिहासिक कदम हैं । मैं इसका प्रशंसक हूं । राजस्थान में एन.आर.ई.जी.एस. सक्सेसफुल हुआ हैं । आपने खुद ने प्रश्न रखा है कि शायद भारतवर्ष में नम्बर-एक है । इम्प्लीमेंटेशन में जगह-जगह खोट हैं, कमियां हैं, जो आप डील कर रहे हैं, पूछने का सवाल है कि आज जो एन.आर.ई.जी.एस. हटालें, हटा दें, तो क्या 604 डिस्ट्रिक्ट्स में फायदेमंद होगा । एन.आर.ई.जी.एस. होनी चाहिए लेकिन become in certain places a cesspool of corruption. That corruption must be eliminated by an iron hand. A man can not do it, if he does not have a committed mind.

मैं इतना ही कहना चाहूंगा मैं लम्बी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि आपके पास समय कम हैं। लेकिन मैं यह जरूर निवेदन करूंगा कि ओस चाटने से प्यास नहीं बुझेगी, Something tangible has to be done.

उसमें पहली बात तो यह होनी चाहिए कि हमारे जी.डी.पी. का टोटल कितना परसंटेज हम खेती के डवलपमेंट में लगा रहे हैं। मान्यवर, इसके बड़े इंटरस्टिंग आंकड़े हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात है कृषि विकास की दर का गिरना, जो धीरे-धीरे 2.2 पर आ गई है और इससे ज्यादा परेशानी की बात क्या है, मैं आंकड़े कोट कर रहा हूं। 2007-08 के आंकड़ों में कहा गया है कि कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश 2002 के दस फीसदी से घटकर 2006-07 में 5.8 फीसदी रह गई है। अगर निवेश घटता गया, कृषि का योगदान घटता गया लेकिन लोगों की संख्या 70 करोड़ की रही, तो यह सुनिश्चित है कि इसमें गरीबी आएगी। यह क्या किसी तरह से दूर नहीं की जा सकती। निवेदन है कि कृषि में निवेश बढ़े-नम्बर-1, और नम्बर-2, एश्योर करें कि जो उत्पादन है उस उत्पादन का सही दाम मिले,उसको सही दाम नहीं मिलता। वह दाम जो उसकी मजदूरी को काट करके मुनाफे का दाम हो, जो स्वामीनाथन कमेटी ने रिपोर्ट किया है। आप कितना ही इन-पुट कर दो, आप कितने ही फायदे दे दो, अगर उत्पाद का सही दाम नहीं दिया,तो कृषि घाटे का धंधा रहेगी, कृषि धोखे की एक चीज़ रहेगी, कृषि एक छलावा रहेगी। इसके बारे में आप कुछ करिए। जब कृषि में कामयाबी होगी तभी बेरोजगारी दूर होगी। कृषि मूल और कुंजी है, इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। उसको सही बीज चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको खाद चाहिए। मेरे पास लम्बे-चौड़े आंकड़े है, मैं ज्यादा आंकड़ों की बात नहीं करूंगा। उसको नॉन-फार्म एम्पलायमेंट भी चाहिए, क्वालिटी ऑफ सीड के बारे में, सर,मैं एक मिनट लूंगा। "Funded by Union Ministry of consumer Affairs, the study conducted by CCS, Haryana Agricultural University, Hissar, shows that 41.3 per cent of farmers had problems in getting the desired variety of seeds; in Punjab, 41 per cent farmers." यहां, बहुत अच्छा सीड का सिस्टम है। फर्टिलाइजर के आंकड़े भी इसी तरह से हैं। पीने के पानी के आंकड़े बड़े अजीब हैं और वे यह दिखाते हैं कि गांव के अंदर या तो bacterial contamination है या nitrate contamination है या salinity है या arsenic है। Arsenic के रूप में लोग बंगाल और बिहार में जहर पीते हैं, लाखों आदमी है—करोड़ों हो, तो भी गलत बात नहीं होगी। जहां तक सवाल हैं —floride "nearly 60 million in 20 indian states are at risk of excessive fluride in their water. मैं राजस्थान के बारे में जानता हूं,

उपसभाध्यक्ष(श्री उदय प्रताप सिंह): डा. ज्ञान प्रकाश पिलानिया जी, आप कितना समय और चाहेंगे ?

डा. ज्ञान प्रकाश पिलानिया: जब आप कहेंगे मैं फौरन बंद कर दूंगा, क्योंकि मुझे एहसास हैं कि मेरी बात शायद आपको ज्यादा सारगर्भित नहीं लग रही।

उपसभाध्यक्ष(श्री उदय प्रताप सिंह): नहीं, बड़ी सारगर्भित है, लेकिन समय की पाबंदी हैं। आपने बहुत अच्छा पांइट बनाया हैं।

डा. ज्ञान प्रकाश पिलानिया: सर,मैं इतना ही कहूंगा कि हमको यह निश्चित करना चाहिए कि किसान को उसका हक मिले और किसान जिंदा रह सके, वह खुदकुशी न करे। किसान का खुदकुशी करना हर व्यक्ति के लिए लानत है, देश के कर्णधारों के लिए लानत है, इस राज्यसभा के लिए भी लानत है और नेताओं के लिए भी लानत है। यह किसी तरीके से बंद होनी चाहिए। मैं इस बारे में इतना ही कहूंगा-आप एक बड़े सह्रदय कवि है, आप इसको महसूस करेंगे।

हर उस खोशा-ए-गंदुम को जला दो, साहिर लुधियानवी ने कहा है-
हर उस खोशा-ए-गंदुम को जला दो, मान्यवर डा.रघुवंश प्रसाद जी,
हर उस खोशा-ए-गंदुम को जला दो,
जिससे दहकां को मयस्सर न हो रोटी।

दहकां, को जिससे खेती करने वाले को रोटी न मिले, उस गंदुम का शाख का फायदा क्या है? अच्छा है उस खेत को जला दो। मैं अंत में एक ही बात कहूंगा। मान्यवर, मेरा मकसद हंगामा पैदा करना नहीं। मैं दुष्यंत के शब्दों में कहूंगा, मेरा मकसद है कि हालात बदलें, मेरा मुद्दा है कि हालात बदलें, हिमालय सी हो गयी हैं भारी पीर अब तो गंगा बहनी चाहिए, मेर मन में न सही, तो रघुवंश प्रसाद जी साहब, आपके मन में तो आग जलनी चाहिए। हो कही भी आग, लेकिन आग

जलनी चाहिए । तभी रूरल डेवलपमेंट होगा और मुझे आशा है, आप एक प्रगति की नई ज्वाला जलायेंगे, उसमें विकार भस्म हो जायेंगे, उसमें करप्शन भस्म हो जायेंगे और एक नई गंगा विकास की बहेगी । धन्यवाद ।

उपसभाध्यक्ष (श्री उदय प्रताप सिंह): डा. ज्ञान प्रकाश पिलानिया जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । कुमारी निर्मला देशपांडे जी ।

कुमारी निर्मला देशपांडे (नाम-निर्देशित): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद । मेरे पूर्व साथियों ने जो-जो कहा है, उसमें से बिना कुछ दोहराये चंद शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करूंगी । यह जो ग्रामीण रोजगार गांरटी स्कीम है, यह देश के, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की क्षमता वाली योजना हैं । लेकिन वह क्रांतिकारी क्षमता प्रकट होगी, किस तरह से उसका क्रियान्वयन होता है, इस पर । इसीलिए मैं इसी के संबंध में कुछ बातें कहना चाहूंगी, नाम लिए बगैर, क्योंकि देश के सभी जिलों में हमारे साथी काम करते हैं । एक जिले में कलैक्टर के सामने हमारे ग्रामीण साथियों को बड़ी तादाद में धरना देना पड़ा कि एक अप्रैल से योजना लागू होने वाली हैं और ग्रामीण क्षेत्र में अभी तक इसका कुछ अता-पता ही नहीं हैं ।

[**उपसभाध्यक्ष** (प्रो.पी.जे.कुरियन)**पीठासीन हुए**]

इसके परचे छपवाकर बंटवाने की आपकी जिम्मेदारी हैं । अगर आपके पास बांटने वाली योजना न हो तो हम लोग बांटेंगे, पर परचे तो दिलवा दीजिए । जब योजना लागू होने वाली थी, आठ दिन पहले यह कहना पड़ा । किसी प्रदेश के एक और जिले में जब ग्रामीणों ने कलेक्टर से पूछा, शायद आदिवासी क्षेत्र का जिला था, तो उन्होंने कहा कि हमको ऐसी योजना की कोई जानकारी नहीं है । एक जगह जब यह कहा गया कि लोगों को पूरा काम क्यों नहीं मिल रहा है, तो कहा गया कि उन्होंने काम मांगा कहां हैं ? उन गरीब ग्रामीणों को पता ही नहीं था कि काम मांगना होता है, तब मिलता है । इन्हें जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने काम नहीं मांगा । मैं इसमें यही निवेदन करना चाहूंगी कि जानकारी पहुंचाने के काम में स्वयंसेवी संस्थाओं की निःशुल्क मदद ली जाए और इसके लिए अनेकों कार्यकर्त्ता तैयार है । इसी के साथ मैं चंद बातें ये कहना चाहूंगी कि पूरे सालभर में सभी जगह मिट्टी का काम नहीं दिया जा सकता है । क्या काम दिया जा सकता है इसकी जो सूची है, उसमें कुछ चीजों को शामिल करना बहुत जरूरी है । हम जानते हैं कि कृषि के बाद यह हथकरघा, हैंडलूम का क्षेत्र है, जो बहुत लोगों को काम देता रहा है, लेकिन आज उस क्षेत्र में भी आत्महत्याओं की नौबत आ रही है हम क्यों न हैंडलूम को इसमें शामिल करें, वह किस तरह से होगा, क्या होगा, बैठकर बात कर ली जाए । हैंडलूम के साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि पूरे खादी ग्रामोद्योग का जो क्षेत्र है, जिसके बारे में अभी एक सज्जन ने बहुत अच्छी बात कही है कि घर में बैठकर ही लोगों को काम मिल सकता है । उसको भी क्यों नहीं शामिल किया जा सकता है, तो खादीग्रामोद्योग, हैंडलूम आदि को इसके अंतर्गत शामिल किया जाए, तो लोगों को जब चाहे काम मिल सकेगा, पूरा काम मिल सकेगा और इस योजना का सबको पूरा लाभ प्राप्त हो सकेगा ।

इसी के साथ मैं एक और प्रयोग की जानकारी देना चाहती हूं, जो कृषि से संबंधित है । हमारी एक संस्था के कार्यकर्त्ताओं ने करीब चार सौ गावों में महिलाओं को स्वयं सहायता समूह, सैल्फ हैल्प ग्रुप्स के जरिए गाय दिलवाई और कहा कि आप यह जैविक खाद बनवाइये । वहां की महिलाओं ने जैविक खाद बनाने का काम शुरू किया, आज संस्था उसे खरीदती है और फिर उसे दूसरों को बेचती है । यह जो जैविक खाद बनाने का कार्यक्रम है, यह खेती के उत्पादन बढ़ाने में भी बहुत काम आएगा और घर बैठे लोगों को काम मिल सकेगा । मैं इसको भी इसमें शामिल करना जरूरी मानती हूं । हम इसके सफल प्रयोग कर चुके हैं । इसी के साथ जो बहुत कम जमीन वाले गरीब लोग है, जो अपने खेत में कुछ काम करें, तो क्या उनको इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है । क्यों नहीं किया जा सकता है, इस पर भी जरूर सोचा जाए, क्योंकि आखिर देश की जमीन में वे काम कर रहे हैं । उनको कुछ काम करने से कुछ न कुछ मिल रहा है, जिससे वे भूख की कगार पर नहीं पहुंचेगे । मैं इनको भी शामिल किया जाना आवश्यक मानती हूं । इसी के साथ इस किस्म के और भी लोग हैं । हर प्रदेश की परिस्थिति अलग है, मौसम अलग है, उसको देखते हुए क्या-क्या ऐसे काम हो सकते है, जो इस योजना में शामिल किए जाएं, ताकि हर किसी को, जिसको रोजगार की आवश्यकता हैं, उसको रोजगार प्राप्त हो सके और उसको भूख से मरने की नौबत न आ सके । इस दिशा में अवश्य सोचा जाए । मेरा मंत्री जी से निवेदन हैं कि इस सोच कर एक नई सूची बनाई जाए । उसी के साथ तुरन्त उसकी जानकारी सब कलक्टरों के पास पहुंचाई जाए, नहीं तो सूची जारी होने के साल भर बाद भी वे कहेंगे कि हमें कोई जानकारी नहीं है । ऐसी नौबत न आए । इसमें जो स्वैच्छिक संस्थाएं हैं,

एनजीओज हैं, उनका पूरा सहयोग लेने की कोशिश की जाए, ताकि सब मिल कर इस योजना को पूरी तरह से क्रियान्वित करने में सफल हो सकें और देश के ग्रामीण क्षेत्र की शक्ल को बदलने में कामयाब हो सकें। धन्यवाद। जय जगत।

श्री राजनीति प्रसाद(बिहार)ः धन्यवाद, सर। कुछ दिन पहले मैंने मंत्री जी के साथ रूरल डेवलपमेंट स्कीम और नेशनल रूरल एम्प्लायमेंट गांरटी स्कीम के बारे में ज़िक्र किया था, तो उन्होंने कहा था कि आप मुझे एक पत्र लिखिए। मैंने तीन-चार पन्ने का एक पत्र लिखा और मंत्री जी बता रहे हैं कि उनको पत्र मिला ही नहीं। उस पत्र में मैंने इनके निर्देशानुसार, यह निर्देश सिर्फ मुझे नहीं था, सब लोगों के लिए था कि आपके इलाके में जो डेवलपमेंट हो रहा है, आपके इलाके में ब्लॉक आफिस में नेशनल रूरल एम्प्लायमेंट गांरटी स्कीम के तहत जो काम हो रह हैं, सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो काम हो रहे हैं या ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो काम हो रहे है, उनके बारे में आप जांच करके बताइए। उन्होंने सब लोगों को लेटर लिखा, कई बार लेटर लिखा। अभी भी हम लोगों के पास एक लेटर आया है। उसके तहत हम लोगों ने बिहार के करीब दर्जनों ब्लॉक्स में, हमने और कई लोगों ने भी, जिन लोगों का भी इंटरेस्ट था, गांवों में जाकर देखने का काम किया। मैंने देखा कि एम्प्लायमेंट गांरटी योजना के तहत जो काम हो रहे हैं, उनसे गरीबों के अन्दर एक नई आशा की किरण को मैंने झलकता हुआ देखा है। जो लोग बाहर जाकर रिक्शा चलाते थे, बाहर जाकर पंजाब में रहने का काम करते थे, उनको भी दो-तीन महीने ही काम मिलता था। वे लोग अब उधर से पलायन करने का काम छोड़ कर वहां रहने का काम करते हैं। हमने यह देखा हैं कि गरीब लोगों को काम किस तरह मिल रहा है और किस तरह वे लोग थोड़ा सा रोजगार पाने के लिए मेहनत कर रह है।

उपसभाध्यक्ष जी, एक ही दिन में सब काम नहीं होता है। पहले हमारे पूर्व की सरकार ने भारत शाइनिंग की योजना बनाई थी। भारत शाइनिंग क्या हुआ, उसके बारे में आपको मालूम है। लेकिन हम लोगों ने भारत निर्माण का काम किया। इस कार्यक्रम में हम लोगों ने अच्छे-अच्छे काम किए हैं। मैं यह केवल प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूं। आप गांवों में जाकर देखें। हमारे जो लोग है, उनको गांवों में जाकर देखना चाहिए। गांवों में इस तरह के जो कार्यक्रम चले हैं, उसमें बहुत परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन इस मायने में हुआ हैं कि जो नौजवान लोग बाहर काम करते थे, जो गरीबी की जिन्दगी जीते थे, उनको कुछ राहत मिली हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उनको सारी राहत मिल गई। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि रोजगार गारंटी योजना सब दिन के लिए होनी चाहिए।

एक दूसरी बात, जो मैं कहना चाह रहा हूं कि अभी भी ग्राम में एक बहुत आवश्यक चीज है, जिसके बारे में कई लोगों ने चर्चा की है, लेकिन मैं भी इस पर चर्चा करना चाहता हूं। वहां पर शौचालय की व्यवस्था नहीं हैं। हमारे ग्रामीण मंत्री साहब ने जो स्कीम दी है, अगर वहां पर ग्रामीण शौचालय की व्यवस्था हो जाए, तो बहुत उत्तम होगा, जैसा कि अभी श्रीमती वृंदा कारत जी ने भी कहा है कि यह महिलाओं के सम्मान की बात हैं। जब हम लोग ग्रामीण इलाकों से चलते हैं, खास तौर पर रात्रि में कहीं जाते हैं तो कभी-कभी तो हम लोगों को अपनी आंखें मूंदनी पड़ती हैं और वह स्थिति बड़ी दर्दनाक होती है। जब कभी बाढ़ या बरसात की समस्या आती है, उस वक्त तो हम लोग सड़क के किनारे चल भी नहीं सकते हैं, वहां से गाड़ियां निकल नहीं सकती हैं।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि आपके सारे डेवलमेंट ठीक है, आपका रोजगार गांरटी कार्यक्रम ठीक है, अच्छा काम हो रहा है, सर्वशिक्षा अभियान भी ठीक है, वह भी अच्छा काम हो रहा है, लेकिन एक काम आप और करिए कि आप कुछ ज्यादा उदार बनिए। सरकार में आप जो काम कर रहे हैं, उसमें कुछ और उदार बनिए और उदार बन कर एक बार में कुछ हजार करोड़ रूपया दीजिए ताकि ग्राम वासियों के लिए कम से कम शौचालय की व्यवस्था हो सके, जिससे कम से कम हमारे यहां की महिलाओं को सड़क के किनारे इस तरह का काम न करना पड़े। आप इसके बारे में जरूर सोचिए। हम केवल सोचते हैं, विचार करते हैं और सोच-विचार करके आपसे यह कहना चाहते हैं कि अगर यह काम हो गया तो हमारे ख्याल से यह एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। पूरे हिन्दुस्तान में इससे आशा की एक नई किरण फैलेगी।

एक बात मैं और भी कहना चाहता हूं। कई लोगों ने यह बात कही हैं कि लैंड डेवलमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे यहां पर बीज की कमी है, हमारे यहां पर पानी की कमी है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कमी केवल चार साल के अन्दर पैदा नहीं हुई है। हम लोगों के यहां तो यह स्कीम ही नहीं बनती थी, हम लोगों ने इस प्रकार की स्कीम बनाने का काम किया है। हमारा जो बजट है, उस बजट में भी हम लोगों ने कहा है कि हर गांव में हम एक बड़ा सा गड्ढा खोदेंगे, ताकि उसमें पानी रिजर्व हो सके, जिससे जो ग्राउंड वाटर है, उसमें कुछ नमी आए और जमीन से पानी निकलने का काम हो सके। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पानी की जो समस्या है, वह बहुत गंभीर समस्या हैं

मंत्री जी, एक बात की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपके जो नल गढ़े जाते है, वह नल कहीं 50 फीट पर गढ़ते हैं, कहीं 100 फीट पर गढ़ते हैं, जबकि उसके लिए पैसा डेढ़ सौ या दो सौ फीट की गढ़ाई के लिए लिया जाता हैं । वहां पर जो नल गढ़े जाते हैं, उस पर आप ध्यान रखिए । नल गढ़ने के अलावा वहां पर जो कुंए खोदने के मामले, कुओं के रख-रखाव के मामले, यह सब बंद हो गया है । इस पर भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं और वह यह हैं कि ग्रामीण विकास हम तभी कर सकते है, जब हम लोग, जो यहां बैठे है, उस पर थोड़ा ध्यान दें । हमारे यहां पर पैसा तो चला जाता है, निर्मल जल योजना के लिए भी पैसा जाता है, लेकिन हमें उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा । हमारे राजपाल जी ने अभी यहां कहा कि हमको मीटिंग में नहीं बुलाते हैं, तो मीटिंग में तो हमको भी नहीं बुलाते हैं । हमें यहां पर आए दो साल हो गए, हमें याद नहीं कि हम कभी मीटिंग में गए हो, या कभी कलेक्टर ने कभी हमको नोटिस दिया हो । लेकिन अगर आप अपने ब्लॉक में जाएंगे और उनको कहेंगे कि हम आपकी इस स्कीम को देखना चाहते है, तो हमारे ख्याल से हमारी सरकार की यह योजना सफल हो सकेगी । पार्लियामेंट के मेम्बर अपने क्षेत्र में जा करके इस काम को करने का काम करेंगे, उसे देखने का काम करेंगे तो सरकारी मशीनरी भी कार्यशील होगी, वे लोग अच्छी तरह से अपना काम करने लगेंगे । मंत्री महोदय ने भी यही कहा है और सब लोगों को लैटर भी लिखा हैं कि आप लोग अपने-अपने इलाके में केन्द्र से संचालित जो योजनाएं है, कम से कम उसे देखने का काम करें, उस पर काम करने का काम करें, गांव में घूमने का काम करें ।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं स्वंय ऐसे कई गांवों में गया और ब्लॉक डेवलेपमेंट ऑफिसर के साथ, वहां के इंजीनियर के साथ वहां पर घूमने का काम किया । मैंने देखा कि आपकी जो इम्प्लॉइमेंट स्कीम है, वह अच्छी चल रही हैं, जो सर्व शिक्षा अभियान हैं, वहां भी अच्छे काम हो रहे हैं । सर्व शिक्षा अभियान के संबंध में एक बात और हैं कि गांव के स्कूलों में जो मिड डे मील दिया जाता है, उसके बारे में आप सोचिए और विचार करिए क्योंकि वह बहुत ही रद्दी किस्म का होता हैं । हमारे ख्याल से कहीं-कहीं तो वे अच्छे होते हैं, लेकिन हमें जहां तक देखने को मिला है, हमको लगता हैं कि वह अच्छा नहीं बनता है, तो उसके बारे में भी कुछ नयी सोच और नयी बात होनी चाहिए । आपने जो ग्रामीण सड़क योजना बनाई है, वह भी अच्छी हैं ।

अंत में मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि सबसे अच्छी बात जो हुई है, वह इन्दिरा आवास की हुई है । इन्दिरा आवास में सबसे खूबसूरत बात क्या हैं? जैसा कि हमारे यहां के एक सदस्य ने कहा कि वहां रूपया में से चार आना पैसा ही जाता हैं । लेकिन इन्दिरा आवास में मैंने देखा कि वहां 4 आना ही नहीं, बल्कि 16 का 16 आना जाता है। वहां कोई करॅप्शन नहीं हैं । इसलिए नहीं है कि ....(**व्यवधान**).... मैं वह बता रहा हूं, मुझको बोलने दीजिए । ....(**व्यवधान**)....मुझको बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोल लीजिएगा । वहां जो ग्रामीण आवास बनते हैं, उनमें किसको-किसको आवास मिलना है, आप उसका नाम बता दीजिए । किसको-किसको मिलना है ....(**व्यवधान**).... हां, आप उसकी परमार्नेट लिस्ट बना दीजिए और उसे सरकार को भेज दीजिए । सरकार क्या करती है कि वह बैंक में पैसा जमा कर देती हैं । आप बैंक में जाकर निकाल लें । मैंने कम-से-क्म 100 लोगों से पूछा कि क्या आपको इसमें पैसा लगा । वे बोले कि नहीं, मैंने बैंक से पैसा निकाल लिया है, हमसे एक पैसा नहीं लिया गया । वे 24 हजार रुपये देते हैं और 24 हजार में से 24 हजार रूपए उनको मिलते हैं । मैंने कई लोगों से क्रॉस-चेकिंग भी किया और पूछा कि आपको 24 हजार से कुछ कम पैसा लगा है या आपको कुछ करॅप्शन दिखाई पड़ता है, कुछ घूस-वगैरह देना पड़ा ? इस पर उन लोगों ने कहा कि हमको बैंक से पैसे निकालने में कोई असुविधा नहीं होती है, हमारे पास चेक होता है, हमारे पास फॉर्म होता है, इसलिए यह एक अच्छी स्कीम है । अच्छी चीजों के बारे में थोड़ी बड़ाई भी तो करिए, नहीं तो सब जगह आप लोग ऐसे ही बोलेंगे । मैंने कम-से-कम 100 आदमियों को देखा है और उनका इंटरव्यू लिया है । सर, मैंने देखा है और पाया है ...(**समय की घंटी**)....कि इसमें कोई भी गड़बडी नहीं हैं, क्योंकि ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि 4 आने नहीं, एक रूपया का एक रूपया ही मिले । ...(**समय की घंटी**)....एक मिनट, सर । इसके बारे में एक और बात कह कर मैं समाप्त करूंगा ।

सर, इसमें निर्मला देशपांडे जी ने एक अच्छी बात कही हैं कि केवल मिट्टी के काम से ही काम नहीं चलेगा । उसमें भी एक बात यह है कि अगर मिट्टी का काम और कोई दूसरे काम देंगे, तो कई ऐसे काम होते है, जो गांव में नहीं होते है । इसलिए जो मिट्टी का काम है, जो पुल-पुलिया बनाने का काम है, जो सड़क बनाने का काम है और जो टैंक को ठीक करने का काम होता है, वह easily available हो जाता है । अगर आप इसमें ज्यादा नुक्स लगाएंगे, तब उसमें जो बेरोजगार लोग है, नौजवान लोग है, उनको काम नहीं मिलेगा । उसमें थोड़ा सुधार जरूर होना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि आप एक स्कीम बनाइएं । वृंदा जी ने भी इस पर विचार किया है ....(**व्यवधान**)....

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Yes, yes. Please ... {*Interruptions*]हो गया ?

श्री राजनीति प्रसाद: एक मिनट, सर ....(**व्यवधान**)....वृंदा जी ने एक विचार दिया है। मैं उस पर सिर्फ जोर लगाकर यह कहना चाहता हूं कि एक ऐसी व्यवस्था करिए ताकि ग्राम में रहने का मन करे, लोगों को वहां जाने का मन करे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप वहां शौच की व्यवस्था तथा पानी की व्यवस्था निश्चित रूप से करिए, तब हम लोग भी जाकर वहां रहें और देखें। डाक्टर भी वहां जाएं, रहें और देखें। वे तो वहां जाते ही नहीं हैं। उनको भी अगर लोटा लेकर बाहर जाना पड़ेगा, तो शहर का कोई आदमी वहां नहीं जाएगा। इसलिए, सर, इस पर मैं विशेष बात कहना चाहूंगा। मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि शौच की व्यवस्था एकदम इंटरलिंकिंग व्यवस्था की तरह होनी चाहिए। वह एकदम ऐसा होना चाहिए कि अब कोई भी रात्रि में सड़क पर दिखाई नहीं पड़े और सुबह में भी सड़क पर दिखाई नहीं पड़े। वहां केवल आपने नारा लिखा है कि हम वहां शादी नहीं करेंगे, जहां शौचालय नहीं होगा, लेकिन आप देखिएगा कि आपकी शौच की व्यवस्था अच्छी नहीं है ...(**समय की घंटी**)...और अगर आप शौच की व्यवस्था ठीक नहीं करेंगे, तो फिर हमारा जो रूरल डेवलपमेंट है, गांव का जो विकास है, वह ठीक से नहीं होगा।

अंत में, सर, मैं एक शब्द इन्दिरा आवास योजना के बारे में कहना चाहता हूं कि "बोरियां ओढ़ कर जो बिलखते रहे, रात भर का उन्हें ठहर तो हुआ"। उनके पास एकदम मकान नहीं था, कुछ भी नहीं था। वे झोपड़ी में रहते थे, गाछ के नीचे रहते थे। इन्दिरा आवास ने एक बड़ा क्रांतिकारी काम किया है। "बोरियां ओढ़ कर जो बिलखते रहे, रात भर का उन्हें छत तो मिला, ठहर तो हुआ "। यही कहकर मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा कि शौच की समस्या के बारे में आप जरूर सोचिए, क्योंकि इसके बारे में अगर आप सोचेंगे तो एक नया भारत बनेगा, नए भारत का निर्माण होगा। यही एक समस्या हैं, जिसको हम अभी तक दूर नहीं कर पाए। धन्यवाद।

श्रीमती विप्लव ठाकुर: माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मुझे आज इस बात की बहुत खुशी है कि पूरा हाऊस इस बात की चिंता में हैं कि ग्रामों और ग्रामवासियों का सुधार कैसे हो। आज ग्रामीण विकास मंत्रालय के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और जो उनकी स्कीम्स हैं, कार्रवाइयां हैं, उनके बारे में आज हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं।

महोदय, मैंने सभी के विचार सुने और यहां तक भी कहा गया कि कुछ नहीं हुआ है। मैं यहां बैठे सांसद महोदय से पूछना चाहती हूं कि क्या देश की आजादी के पहले के गांव उन्हें याद हैं? क्या उनको दो बीघा जमीन, गबन और गोदान का साहित्य और उसकी गूंज मालूम हैं? क्या वे जानते हैं कि उस समय का गांव कैसा था, उस समय के लोग, उस के गांववासी कैसे जीते थे ? आज ये कहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है। हां नहीं हुआ, लेकिन उपसभाध्यक्ष जी, वहां नहीं हुआ, जहां भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू नहीं किया गया। आज यह बात सबसे बड़ी सोचने की है और मैं कहना चाहती हूं कि यह सारा हाऊस इस बात को सोचे कि इतने सालों तक इतना कुछ करने के बावजूद भी आज गांवों की और गांववासियों की दशा क्यों नहीं सुधरी हैं। उपसभाध्यक्ष जी, जहां पर भूमि सुधार हुआ है, चाहे वह पंजाब हो, हरियाणा हो या हिमाचल प्रदेश हो, आज वहां के गांवों में और ग्रामीणों में विकास हुआ है, उत्थान हुआ है और वे आगे बढ़े है। सबसे बड़ी बात यही है कि भूमि, जिसके सुधार और इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए हम इतनी स्कीम्स बना रहे हैं, का मालिक आज भी वही पूंजीपति है। पहले भी बेचारा गरीब खेत पर मजदूरी करता था, धूप में सड़ता था, बारिश में भीगता था, लेकिन उसे भर पेट अनाज नहीं मिलता था, उसका पेट भूखा रह जाता था, हालांकि आज हम कहीं ज्यादा आगे बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ करना है, किया भी है। जब से हमारा देश आजाद हुआ है, कई स्कीम्स आई है, इस देश के गावों और ग्रामवासियों के लिए सोचा गया है, क्योंकि भारत गांवों में बसता है और जब तक हम गांवों को ऊपर नहीं उठाएंगे, वहां की जनता को नहीं उठाएंगे, हम विकासशील देश नहीं कहला सकते। नेहरू जी के समय भी और इंदिरा जी के समय भी, जब उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, उस समय IRDP की स्कीम चलाई थी, जिसमें महिलाओं के लिए था कि वे अपना काम करें। मैं गांव में जाती थी, मैंने देखा था उन औरतों को, जो लकड़ी जलाकर काम करती थीं और धुआं उनकी आंखों पर असर डालता था, वहां उनके लिए स्माकलैस चूल्हें लाए गए। यह उस समय की क्रांति थी, यह उस समय का स्टेप था, क्योंकि उस समय उसकी जरूरत थी। इसके साथ-साथ उन्हें काम दिया जाता था, क्योंकि हमारा मानना था कि हमें गांव वालों को डिपेंडेंट नहीं बनाना हैं, हमें उनको अपने ऊपर निर्भर नहीं करना है, बल्कि उन्हें ऐसी स्कीमें देनी हैं, ऐसा इन्फ्रास्ट्रक्चर उनके लिए बनाना हैं, ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें और वे यह न सोचें कि हम भिखारी हैं और हमें गवर्नमेंट भीख में, दान दे रही है, बल्कि वे अपने आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से अपनी लड़ाई लड़े और आगे बढ़े। हमने ऐसी स्कीमें दीं।

उसी तरह की एक स्कीम बनाई गई है रोजगार गारंटी स्कीम। सबसे बड़ी बात क्या है, इतना कुछ कहा गया, यहां पर बताया गया कि इतना पैसा जाता है, राजीव जी ने भी यह कहा था कि एक रूपए में से गांव में, नीचे तक केवल 15 पैसे ही पहुंच पाते है, तो हमें यह देखना है कि ऐसा हो क्यों रहा हैं? बीच की वह कौन सी कड़ी है, जो इन चीजों को गांवों तक पहुंचने नहीं देती, हमें उसको identify करना है, उसके लिए कोई कुछ नहीं कह रहा है। मैं शरद यादव जी को बधाई देती हूं, जिन्होंने इस चीज को उठाया है स्कीमें बहुत है, पैसा बहुत है, मुझे याद है कि पहले गांवों के पास पैसा नहीं था, सड़कों के लिए पैसा नहीं था, पानी के लिए पैसा नहीं था, जब पहली बार गांवों में पानी के लिए स्कीम आई, तो शायद आपको मालूम नहीं होगा कि 10 घरों के लिए एक नलका होता था। यह काम वहां से शुरू हुआ था, मैं नहीं जानती कि बिहार में क्या स्थिति है, राजस्थान में क्या स्थिति है, लेकिन आज हिमाचल प्रदेश के गांवों में हर घर में नलका है, हर घर में टॉयलेट है और वहां तरक्की का एक सिलसिला चला हुआ है, क्योंकि वहां पर भूमि सुधार हुआ और उसके साथ- साथ लोगों का ध्यान इस बात की ओर गया कि खेती के साथ-साथ और क्या चीजें की जा सकती हैं। यहां पर माननीय सदस्यों ने बिल्कुल ठीक कहा कि हम आज पुरानी धुरी पर नहीं चल सकते हैं, आज हमें नयी चीजें लानी होंगी। यह जरूरी नहीं है कि महिलाएं जाकर गांवों की गलियां पक्की करें, तभी उन्हें wages मिलेंगे, यह जरूरी नहीं है कि वे सड़क पर काम करें, यह जरूरी नहीं कि वे बोझा उठाएं, उनके लिए और भी बहुत काम है, उनको वे काम देने चाहिए, ऐसी स्कीमें बनानी चाहिए। मंत्री जी, आप assets की बात करते हैं कि इसके साथ-साथ assets होंगे, लेकिन आप मुझे बताइए कि जो एक कच्ची सड़क बन गई है, वह कितने दिन चलेगी ? वह पहली बरसात में ही खत्म हो जाएगी, फिर वे आपके पास आ जाएंगे कि वह सड़क तो खराब हो गई है, हमें और पैसा दीजिए। आप वह स्कीम बनाइए, जो ज्यादा देर तक चले, लंबे समय तक चले, आप उसको शॉर्ट मत कीजिए कि आज हमने यह कर दिया है, आज हमने जो काम दिया, वह हो गया, उनको दिहाड़ी दे दी, उनकी गरीबी दूर कर दी, लेकिन आपकी assets नहीं बनीं, वे आपके लिए liabilities हो जाएंगी। जो कच्ची सड़कें बन रही है या कच्चे रास्ते बन रहे हैं, वे एक बरसात भी नहीं काटेंगे, विशेषकर जहां पर ऐसा मौसम है, मैं सूखे की बात नहीं कर रही हूं। इसलिए आप इसमें चेंज लाइए, आपके पास बहुत अच्छी स्कीमें है, उन पर बहुत काम हो रहा है, सर्व शिक्षा अभियान में बहुत काम हो रहा है। आज स्कूलों में 8वीं तक elementary शिक्षा जरूरी कर दी गई है, यह सर्व शिक्षा अभियान में आता है। स्कूलों की बिल्डिंगें बन रही है, प्लेग्राउंड बन रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह थी कि हमारी लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं थे, उनको भी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लाया गया, लेकिन मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये जो टॉयलेट बच्चियों के लिए बनने थे, अब इनको सर्व शिक्षा अभियान से निकाल दिया गया है, आप उनको दोबारा से इसमें include कीजिए, आप सभी स्कीमों को एक जगह रखकर यह काम कीजिए, ताकि overlapping न हो। इससे भी ग्रामीण विकास के रास्ते में मुश्किलें पैदा होती है, कठिनाइंया आती हैं। एक डिपार्टमेंट कहता है कि अब यह हमारे पास नहीं रहा है, आप किसी और डिपार्टमेंट के पास जाओ और गांव का प्रधान चक्कर ही लगाता रह जाता है।

दूसरी बात यह है कि ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना में जो कार्य होने हैं, उनकी सूची ग्राम सभा बनाती हैं। शायद आपको भी इसकी जानकारी होगी कि ग्राम सभा में पूरी योजना बनती है कि गांव में कहां रास्ता बनाना है, कहां कुआं बनाना है, कहां बावड़ी बनानी है। आज यहां पर पंचायत मंत्री भी बैठे हुए हैं, मैं बार-बार यह कहती हूं कि उस ग्राम सभा में कोरम कभी पूरा नहीं होता और सेक्रेटरी और प्रधान, जहां जरूरत होती है, वहां सूची नहीं बनाते हैं, जब कि रूरल इम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में यह जरूरी है कि जो सूची ग्राम सभा बनाकर देगी, वहां लोगों को लगाया जाएगा, वहां मजदूरी दी जाएगी। जब कई ग्राम सभाओं के कार्यो की सूची नहीं आती, तो वे कहते हैं कि DC के पास जाओ, वहां से सैंक्शन करवा दो, जो होता नहीं है। इसलिए इसको भी आप सरल बनाइए। आप इसे हर वार्ड में, हर पंचायत में प्रधानों के ऊपर भी मत छोड़िए कि जो कुछ करे, वह प्रधान ही करे। जो प्रधान है, वह खुद एक राजा की तरह बन जाता है, वह सोचता है कि जो मेरी खुशामद करेगा, जो मेरी जी –हुजूरी करेगा, मैं उसका काम करूंगा और वह यह भी देखता है कि इसने मुझे वोट नहीं दिया, मैं इसका काम नहीं करूंगा। इसलिए यह जो आपकी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, यह जो इतना बड़ा ऐक्ट है, जिसके लिए हमारे प्रधान मंत्री जी ने, हमारी UPA की चेयरमैन ने पूरा जोर लगाया है और सारे जिलों में इसे लागू कर दिया है, उसमें इन चीजों की वजह से कमी रह जाती है। इन चीजों को आप दूर कीजिए जिससे कि हर एक को रोजगार मिल सके, हर एक को काम मिल सके। उनकी अपनी जो स्थिति है, उसको वह सुधार सके। दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि आपने यहां पर wages की बात ठीक कही है, आप अपने तौर पर पूरे हिन्दुस्तान में इस-इस स्कीम के अंदर एक wages कीजिए। आप यह instruction दीजिए कि स्टेट की wages नहीं चलेगी, क्योंकि कहीं 75 रूपए

5.00 P.M.
है, कहीं 80 रूपए हैं, कहीं 100 रूपए हैं । आप इस बात को देखिए, जहां आपने रूरल मिनिस्ट्री में इतना किए हैं, वहां यह भी एक कदम उठाइए कि इस स्कीम के अंदर, इस गारंटी योजना के अंदर हर एक की wages चाहे वह 100 रूपए हो, 150 रूपए हो, चाहे कोई भी हो, उसे आप रखिए । इससे पूरे भारत में एक समान बात होगी । यह नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में क्या दे रहे है, मध्य प्रदेश में क्या दे रहे हैं, कर्नाटक में क्या दे रहे हैं या आन्ध्रा, जो अमीर स्टेट है, वह तो दे सकती हैं, लेकिन जो गरीब है, वह उतना wages नहीं दे सकती है। आप इसी में inbuilt रखिए, इसी में इस बात को रखिए कि इस योजना के अंदर, इस एक्ट के अंदर, चाहे 100 रूपए दिहाडी कीजिए, चाहे 150 रूपए दिहाड़ी कीजिए, पर सबको बराबर दीजिए, ताकि ऐसा न लगे कि इसमें भी भिन्नता हैं, इसमें भी अलग मापदंड रखे गए है । यह नहीं होना चाहिए ।

दूसरी बात मैं यह कहूंगी कि यह जो सड़कों की बात है, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की बात है, इसके रख-रखाव की बात है, शायद वृंदा जी को पता नहीं है कि जब यह सड़क बन जाती है तो जिस contractor ने यह सड़क बनाई है, इसके देखभाल की ड्यूटी उसी contractor की बनती हैं, क्योंकि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में जो पैसा sanction किया जाता है, उसमें यह बात है कि पाचं साल के लिए स्टेट नहीं बल्कि contractor देखभाल करेगा । मंत्री जी contractor कौन आता है, छोटे गांव का contractor नहीं आ सकता है, मध्यम वर्ग का contractor नहीं आ सकता है, जो ए-क्लास के contractor हैं, वही प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के ठेके लेते हैं । वह आपस में पूल कर लेते हैं और जो गांव में बैठा हुआ मजदूर है, उसको काम नहीं मिल पाता है । इसके बारे में भी ध्यान कीजिए कि यह जो contractor सिस्टम है, अगर हम ग्रामों की दशा सुधारना चाहते है, उन लोगों की उन्नति करना चाहते है, उत्थान करना चाहते है, तो इन चीजों पर भी ध्यान देना जरूरी हैं कि यह contractor सिस्टम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जो छोटे लोग है, छोटे पैमाने में काम करना चाहते है, उनको काम नहीं मिल रहा है। निर्मला देशपांडे जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि एक revolution ला दिया है, आज लोग घर में बैठकर विशेषकर महिलाएं घर में बैठकर कमा रही हैं । मैं एक गांव में गई, वहां एक बुजुर्ग औरत मुझे मिली, उसके हाथ में 2600 रूपए थे, वह उसे कभी ऐसे गिने तो कभी वैसे गिने । मैंने कहा कि आप क्या गिन रही हैं, वह कहती हैं कि मैंने पहली बार 2600 रूपया देखा है, मैं तो उस सरकार को प्रणाम करती हूं, उस यूपीए सरकार की चैयरमेन सोनिया गांधी को, डॉ. मनमोहन सिंह जी को, जिन्होंने यह योजना चलाई है, यह एक्ट बनाया, जिससे मुझे घर बैठे 2600 रूपए मिला है । क्यों गांव से लोग बाहर जाते हैं, आज प्रश्न यह भी हैं ।

श्री रघुनन्दन शर्मा: आप ग्रामीण मंत्री जी को नहीं कहते हैं ......(**व्यवधान**)....

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please, please. ...*(Interruptions)*... There is no time for this....*(Interruptions)*...

श्रीमती विप्लव ठाकुर: गांव से लोग क्यों बाहर जाते हैं, गांव से क्यों पलायन होता है ? रोजी, रोटी के लिए,कमाने के लिए पलायन होता है ...(**व्यवधान**)...

श्री रघुनन्दन शर्मा: यह बेचारा कुछ नहीं कर रहा हैं ....(**व्यवधान**)....

श्रीमती विप्लव ठाकुर: यह भी यूपीए सरकार के अंग है, यह अलग नहीं है । आप इनको अलग नहीं कर सकते हैं । यह उसी सरकार के मंत्री हैं। ....(**व्यवधान**)... **।**

श्रीमती विप्लव ठाकुर: मैं यह कहना चाहती हूं कि लोग गांव से बाहर क्यों जाते है, किस लिए जाते हैं, रोटी कमाने के लिए, अपने पेट की भूख मिटाने के लिए, अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए गांव से बाहर जाते हैं । यह जो हमारा ग्रामीण मंत्रालय हैं, जिसने ये स्कीमें बनाई है, मंत्री जी भी बधाई के पात्र हैं । इसमें उन्होंने उन सभी चीजों का ख्याल रखा है, यहां रोजगार का रखा है, वहीं घर का भी रखा है, शिक्षा का भी रखा है, सेहत का भी रखा है, पानी का भी रखा है और सिंचाई का भी रखा है । यही गांव में अगर हम पूरा कर सकेंगे, तो हमारे गांव ज़रूर खुशहाल हो जाएंगे । हमारी पहले की जो कहावत थी, उसको हम कर सकेंगे, पर इसके लिए एक ही बात करनी हैं कि आपको ब्यूरोक्रेसी को, जो इसको लागू करते है, आप स्कीमें बनाते हैं, आज हर राज्य में 75 प्रतिशत के लगभग पैसा केंद्र का जा रहा है, उन स्कीमों के द्वारा जा रहा है, जिसको वे लागू करते हैं और अपनी कहलाते हैं, लेकिन मंत्री जी, आपको यह देखना होगा कि monitoring के ऊपर और implementation के ऊपर ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा । आप चाहे राज्यों के

मुख्य मंत्री को या उनके जो मंत्री हैं, उन्हें महीने में एक बार बुलाइए या दो महीने में एक बार बुलाइए, उनसे फीडबैक लीजिए कि कहां, क्या हो रहा हैं? सबसे बड़ी कमी हमारी यही है कि यहां से स्कीमें बन जाती हैं, लेकिन वे लागू नहीं हो पाती हैं, इसलिए हम आज भी साठ साल के बाद फिद उसी बात के लिए कह रहे हैं कि हमें गांवों का कैसे सुधार करना हैं, गांववासियों की आर्थिक स्थिति कैसे सुधारनी हैं ? अगर हम implementation और monitoring को नहीं देखेंगे, तो हमारी बातें वहीं की वहीं रह जाएंगी, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now, Shri Tiruchi Siva. There is one more speaker after him, Shri Ram Narayan Sahu.

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, since this morning, my esteemed colleague, Shrimati Brinda Karat, who initiated this discussion, has given valuable suggestions. The Members who followed also deliberated interestingly.

Sir, the United Nations has projected that the real India will live in the rural outbacks for at least, 50 more years. Breaking the urbanisation myth, the projection report of the UN has said that though most of the countries in the world would see rapid urbanisation, India would have the largest rural population till 2050. Even in 2050, people who are going to reside in urban India would constitute only 55 per cent. In such a State of affairs, it becomes the bounden duty of the Government to give priority to rural development. Many measures have been taken, S ir. One among them is Bharat Nirman, which would put the required infrastructure in its place. But, at the same time, equitable growth is necessary. The employment engines have to be created for the rural India. And for that also, various measures are being taken. One is the Bharat Nirman Plus, which talks of expanding farming into livestock and changing of laws for the utilisation of the vast amount of wasteland in the country for cultivation of Jatropha and Pongamia plantations for producing bio-fuel. Sir, This would reduce the country's dependence on imported petroleum. Not only that, it would generate, or rather increase the rural income of India to Rs. 45,000 crores and would create job opportunities for 12 to 15 million people.

Sir, I would like to draw the attention of the hon. Minister here. This projection is for 2012 and it was conceived in October 2006. The proposal was processed with the Expenditure Finance Committee and on 8th March 2007, it was considered by the Cabinet Committee on Economic Affairs. Thereafter it was referred to the Group of Ministers for further examination and recommendations, During the year 2007-08, an outlay of Rs. 50 crores was earmarked for the National Mission on Bio-Diesel. However, no releases were made under this Head. Again, in 2008, the same amount has been proposed under the same Head. The Standing Committee when asked for the reason and wanted to know the logic for earmarking the outlay for the scheme, particularly when it was not utilised in the previous year, the reason given was, "as the Group of Ministers could not meet, therefore, the 2007-08 allocation of Rs. 50 crore could not be utilised on the Bio-Diesel Programme." The same reason has been given for the year 2008-09. I couldn't understand as to why for such a vital scheme the meeting of the Group of Ministers is not being convened. If it is delayed, how could the State Governments implement it? Sir, we are well-aware that this sub-continent is working on the principles of federal nature. The State Government has also got its responsibility. I belong to a regional party and my State has been appreciated many a times by the hon. Minister himself on the floor of the House as one of the best-performing States in implementing the rural development schemes. We have our promising young leader Shri M.K. Stalin as the Minister for Rural Development there. Sir, the NREG scheme is very successfully implemented there and the hon. Members here will be happy to know that 82 per cent of men or women and 59 per cent of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes were benefited

through this scheme in Tamil Nadu. I would also like to mention two other schemes which we have done th,ere. One is, Indira Awas Yojana Scheme. We have given Rs. 55,000 for every house instead of Rs. 37,000 which is allotted. Thus, we have given Rs. 18,000 more from the State Government in order to help those people who are constructing the house, Sir, every second child in this country, that is, 46 per cent of the children in this country, is mal-nourished. In order to bring down that level, many schemes were being implemented and the Government is recommending many more. But what we do is that we give the financial assistance of Rs. 1000 per month to every pregnant women, three months before delivery and there months after delivery, that is, Rs. 6000 for whom an income certificate is not must. That helps the pregnant women as well as the children who is even when borne by mothers and after they are born. So also, we have got new schemes like *Pudia Anna Marumalarchi Thittem* which gives a financial assistance of Rs. 20 lakhs to every Panchayat, other than its own revenue, to create basic amenities like sanitation, a library, a burial place or a cremation place, a playground and the watershed. The town Panchayat gets Rs. 50 lakhs in the same category. Also the PMGSY scheme which links two villages having more than 500 population is being implemented very well. Sir, it is the right time to record here or to recollect, when the economic sanctions were imposed on India when we had our Pokhran test, India was able to overcome only because of the relentless and tireless tailing of the farmers in the rural India. So, considering them and keeping in mind that the future India is going to have the most number of rural people even in 2050, this Government is taking measures to uplift the lives of those people who are in the rural areas. I would also like to request the hon. Minister that, as a token of encouragement, you should give more financial assistance to the States which are performing well and other States also. So, the State Governments require more financial assistance. I belong to a State and I belong to a party in Tamil Nadu which implements most of the schemes which have been recommended by the Central Government fully well. Thank you.

राम नारायण साहू (उत्तर प्रदेश)**:** बहुत-बहुत धन्यवाद उपसभाध्यक्ष जी । मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा ।

आज ग्रामीण विकास योजना के बारे में हमारे सभी साथियों ने अपने अच्छे-अच्छे विचार व्यक्त किए । हमारे देश की आजादी को 60 साल हो गए हैं और 60 साल के अंदर हम ऐसा नहीं कहेंगे कि काम नहीं हुआ हैं । लेकिन जिस तरीके से काम होना चाहिए था उस तरीके से काम नहीं हुआ । अगर हम अमेरिका का इतिहास उठाकर देखें तो हमारे सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि पांच सौ साल पहले उसकी क्या हालत थी और आज वह दुनिया का नम्बर एक बना हुआ है । हमारे बाद में जो देश आजाद हुए, और तब चायना की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है । हमारे यहां लोग केवल बतलाते हैं, सोचते है, भाषण देते हैं और योजनाएं बनाते हैं लेकिन इच्छा शक्ति की कमी होने के कारण उस काम को इम्पलीमेंट नहीं कर पाते । इंडिया टुडे मेग्जीन में 60 लोगों के बारे में निकला हैं कि उन्होंने किस तरीके से तरक्की की और कैसी की । अगर इन लोगों ने दिली इच्छा से उस काम को किया और एक लक्ष्य अपने सामने रखा और पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम किया तो उन्होंने वह लक्ष्य प्राप्त किया । किसी को यह बतलाने की जरूरत नहीं हैं कि किसने क्या किया । लेकिन देखें कि कहां से उन्होंने शुरूआत की थी और आज वे किस मुकाम पर है । तो उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के कारण ही उस मुकाम को हासिल किया । इसी तरीके से अगर हमारी सरकार इच्छा शक्ति रखे तो हम भी इस मुकाम को छू सकते हैं । जब अमेरिका आगे बढ़ सकता है, चायना आगे बढ़ सकता है तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं । पांच सौ साल कोई बड़ी चीज नहीं होती, 60 साल हमको भी हो गए हैं । यहां के कुछ लोग कहते हैं कि लोग पंजाब जा रहे हैं और कुछ वहां से वापिस आ रहे हैं । यहां हमारी एक बहन जी कह रही थी कि लोग गांव छोड़ करके शहर क्यों जा रहे हैं । बात यह हैं कि सही तरीके से योजनाएं बनाई जाएं और उनको सही इम्प्लीमेंट किया जाए । अभी बहुत बड़ा काम पड़ा हैं हमारे सामने भूमि सुधार योजना का । काम भी बहुत बड़ा है और जो हमारे यहां बेरोजगारी बहुत लम्बी-चौड़ी है, उस बेरोजगारी को दूर भी किया जा सकता है । काम दिखाई भी पड़ता है । लाखों नहीं करोड़ों बीघा जीमन बेकार पड़ी हुई है, जिस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है, कोई प्लानिंग नहीं बन रही हैं अगर इस पर ईमानदारी के साथ प्लानिंग शुरू कर दी जाए तो हमारे बेरोजगार लोगों को काम भी मिलेगा और हमो देश का सुधार भी होगा ...(**समय की घंटी**)...

अगर इतनी जल्दी घंटी बजा देंगे तो कैसे काम चलेगा, यह तो आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष(प्रो.पी.जे.कुरियन): समाप्त करें।

श्री राम नारायण साहू: मैं ब्रीफ में बात करना चाहूंगा। हर आदमी गांव से शहर नहीं जाना चाहेगा और शहर वाला आदमी जंगल में जाकर काम नहीं करना चाहेगा कि हम भूमि सुधार योजना में लगें। लेकिन अगर सौ रूपए मजदूरी बनती है और हम उसको दो सौ रूपया मजदूरी देंगे तो जरूर जाएगा। जब हम दूसरे कामों में सब्सिडी देते हैं तो हम लोगों का पेट भरने के लिए क्या इस तरह से सब्सिडी नहीं दे सकते। सूखी-सूखी सब्सिडी देने से काम नहीं चलेगा। हम काम भी लेंगे और देश को सुधारेंगे भी और लोगों का पेट भी भरेंगे।

उपसभाध्यक्ष(प्रो.पी.जे.कुरियन): बस अब आप समाप्त करिए।

श्री राम नारायण साहू: सर,मैं एक पाइंट बोलकर अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं चाहता हूं कि ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना जो बनाई गयी है, क्यों नहीं इसको पंचायती राज़ के साथ जोड़ा जाता है? अगर इसको इसके साथ में जोड़ लिया जायेगा, तो हम इसका बहुत-बहुत स्वागत करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती जया बच्चन: थैंक्यू सर। उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा बोलने का कार्यक्रम तो नहीं था, मगर इतने बुद्विजीवियों को यहां सुनकर और इतने experienced लोगों को यहां सुनकर मेरा भी थोड़ा-बहुत मन किया कि मैं कुछ बोलूं।

उपसभाध्यक्ष (प्रो.पी.जे.कुरियन): आप भी बुद्विजीवी हैं।

श्रीमती जया बच्चन: मैं तो बुद्विजीवी नहीं हू, मैं हृदयजीवी हूं। मेरा भी मन किया कि मैं कुछ थोड़े-बहुत अपने आब्जर्वेशन्स आपके सामने रखूं। सबको सुनकर ऐसा लगा कि इस देश के गरीब के लिए, गामीण जगह पर जो लोग रहते हैं, उनके लिए, महिलाओं के लिए इतने बड़े घर में सब इतनी चिंता कर रहे हैं, इतनी सद् भावनाएं हैं, तो हमारे देश में शायद गरीबी है ही नहीं। क्योंकि अगर इस घर में बैठकर 60 साल बाद, हम उसी बात पर डिसकशन कर रहे है, तो मुझे लगता है कि बहुत शर्म की बात है। सच कौन बोल रहा है और सच क्या है, यह मैं जानना चाहती हूं। मैं माफी चाहती हूं कि जो ग्रामीण जगहों पर रहते हैं, उनको experience ज्यादा है, शायद मुझे नहीं है, मगर मेरा आब्जर्वेशन यह है कि मुम्बई जैसे शहर में ग्राम और शहर साथ-साथ बसता है, जब हम शहर का डेवलेपमेंट नहीं कर सकें, तब हम ग्राम के डेवलेपमेंट की क्या बात करते हैं?

सर, मेरे हिसाब से गलती हैं कि हमने साहूकार के हाथ में चौकीदारी दे दी हैं। साहू साहब, आप मुझे माफ करेंगे। सर, मंत्री जी ने तो इस मंत्रालय को चार साल से सम्भाला हैं। इतने सालों में जब कुछ नहीं हुआ तो चार साल में आप जादू की छड़ी क्या घुमायेंगे ? मैं यह सोचती हूं, It is very important that we make you responsible people accountable. आप जो कर रहे हैं। मैं जानती हूं कि आप गरीबों के लिए जरूर सोचते है, ग्राम के ऊपर भी आपका ध्यान है, मगर आप से पहले जो इस कत्तर्व्य को सम्भाल चुके है, उनसे पूछिए कितना काम हुआ, कितनी प्लानिंग हुई ? अगर एक मंत्री का चार साल में दो बार पोर्टफोलियों बदल दिया, तो वह कहां ध्यान देगा, वह क्या-क्या करेगा ? वह अपनी कुर्सी सम्भालता हैं, उसे गरीबों का ध्यान नहीं है, उसको ग्राम के बारे में चिंता नहीं है, महिला तो *मैं गई। यह बहुत दुख की बात हैं। सर, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हूं जैसा कि मैंने पहले कहा-मैं हृदयजीवी हूं, इसलिए हृदय से बात करती हूं 1 Sir, there is a report that the Government schools in villages all'over India are 8,45000. इनमें 1,32,000 में ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी नहीं हैं I toilets were promised, and, out of that, we have been able to achieve below 50 per cent, that is, only 3,37,502 have been made so far. It is a very pathetic situation. There is a fantastic comment by the Standing Committee Report of 2007-08. It reads, "It is really reprehensible that the Government cannot ensure drinking water and sanitation facilities in Government schools in rural areas even after six decades of planned development, particularly when the Indian economy is making giant strides world-wide."

Sir, I thank you for this opportunity.

♦Expunged as ordered by the Chair.

सुश्री अनुसुइया उइके (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय रोजगार गांरटी योजना के संबंध में मैंने पिछले सत्र के दौरान माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया था। चूंकि मध्य प्रदेश एक आदिवासी बाहुल प्रदेश माना जाता हैं। वहां पर जो बहुत सारे आदिवासी लोग है, वे लघु वन उपज पर आधारित अपना निर्वाह करते हैं। उनका पूरा जीवन मजदूरी पर निर्भर रहता हैं। ऐसी स्थिति में वे हजारों की संख्या में दूसरे जिलों में पलायन करते हैं और इसके लिए मैंने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था कि आपने जो 100 की रोजगार गारंटी योजना लागू की है, वह उनके लिए पर्याप्त नहीं हैं। केवल आदिवासी क्षेत्रों के लिए 100 की जगह 200 दिन का रोजगार बढ़ाया जाए, तो ज्यादा अच्छा होगा।

SHRI GIREESH KUMAR SANGHI (Andhra Pradesh): Sir, we are fortunate that both the Urban Development and the Rural Development Ministers are here. The efforts of converting our rural areas into urban areas are highly applauded, particularly in our State of Andhra Pradesh where a lot of good schemes are going on for providing housing, drinking water, and employment. I want to draw the attention of the hon. Minister.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): One second. The word* used by Shrimati Jaya Bachchan is unparliamentary, so it is expunged.

SHRI GIREESH KUMAR SANGHI: Sir, when we say Grameen it does not only mean the farmer and the agriculturist, it has got many other components also. Like artisan community. Sir, these artisan communities are our backbone. They provide various services to the villages, particularly barber, blacksmith, goldsmith, kanu, teli, kalwar, etc. There are 50-60 such artisan communities in the rural areas, particularly in the State of Bihar. I have been going to Bihar also quite often. Their state of affairs is not at all good. There are no specific schemes for these artisan communities जो हमारे देहात में ये स्किल्ड वर्कर्स रहते है, स्किल्ड artisans रहते हैं, जो उत्पादन करते हैं, अगर हम उनके लिए न सोचें तो, अगर सोचें कि भारत ऊपर आ जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन से लोग ऊपर आ जाएंगे, तो असंभव हैं। क्योंकि हर गांव में आप देखेंगे कि जो इतने दिनों से सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, उन कम्युनिटीज को बिल्कुल नेगलेट किया गया है। उनके लिए कोई स्पेसिफिक स्कीम नहीं बनाई गई। महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि वे उनके लिए कोई स्पेसिफिक स्कीम बनाएं, ताकि वे भी अपनी कला का इस्तेमाल करें और ऊपर आ सकें।

इसके साथ ही साथ जो खुदरा व्यापारी हैं, छोटे-छोटे व्यापारी हैं, हलवाई हैं, कई तरह के छोटे-छोटे लोग हैं, जो अपने श्रम पर आधारित होते है, गवर्नमेंट पर आधारित नहीं होते है, अगर हम उनके बारे में भी सोचें और उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन, अभी नेशनल सर्वे रिपोर्ट आई हैं,92 percent are not included in our financial system. They don't have access to the financial facilities. जब तक हम इनको इंक्लूड नहीं करेंगे, इनको साथ लेकर नहीं चलेंगे, तो हमारा देश कभी ऊपर नहीं आएगा। महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि ...(**समय की घंटी**) सर, मैं सिर्फ दो मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। हमारे आन्ध्र प्रदेश में, खास कर हमारे तेलंगाना एरिया में फ्लोराइड की बड़ी समस्या हैं। पीने का पानी, पेयजल polluted है, fluoride affected हैं। मंत्री जी ने काफी प्रयास किया है, फिर ऐसे कई गांव बचे हुए हैं, जहां शुद्व पेय जल नहीं प्राप्त होता हैं। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि आन्ध्र प्रदेश, खास कर नलगोंडा जिला, जो हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के तहत भी हैं, रंगरेड्डी जिला, ख्म्मम जिला, महबूबनगर जिला और खास कर महबूबनगर जिले में, जहां से पहले जयपाल रेड्डी साहब रिप्रिजेंट करते थे, वहां से पलायन बहुत होता है, अभी भी बहुत पलायन होता है ....(**व्यवधान**)....

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Okay, That is enough. Now, please conclude.

SHRI GIREESH KUMAR SANGHI: Sir, just one minute.

उपसभाध्यक्ष (प्रो.पी.जे.कुरियन): ठीक हैं, हो गया।

श्री गिरीश कुमार सांगी: ठीक हैं, थैंक्यू सर।

'Expunged as ordered by the Chair.

श्री रघुनन्दन शर्मा: सर, मेरा एक प्वायंट ऑफ ऑर्डर हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि शहरी विकास मंत्री शहर के नागरिकों की चिन्ता करेंगे, वहां की व्यवस्था करेंगे, ग्रामीण मंत्री ग्रामीणों की चिन्ता करेंगे, लेकिन भारत में बहुत बड़ी आबादी ऐसी हैं,, जो न शहरों में रहती है, न गांवों में रहती है, जिनके पास न मकान है और कुछ नहीं है, जो घुमन्तु जातियां है, उनकी व्यवस्था कौन करेगा, उनके विकास की चिन्ता कौन करेगा ?

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now, all of you please listen to the reply. It was very good discussion. Everybody contributed very well. Now, everybody should listen to the reply.

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): उपसभाध्यक्ष महोदय, हम मंत्रालय की ओर से आसन के प्रति, आपके प्रति बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और सदन के सभी नेता के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि जब पांच विभागों का नाम तय हुआ, उनमें से ग्रामीण विकास को बहस के लिए चुना गया। इस उच्च सदन में जब ब हस हो और इतने विद्वान माननीय सदस्य जब रूचि लें, तो कोई कारण नहीं है कि देश में गरीबी और बेकारी बनी रहेगी और हमारा गांव पीछे छूट जाएगा। हमारा गांव जरूर विकास करेगा और समृद्धि आएगी। हम गरीबी और बेरोजगारी पर भी काबू पा सकेंगे। हम श्रीमती वृंदा कारत जी को धन्यवाद देते हैं। जब वामपंथी नेता बहस की शुरूआत करें और सभी लोग उसमें रूचि लें, तो इससे मुझे और विश्वास बढ़ता हैं कि गरीबी और बेकारी के खिलाफ जो जंग है, उस जंग में हम विजय हासिल करेंगे। इसमें कोई सन्देह नहीं हैं।

संक्षेप में, जब शुरूआत होती हैं कि सरकार का ग्रामीण विकास के लिए दृष्टिकोण क्या हैं ? महोदय, 10वीं योजना का आउटले 76 हजार करोड़ तय हुआ था, लेकिन जब अन्तिम में 3 वर्ष का मौका मिला तो उसको बढ़ाकर 1 लाख 14 हजार करोड़ रूपए खर्च हुए। आउटले 76 हजार करोड़, बजट प्रावधान में 48 फीसदी बढ़ोतरी हुई, योजनाकारों ने जो आउटले सोचा था। यह साबित करता हैं कि हमारा दृष्टिकोण क्या हैं। उसकी प्राथमिकता, ग्रामीण विकास, ग्रामीण समृद्धि, बेरोजगारी और गरीबी के खिलाफ और गांवों में सारी शहरी सुविधाएं दी जाएं, उनको इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिसटीज़ और सभी तरह की सहूलियतें दी जायें, उस तरफ हमारा जोर हैं। फिर 11वीं योजना का एक वर्ष हम बिता चुके हैं और दूसरे वर्ष में बहस चलाई जा रही हैं। हमने बजट प्रावधान वर्ष 2004-05 से 16 हजार करोड़ से शुरू किया। 2004-05 में 16 हजार करोड़, 2005-06 में 24 हजार करोड़, इसमें 53 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। 2006-07 में 31 हजार करोड़, 2007-08 में 40 हजार करोड़ का प्रावधान था, लेकिन हमने 42 हजार करोड़ रूपया खर्च किया है। इस साल 2008-09,जिसमें हम चल रहे हैं, इसका बजट प्रॉविजन 49 हजार 4 सौ करोड़ हैं, लेकिन 60 हजार करोड़ खर्च होगा। अभी तक 11 वीं योजना का 2 लाख 60 हजार करोड़ का आकार बनाया गया है, लेकिन हम इसका अन्त सवा तीन लाख करोड़ पर जाकर खत्म करेंगे। ऐसा हमारा लक्ष्य हैं, ऐसा हमारा दृष्टिकोण है, ऐसे सारे लक्षण मौजूद हैं।

श्रीमती वृंदा कारत जी ने शुरूआत करते हुए एनआरईजीए की चर्चा की। मैं एनआरईजीए से शुरूआत करता हूं। यह ठीक बात हैं कि एनआरईजीए हमारा फलैगशिप प्रोग्राम हैं। गरीबों को गांव में ही रोजगार मिले यह प्रसन्नता की बात होगी, लेकिन यह दावा कहीं भी नहीं किया गया कि इसी से गरीबी हट जाएगी। गरीबी हटाने की तरफ अवश्य यह एक मजबूत कदम होगा। गांव में वह गरीब आदमी, जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, वह जब मेहनत करेगा, तभी रोटी खा सकेगा, फूड सिक्योरिटी के माध्यम से उन्हीं लोगों के लिए NREGA कानून बनाया गया।

वेज इम्प्लॉइमेंट प्रोग्राम कोई नया प्रोग्राम नहीं है, जिसकी शुरूआत हमने ही की हो, वेज इम्प्लॉइमेंट प्रोग्राम तो देश में करीब तीस वर्षो से लागू हैं। पहले भी जब कभी अकाल पड़ता था तो रिलीफ हॉटमैन वाली स्कीम, लाइट मैन वाली स्कीम, फूड फॉर वर्क, NREP,RLEGP, इम्प्लॉइमेंट इंश्योरेंस स्कीम, जवाहर रोजगार योजना आदि विभिन्न नामों से यह चलता रहा हैं, लेकिन तब इससे नॉमिनल लोगों को ही रोजगार दिया जाता था। लेकिन अब कानून बना करके इसे मज़बूत किया गया हैं। बचपन में हम लोग श्री जयपाल रेड्डी साहब के साथ समाजवादी पार्टी की नेतागिरी करते थे, उस समय डां. लोहिया और हम लोगों के पुरखे श्री कर्पुरी ठाकुर इत्यादि कहा करते थे, " काम का अधिकार दो, काम का अधिकार दो"। उस समय एक फंडामेंटल राइट्स में संशोधन करने के लिए हम जोरों से कहते थे। उसी के तहत सभी दिनों के लिए नहीं, 100 दिनों के काम के अधिकार की गांरटी दी गई हैं।

महोदय, गरीबों का शहरों की ओर जो पलायन हो रहा है। शहर के लोग भी घबरा रहे हैं कि गांव के लोग यहां आ रहे हैं और शहरों में भीड़ बढ़ रही हैं। ऐसे लोगों को गांव में ही रोटी मिल जाए, इसीलिए यह कानून लाया गया हैं। इस क्रांतिकारी कानून को दोनो सदनों के माननीय सदस्यों ने, सभी पार्टियों के नेताओं ने बड़ा भारी समर्थन दिया। सभी ने यह कहा कि यह योजना सावधानी से चले, साफ-सुथरी रहे, जहां-तहां करप्शन और गड़बड़ी न फैले, यदि कहीं ऐसा हो भी तो उसे दूर करना चाहिए, इन सुझावों के साथ सभी लोगों ने हमें समर्थन दिया, इसके लिए हम उन सभी के आभारी हैं। सभी बुद्विजीवियों, अर्थशास्त्रियों,समाजशास्त्रियों और दुनिया भर के लोगों की नज़र रोज़गार गांरटी कार्यक्रम पर लगी हुई हैं।

इसकी शुरूआत 2 फरवरी, 2006 को अनन्तपुर जिले से हुई, जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी साहब का जिला हैं। वहां पर श्रीमती सोनिया गांधी, प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री इत्यादि सभी लोग मौजूद थे। वहीं से इसकी शुरूआत हुई। शुरू में यह 200 जिलों में लागू हुआ और इन 200 जिलों में 2 करोड़ 10 लाख परिवारों को रोज़गार मिला, इसके साथ ही 90 करोड़ मानव-दिवस सृजित हुए।

दूसरे चरण में जब इसमें 130 नये जिले जुड़ गए, मैं अभी 31 मार्च तक की रिपोर्ट सदन के सामने रख रहा हूं, इन 330 जिलों में 3 करोड़ 20 लाख परिवारों को रोजगार मिला। 1 अप्रैल से तो इसे देश भर में और भी फैलाया गया, लेकिन अप्रैल की रिपोर्ट हम सदन के माननीय सदस्यों को मई में बताएंगे। हरएक सत्र में हम अपनी स्टेटस रिपोर्ट और उपलब्धियां सदन की सेवा में समर्पित करते रहे हैं। इस तरह इस योजना से 3 करोड़ 20 लाख परिवारों को रोजगार मिला हैं और 120 करोड़ मानव-दिवस सृजित हुए हैं।

महोदय, अभी तक इन 330 जिलों में जितना भी वेज इम्प्लॉइमेंट प्रोग्राम लागू हुआ, उससे कभी 60 करोड़, कभी 70 करोड़ कभी 72 करोड़ कभी 75 करोड़ मानव-दिवस सृजित हुए। इसे SGRY के नाम से, इम्प्लॉइमेंट इंश्योरेंस स्कीम के नाम से चलाया गया और जिस साल हमने फ़ूड फॉर वर्क की शुरूआत की, उस साल भी देश भर में कभी 70 करोड़, कभी 75 करोड़ मानव-दिवस सृजित हुए। अभी तो 330 जिलों में केवल 120 करोड़ मानव-दिवस सृजित हुए हैं, लेकिन जब यह देश भर में फैल जाएगा, तब मुझे लगता है कि चार से पांच करोड़ के लगभग परिवार, जो वास्तव में गरीबी रेखा से नीचे है, उन्हें रोज़गार मिल सकेगा। गरीबी रेखा से नीचे असल में वही है, जो रोज़गार गांरटी योजना में काम कर रहा है, जो काम की मांग कर रहा है और जिसे काम मिल रहा हैं। हमारा अनुमान हैं कि इस योजना से देश भर में चार से पांच करोड़ के लगभग परिवार लाभान्वित होंगे।

यहां के जो शहरी लोग है, दिल्ली के जो अधिक विद्वान लोग है, वे अखबारों में लिख देते हैं कि इससे सभी लोगों को काम क्यों नहीं मिला और पूरे 100 दिन का काम क्यों नहीं मिला। सरजमीन के सभी लोगों से हमारी प्रार्थना है कि यह बुद्विजीवी वर्ग, जो दिमाग वाले लोग हैं, वे थोड़ा अपनी सरजमीन का अध्ययन भी करें, उसे देखें-भालें और उसकी जानकारी करें। हमने बार-बार लिख-लिख कर यह प्रार्थना की है कि सब लोग वहां जाकर देखें कि क्या स्थिति हैं। इसका मिक्स्ड रिज़ल्ट आया है, क्योंकि अगर कहीं पर किसी जिले का कलैक्टर बेहतर है, कहीं पंचायती राज का कार्य बेहतर ढंग से हो रहा हैं, तो वहां पर यह काम प्रथम श्रेणी का होगा। ऐसी जगह जाकर तो आप प्रशंसा करेंगे और कहेंगे कि पूरे देश से गरीबी बस यही मिटा देंगे। अगर कहीं गड़बड़ी हो तो वहां से शिकायत भी हो सकती हैं, क्योंकि हर चीज़ के शॉर्टकमिंग्स भी होते है, इसलिए उसमें हेराफेरी भी हो सकती हैं। ऐसे लोग पकड़े भी जा रहे है, उनके खिलाफ कार्यवाहियां भी हो रही हैं , इसलिए लोग कैसे ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि सब जगह की स्थिति एक-सी नहीं होती। हमारे देश में 2,38,000 पंचायते हैं। 34 लाख चुने हुए प्रतिनिधि हैं, 600 जिले हैं और उसके 600 अधिकारी हैं, 6 हजार प्रखंड हैं, तो उसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रोग्राम अफसर हैं। सभी लोग कैसे मान लेते हैं? अनार्किस्ट थ्योरी की जो शुरूआत हुई, लोगों ने भूल की थी, कि उसने मान लिया कि सभी मनुष्य विवेकशील हैं। बाद में वे टेरॅरिस्ट हो गए। हम यहां से कैसे मान लें कि सारे लोग सत्य हरिश्चंद्र हो गए हैं। भले ही उसमें तरह-तरह के लोग हैं। गड़बड़ियां हो सकती हैं। इसलिए श्रीमती वृंदा कारत जी ने जो यहां शंका जाहिर की और कहा कि एक anti-rural and anti-poor lobby देश में काम कर रही हैं। जब गांवों की तरफ ध्यान दिया जाए तथा गरीबों का सवाल और गांव के विकास का सवाल उठता है, तो कहा जाता है कि नाली में पैसा जा रहा है। पैसा नाली में जा रहा है, हेराफेरी हो रही है, एक रूपया में से 5 पैसा ही पहुंचता हैं लोग क्या-क्या नहीं कहते हैं। Siphoned off, ये सभी तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। गड़बड़िया और short-comings तो मैं स्वंय स्वीकार करता हूं कि यहां कैसे कोई मान ले। इतिहास में अनार्किस्ट थ्योरी फेल हो गई, नहीं तो

उसकी आइडियोलॉजी किसी से अभी भी बेहतर हैं । इसकी आइडियोलॉजी में तो था कि stateless society तथा मनुष्य में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, किस पर किस की हुकूमत चले, कौन प्रधान और कौन असिस्टेंट । कितना बड़ा और ऊचां सिद्वान्त था । उसने मान लिया, उसका assumption गलत हो गया कि हरेक मनुष्य विवेकशील है। मनुष्य में तो इतना divergence है, पशुओं में limitation है । मनुष्य एक देवता से भी अच्छा काम करने वाला हो सकता है और राक्षस से भी खराब, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, ऐसा काम भी करने वाले लोग है । उसके बीच में काम करना होता है । गरीब आदमी की बात है, तो हमारा जो गरीब मजदूर है, वह 1 से 20 तक की गिनती जानता है । वह जानता हैं कि वह कितना पैसा पा रहा है, 3-20 और 13 रूपए 3-20 का मतलब कि गांव का आदमी 20 से ज्यादा गिनती नहीं जानता, तो 20 तिया 60 और 13 मतलब 73 रूपए । एक चौका काटते हैं तो 3-20 और 13 रूपए मिलते हैं । 15 दिन काम किए ? तो हां कितना पैसा मिला ? नहीं बता सका कि सौ-सैंकड़ा कितना कमा सका । उसकी प्रोटेक्शन करना, उसकी सहायता और उसकी मदद करना तथा उसकी रखवाली करना और इसी तंत्र से, जो तंत्र उपलब्ध हैं । इसलिए हम आशान्वित हैं । एक चिन्ता हैं, जिससे लोग हमको जगा रहे हैं । हमें प्रोत्साहन दे रहे हैं तथा चेतावनी भी दे रहे हैं । हम उस चेतावनी और चुनौती को स्वीकार करते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि यह ठीक दिशा की तरफ जा रहा हैं । साल-डेढ़ साल में यह zero tolerance towards corruption हैं । अभी तक जितनी योजनाएं चली हैं, उन सब से इसमें न्यूनतम सम्भावना हैं । इस तरफ से प्रवीण राष्ट्रपाल जी ने सवाल उठा दिया कि आंध्र में पोस्ट ऑफिस से 100 परसेंट अकाउंट से भुगतान हुआ है, कर्णाटक में बैंक से 100 परसेंट भुगतान हुआ हैं । सभी राज्य सरकारों को हमने हिदायत दी हैं कि 30 अप्रैल तक आप हंड्रेड परसेंट भुगतान एकाउंट से करिए, बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस से या जो भी सहकारीकृत हैं, सभी । प्रधान मंत्री के स्तर पर भी बैठक हुई है । अभी तक 3 करोड़ 20 लाख परिवारों में से 1 करोड़ 20 लाख के खाते खुल गये हैं । एक-तिहाई से अधिक लोगों को खातों के माध्यम से भुगतान हो रहा हैं । हम विश्वास करते हैं कि एक-दो महीने में यह 100 परसेंट हो जाएगा । कहीं-कहीं, जहां unbanked areas हैं या पोस्ट ऑफिस भी हैं, वहां उस प्रतिशत में कुछ कमियां आ सकती हैं, नहीं तो हंड्रेड परसेंट भुगतान खातों के माध्यम से हो जाएगा । वहां से बिचौलिये गायब हो जाएंगे । हम उस तरफ जा रहे हैं।

श्रीमती वृंदा कारत जी ने बजट की चिन्ता की है, जो एक वाजिब चिन्ता हैं । आज शुरू के 200 जिलों में हमने कम खर्च किया, 8 हजार करोड़ उसके बाद जब 330 जिले 31 मार्च को हम खत्म किए है, उसमें 12 हजार 800 करोड़ हुआ । इस साल सभी जिलों में हैं, इसलिए हमको 16 हजार करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया हैं । हमने कहा कम हैं । इस पर फाइनांस विभाग, प्रधान मंत्री जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी आदि सब लोगों ने कहा कि यह तो demand-driven हैं । इसीलिए वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण में उल्लेख किया, 16 हजार करोड़ तत्काल किया हैं । यह खर्चा करेंगे तब जितना खर्चा होगा, हम देंगे, बजट में यह कमिटमेंट हैं । सेकंड सप्लिमेंटरी अथवा बीच में ही यह प्रावधान करने का उसमें उपाय किया गया है, इसलिए फंड की चिन्ता नहीं हैं । महोदय, हमने जीवट और मजबूत तथा अच्छे इरादे के साथ यह ग्रामोन्मुखी,समतामुखी और गरीबोन्मुखी कानून लागू किया है । हमें सब का समर्थन है, इसलिए बजट की हमें परवाह नहीं । अब हमारी एक ही चिन्ता हैं । वह चिन्ता यह हैं कि जब गांव से लोग आएंगे और कहेंगे कि इसमें कोई हेराफेरी नहीं है, तब हम इस योजना की असली सफलता मानेंगे । तो उसी पर हमारा ध्यान है । निश्चय ही राज्य सरकार, पंचायती राजें सभी पर हमको निर्भर करना पड़ता है । इसलिए हम बराबर राज्य सरकारों से संपर्क में हैं हम साल में 4-5 बैठकें राज्य सरकारों के साथ कर रहे हैं । हम सभी राज्यों में जा रहे हैं । शरद यादव जी जाने-आने की बात कह रहे थे,हम मुख्य मंत्रियों के साथ बैठकें तय कर रहे हैं क्योंकि यह कार्य राज्य सरकारों के सहयोग से ही होना हैं । इसलिए महोदय, रोजगार गांरटी कार्यक्रम में हमने पांच फार्मूले लागू किए हैं । अवैयरनेस, पीपुल्स पार्टिसिपेशन अर्थात् जानकारी व जन-भागीदारी, स्टेट विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग, ट्रांसपेरेंसी अर्थात् पारदर्शिता, एम.आई.एम. सिस्टमक का प्रयोग । हर चीज वैब-साइट पर खुली किताब की तरह हैं ताकि लोग देखें, जानें और सब की नजर में रहे अकाउंटेबिलिटी, अभी श्रीमती जया बच्चन जी ने अपने भाषण में अकाउंटेबिलिटी की बात की । महोदय, इस में 5 पॉइंट फॉर्मूला है—अवेयरनेस, पीपुल्स पार्टिसिपेशन, ट्रांसपिरेंसी, स्ट्रिक्ट विजिलेंस एंड मॉनीटरिंग और अकाउंटेबिलिटी । महोदय, बाकी हमारे ही हाथ में सब कुछ नहीं हैं, वह राज्य सरकारों को लागू करना हैं हम उनसे आग्रह करते है और कहां-क्हां कठिनाई आती हैं वह हमें बताते हैं । उसके बाद महोदय, प्रथम है लोगों को रोटी देना, उसके बाद वह पर्मानेंट असेट है । महोदय, लोग गलत कहते हैं कि टेंपरेरी काम हो रहा है, यह गलत हैं । मैं सदन को और माननीय सदस्यों को जानकारी देता हूं, हमारी प्रार्थना हैं कि लोग हमें बताएं कि इसमें कहां गड़बड़ी हैं ? हम राज्य सरकारों से बराबर संपर्क में हैं कि गड़बड़ी न हो और पर्मानेंट असेट्स की सूची बनाई जाए ।

उस संपत्ति का रजिस्टर गांव व पंचायतों में रहे और उसके मेंटेनेंस का भी प्रावधान हमने किया हैं। महोदय, उसमें अभी तक 3 करोड़, 20 लाख लोगों को रोजगार मिला हैं। महोदय, उस में शेड्यूल्ड कास्ट 27 परसेंट, शेडयूल्ड ट्राइब्स का 29 परसेंट, वूमेन 41 परसेंट हैं। श्रीमती वृंदा कारत जी लड़ती थीं कि 33 परसेंट से कम नहीं होना चाहिए। वे 41 परसेंट हैं और अदर्स 42 परसेंट हैं। इस तरह से उसमें जो काम हुआ है –वाटर कंजर्वेशन 47 परसेंट। अभी एक माननीय सदस्य भाषण कर रहे थे कि कितना होना चाहिए ? तो 47.88 परसेंट वाटर कंजर्वेशन का,वाटर कंजर्वेशन की 7.99 लाख स्कीम हैं, प्रोविजंस ऑफ अर्बन इरिगेशन फेसिलिटी 15.36 परसेंट और उसकी संख्या 2.56 लाख हैं। रूरल कनेक्टिविटी में मिट्टीकरण, ईटकरण और मुरम वगैरह बिछा देते हैं सड़क पर और जो गांव इंटीरियर में बिछा हुआ है, जहां पी.एम.जी.एस.वाय. अभी तक वहां नहीं पहुंची हैं, इसके लिए तत्काल यह हैं 16.06 परसेंट और इसकी 2.68 लाख स्कीम्स हैं। महोदय, एनी अदर एक्टिविटी 3 परसेंट हैं। इसलिए देश और समाज के लिए पर्मानेंट असेट्स का सृजन हो रहा हैं। महोदय, मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा, डूंगरपुर, को राजस्थान के सभी माननीय सदस्य जानते होंगे। डा. पिलानिया साहब किस इलाके के हैं, हम नहीं जानते, लेकिन डूंगरपुर मैंने स्वयं विजिट किया है। ग्राउंड वाटर ऊपर आ गया है, 6 जगह चैक डैम बना दिए हैं नाले में, 6 जगह दो किलोमीटर पर और 12 किलोमीटर तक पानी का खजाना हो गया है। उससे दोनों तरफ सिंचाई की व्यवस्था हैं और ग्राउंड वाटर जहां हैंडपंप्स बेकार हो गए थे, टयूबवेल्स बेकार हो गए थे, वहां सब कारगर हो गया।

तो इस तरह से सक्सैस स्टोरी सब हैं। मध्य प्रदेश में आप रिपोर्ट लें कि कैसे काम हुआ है, राजस्थान में कैसे लोग काम करा रहे हैं और कितनी आशा हैं लोगों को इस योजना से। यह एक क्रांतिकारी कानून हैं। महोदय, गरीबों के पक्ष में इतना बड़ा कानून अभी तक नहीं बना है, लेकिन मैं स्वीकार करता हूं जो निर्मला देशपांडे जी ने कहा कि लोग नहीं जानते। अधिकारी नहीं जान रहा हैं तो हमारे गांव का अनपढ़ कैसे जान जाएगा ? हमारा इतना बड़ा देश हैं और गांव-गांव तक इसे पहुंचने में कुछ समय लग सकता है, बाकी मैं प्रयत्न कर रहा हूं। इसलिए रोजगार गांरटी कानून की यह स्थिति हैं। महोदय, हम पूरी तरह आशांवित हैं और इसके लिए हमको सदन और माननीय सदस्य सभी के सहयोग की जरूरत हैं। सभी रूरल डवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स, सभी वाइस-चांसलर्स, यू.जी.सी.चेयरमैन, आई.आई.टी/ आई.आई.एम. जैसी एक्सलेंट इंस्टीटयूट्स है—सभी को हमने इसमें भागीदारी बनने के लिए प्रार्थना की हैं कि सब लोग देखें, अध्ययन करें और हमको बताएं। हम वहां स्टेट स्तर पर भी मुख्य मंत्री जी तक संपर्क में हैं। महोदय, पंडित जवाहर लाल जी, महीने में मुख्य मंत्रियों को दो बार पत्र लिखते थे, वह किताब छपी हैं। किताब छपी हैं। हम तीन बार लिखते हैं, बिहार में चार बार लिखते हैं, इसलिए कुछ लोगों को खुजलाहट हो जाती है, जो बहुत लिखते थे। चूंकि हमें राज्य सरकार के सहयोग से काम करना है, तो मुख्य मंत्री जी के लिख देने से, यदि मुख्य मंत्री इसे खोज कर दें, तो काम बहुत आसान हो जाता हैं इस तरह हम रोजगार गारंटी कानून में सफलता की ओर जा रहे हैं। करप्शन, कमियां, शॉर्टकमिंग्स को हम स्वीकार करते हैं, ये जहां-तहां हैं। इसमें पांच सूत्र को हमने लागू किया है, बैंक ट्रांसपेरेन्सी को लागू किया है, साल भर में इसके रिजल्ट आने लगेंगे। जब बिचौलिया रहेगा ही नहीं और जो मजदूरी करेगा, उसके खाते में पैसा चला जाएगा बैंक में या पोस्ट-ऑफिस में। कहा गया कि पोस्ट-ऑफिस में भी कुछ गड़बड़ हो जाती है, पैसा देने में देरी होती हैं। यह सब शिकायतें कुछ महीनों में दूर हो जाएंगी। तो पोस्ट ऑफिस के साथ, बैंकों के साथ तैयारी की गई हैं। अब गरीब का बैंक में खाता खुल जाए, यह भी अपना एक अलग तरह का एम्पावरमेंट हैं। इससे उनमें कुछ बचत की प्रवृत्ति भी बढ़ती हैं, जैसी कर्नाटक के कलेक्टर ने हमको रिपोर्ट की कि एक ब्लॉक में 6 लाख रूपए गरीबों ने बचत किए हैं। वह उनकी जमा-पूंजी है और जब उसकी उन्हें जरूरत होगी, उससे उनका काम चलेगा, उसका वे इस्तेमाल करेंगे। इस योजना का कई तरह से बड़ा भारी असर होने जा रहा हैं।

महोदय, हमारा फिर दूसरा प्रोग्राम भारत-निर्माण का हैं। इस भारत-निर्माण के प्रोग्राम में चार वर्षो के लिए, वर्ष 2005-2006 से लेकर 2009 तक 1,74,000 करोड़ रूपए का रखा है, जिसमें 6 आइटम हैं और इसमें हमारी मिनिस्टरी का 85,000 करोड़ का हैं। यह प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना भारत-निर्माण में हैं। इसमें हमको एक हजार आबादी वाले समतल और 500 आबादी वाले हिली और ट्राइबल एरिया के लिए टाइम-बाउंड प्रोग्राम 2009 तक का है, इन चार वर्षो में 48 हजार करोड़ रूपया खर्च करना है। माननीय सदस्य शांता कुमार जी बैठे हैं, उस समय यह प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरूआत हुई थी। मेंडेट था, पांच सौ समतल और ढाई सौ हिली और ट्राइबल एरिया वाले गांवों को पक्की सड़क से जोड़ना, ताकि गांव के लोग भी सड़क पर चलें। इंटरनेशनल आर्गेनाइजेशन ने जांच कर कहा हैं कि जहां आप एक करोड़ रूपया सड़क पर निवेश करते हो, तो 1640 परिवार गरीबी रेखा से ऊपर आ सकते हैं, यह सड़क का कमाल हैं। वहां पढ़ाई-लिखाई की, और दूसरी सारी सुविधाएं हो जाएंगी, अगर लोगों के लिए गांवो में सड़क हो। यहां वातावरण बनता है कि गांव में सड़क क्यों हो ? गांव में सड़क होने से शहर में रहने वाले लोग कहते हैं कि हम गांव में रहेंगे और अपने जिले में दस मिनट में चले आएंगे। सड़क खराब रहने से, यातायात का साधन न रहने से गांव में लोग नहीं रहना चाहते।

महोदय, अभी सांगी साहब कह रहे थे कि अर्बनाइजेशन कर दीजिए । अगर अर्बनाइजेशन कर दिया जाए, तो खाइएगा कहां से ? कैसे-कैसे सिद्वांत लोग चलाते हैं । अब अर्बनाइजेशन होने से लिमिटेड जगह होगी, शहर में दो-माला, पांच-माला बनाते रहिए, मगर देहातों में अर्बनाइजेशन करेंगे, तो खेती कहां से होगी? क्या शहर में खेती होगी ? खेती तो गांव में होगी । इसलिए इसमें सजग रहने की जरूरत हैं ।

महोदय, जो भारत निर्माण का कार्यक्रम है, 48,000 करोड़ रूपया हमको चार वर्षो में खर्च करना था । ढ़ाई हजार करोड़ का बजट प्रावधान था डीजल सेस से, मगर वह 2400, 2500 करोड़ रूपया भी खर्च नहीं होता था, राज्यों की कन्जुमिंग कैपेसिटी कमजोर थी । अब धीरे-धीरे करके वर्ष 2005-06 में 4200 करोड़ रूपए खर्च हुए, वर्ष 2006-07 में लगभग सात और आठ हजार करोड़ के बीच में खर्च हुए, इस साल जो बीता है, यह 11 से 12 हजार करोड़ के बीच खर्च हुआ हैं । इस तरह यह पांच गुना कन्ज्युमिंग कैपेसिटी में बढ़ोतरी हुई हैं और इस साल भी हम दावा करते हैं कि 12-13 हजार करोड़ रूपए खर्च करेंगे । अगले साल हो सकता है, एक साल योजना स्लिप करे, आगे बढ़ जाएं । इसलिए 48 हजार करोड़ रूपए में हम, यह एक हजार आबादी वाले समतल और पांच सौ आबादी वाले हिली और ट्राइबल गांवों को सड़क से जोड़ेगें । प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की जब शुरूआत हुई थी, तो लोगों ने अनुमान लगाया था कि इसमें 60 हजार करोड़ खर्च होंगे । कहीं नहीं खर्च हुआ, अब इसमें 1 लाख 32 हजार करोड़ रूपए खर्च होना है, तब यह प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का जो मेंडेट है, हम उसको पूरा कर सकते हैं । इसमें भी सभी राज्य सरकारों ने बड़ा भारी सहयोग किया हैं । इसमें इम्प्रूवमेंट आई है, कन्ज्युमिंग कैपेसिटी में भी विस्तार हुआ हैं । अब इसकी सफलता में हमको कोई संदेह नहीं हैं । उसी तरह से रूरल एरियाज में 60 हजार मकान चार वर्षो में बनाने का था, 45 हजार से ज्यादा हम बना चुके हैं और फिर अभी जो इंदिरा आवास योजना का काम है, उसमें भी हेराफेरी का हो रहा है, अभी श्री राजनीति प्रसाद जी बता रहे थे, उसमें भी मिक्सड रिज़ल्ट हैं, कहीं-कहीं हो सकता हैं कि तीन हजार, चार हजार या पांच हजार रूपए वसूल कर लेते हों । अब हमने सभी राज्य सरकारों को कहा पिछले नवम्बर, 2007 को, जब सुप्रीम कोर्ट ने हमको आदेश दे दिया और उसने रोक हटा दिया, तब हमने कहा कि उसको दीवार पर टांगा जाए, ट्रांसपरेंट किया जाए । सबसे गरीब का, poorest of the poor का सबसे ऊपर नाम रहे, उसके बाद गरीबी के घटते क्रम में सब परिवारों का नाम, अगर स्कूल अथवा पंचायत भवन नहीं है तो कोई दीवार बनाकर उस पर लिखा जाए, ताकि गरीब आदमी जान जाए कि उसका नम्बर आ गया है, उसको इंदिरा आवास मिलेगा । तब वह दो-चार हजार रूपए न किसी को दे सकेगा और न कोई ले सकेगा । कुछ राज्य सरकारों ने यह किया है और कुछ राज्य सरकारें अभी टाइम मांग रही हैं । हमने लिखा-पढ़ी की हैं कि हम पैसा नहीं देंगे, लेकिन सब मुख्य मंत्रियों ने आग्रह किया कि उन्हें दो-चार महीने का समय दिया जाए और उनके सहयोग के बिना काम नहीं हो सकता । इसलिए उसमें भी ट्रांसपिरेंसी होने से कमी आई हैं । अब उसमें राशि भी 35,000 की गई हैं । 25,000 की सदन में मांग होती थी, राज्य सरकारों ने मांग की कि उसकी यूनिट कॉस्ट बढ़ाई जाए । तो समतल एरिया में 35,000 और हिल एरिया में 38,500 करके उसका दाम बढ़ाया गया । इतना ही नहीं, कोई गरीब आदमी यदि उसमें कुछ और बढ़ाना चाहे तो 15,000 रूपए वह बैंक से लोन ले सकता है 4% इंटरेस्ट पर । रिज़र्व बैंक आफ इंडिया को निर्देश चला गया है कि वह बैंकों को कहे कि 4% इंटरेस्ट पर उसको कम से कम 15,000 और दिया जाए । इस प्रकार उसको 35,000 इधर से मिलेगा और 15,0000 बैंक से लेकर वह 50,000 कर सकता हैं । कुछ राज्य सरकारें अपनी तरफ से कुछ दे रही हैं, जैसे शिवा जी बता रहे थे DMK सरकार के बारे में, वहां आंध्र प्रदेश में और कुछ राज्यों में लोग अपनी तरफ से कुछ जोड़ देते हैं ताकि मकान थोड़ा और अच्छा हो जाए । लेकिन, इंदिरा आवास योजना एक बहुत क्रांतिकारी योजना है, जो सबसे पापुलर हैं और गांव में जाएंगे तो गरीब बूढ़ा, बुजुर्ग बोलता हैं कि घर न मिला, घर न मिला । गांव में अगर मिलने जाएं, तो वहां यही मांग होती हैं ।

तीसरी बात हैं पीने के पानी की । साफ पीने के पानी का सवाल एक बहुत बड़ा सवाल हैं और डाक्टर लोग बताते हैं कि आधी बीमारियां, 50 परसैंट से ज्यादा बीमारियां गरीब आदमी को अशुद्ध पानी पीने से और सफाई नहीं रखने से हो रही हैं । तो यदि गरी बो safe drinking water उपलब्ध करा दिया जाए और उनके लिए सफाई की व्यवस्था करा दी जाए, तो यह बहुत बड़ा काम होगा गरीब के लिए । गरीब आदमी को कॉलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ थोड़े होती है, उसको तो डायरिया और खारा पानी पीने से कीटाणुओं के कारण बीमारियां होती हैं । वह जमीन पर सोता है तो सेंट फ्लाई मच्छर उसको कूद-कूदकर काट लेता है, वह मच्छर पलंग पर नहीं आता । इसलिए महोदय, बीमारी में भी अंतर हैं, गरीब आदमी की बीमारी अलग हैं और बड़े आदमी की बीमारी अलग हैं । तो गरीब आदमी को तो कालाजार हो जाता है । गरीब आदमी का अगर वाल्व खराब हो जाएगा, टेहुना में दर्द हुआ, सुई नहीं पड़ी, तो उसका वॉल्व खराब हो गया और वॉल्व बदलने में डेढ़-दो लाख रूपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन गरीब आदमी कहां से दे । इसलिए पूरी सफाई और उसको जानकारी कराकर

6.00 P.M.

स्वच्छता अभियान चलाया जाए। महात्मा गांधी जी ने आजादी की लडाई के समय कह गए है Sanitation is more important than independence पंडित जवाहर लाल नेहरु जी ने कहा था कि कोई इकनॉमिकल इंडिकेटर नहीं चहिए, हर घर में जब तब पानी-पखाना की जब तक व्यवस्था नहीं होगी, तब तक हम GDP या Per Capita Income नहीं मानेंगे । ये सब महान पुरुष हमको पहले से बता गए हैं, लेकिन हम पीछे चले गए । लेकिन ,अब पीछे नही रहेंगे । 1981 की जनगणना में देहात मे, रुरल घरों में एक परसैंट में शौचालय था, लेकिन 1991 में 9 परसैंट हुआ, 2001 की जनगणना में 21.9 परसैंट यानी लगभग 22 परसैंट हुआ और अभी हम लोक 50 परसैंट पार कर गए हैं महोदया, यह इंटरनेशनल सेनिटेशन ईयर है और मिलिनियम डेवेलपमेंट बोर्ड ने कहा 2015 तक 50 परसैंट में पूरा करो । हम कह रहे है कि 2015 नहीं, 2012 में हम निर्म्ल हिन्दुस्तान , निर्म्ल भारत बनाएंगे । महात्मा गांधी का सपना विफल नहीं हो सकता । निर्म्ल ग्राम पुरस्कार की स्कीम श्री शांता कुमार जी की बनाई हुई है, लेकिन इसे लागू हमने किया है ।2005 में इसकी शुरुआत हुई , केवल 40 पंचायतों में । देशभर की दो लाख से अधिक पंचायतों में से अधिक पंचायतों में यह शुरु किया गया और डा. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम , तत्कालीन राष्ट्रपति जी के हाथों से उनको पुरुस्कार दिलवाया गया, निर्म्ल ग्राम पुरुस्कार । अगले साल 2006 में उनकी संख्या हो गई, 770,यानी 20 गुणा बढोत्तरी हुई और उसके अगले साल, जो 2007 का साल बीता है, उसमें 4945 की संख्या हो गई , लगभग पांच हजार पंचायतों को निर्म्ल ग्राम पुरस्कार मिला है । इस बार 30 हजार पंचायतों और 12 जिलों को यह पुरस्कार मिला है । इसमें त्रिपुरा का बेहतर काम है, पश्चिम बंग़ाल का बेहतर काम है, सिक्किम में तो पूरा राज्य ही निर्म्ल हो जाएगा, उनको हम जरुर पुरस्कार देंगे । इधर तमिलनाडू में अच्छा काम हो रहा है, महाराष्ट्र में गाडगे बाबा, स्वच्छ्ता का प्रचार करते थे, गुजरात में यह काम शून्य पर था, लेकिन अब गुजरात ने take off किया है और ऐसा लगता है कि 2010 में ही पूरा गुजरात निर्म्ल हो जाएगा । इसी तरह कर्नाटक, केरल, इन सभी राज्यों में यह काम तेजी से हो रहा है और 2012 तक हमें यह लक्ष्य पूरा करना है । लगभग एक करोड़ शौचालय हमको हर साल बनवाने हैं, पहले उसके लिए 600-625 रुपए ग्रांट थी, उसको बढ़ाकर हमने 1,500 रुपए किया है, फिर इसको बढ़ाने को लिखा-पढ़ी हमने शुरु कर दी है, लगता है, लगता है कि महीने- डेढ़ महीने मे इसकी कीमत बढेगी । फिर गांव के लोग मांग़ करते हैं कि 1,500 रुपए में उसका काम पूरा नहीं होता है । इसलिए निर्मल ग्राम पुरस्कार देने की हमारी योजना है ।

संपूर्ण स्वच्छ्ता के लिए 100 लीटर लिक्विड वेस्ट को ट्रीट करने की हमारी योजना है । अभी तो नाली का पानी सडक पर बहता है, जिससे कीचड ही कीचड हो जाता है, उसमें भोजन का अंश मिला रहेने से वह दुर्ग़ंध देता है, उस मक्खियां भिनकती है और गावं के लोग उसी के बीच रहते हैं, तब वे बीमारी से कैसे बचेंग़ी ? इसलिए 100 लीटर लिक्विड वेस्टमैंनेजमेंट का हमने नया प्रावधान किया है । फिर बृजभूषण तिवारी जी पीने के पानी के बारे में बता रहे थे कि पीने का पानी गुणवत्ता वाला होना चाहिए , पीने का पानी की जांच होनी चाहिए । इसके लिए हमने Quality And Survellience Programme बनाया है, इसके लिए हर पंचायत में से 5 व्यक्तियों को चुना जाएगा और उनको पानी की जांच की ट्रेनिंग़ दी जाएगी । इसमें कुछ राज्य आगे और कुछ पीछे चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ महीनों में सभी पंचायतो में वे 5 आदमी हरेक पीने के पानी के स्रोत की जांच करने उस पर लाल चिह्न लगा देंगे कि यह पानी पीने के लायक है या नहीं। इसी तरह गंगा के किनारे पश्चिम बंगाल , बिहार , उत्त्र प्रदेश, झारखंड जैसे इलाकों मे लोग आर्सेनिक मिला जहरीला पानी पीते हैं इसी आंर्ध प्रदेश का नालगोंडा इलाका, राजस्थान कर्नाट्क गुजरात यहां पर फ्लोराइड की प्रॉब्लम है । कोस्ट्ल ऐरिया में कहीं बैक्टीरिया, कहीं नाइट्रेट, इन सभी को मिलाकर 2 लाख,12 हजार habitations में अशुद्ध पानी है, जो पीने के लायक नहीं है । इन सारी समस्याओं को दूर करके हमारे भारत निर्माण का लक्ष्य है, जो 26,000 करोड रुपए का है और वह लक्ष्य सही दिशा में जा रहा है ।

उपसभाध्यक्ष जी, हमारे बलबीर पुंज साहब विद्‌वान आदमी हैं, वे लेख लिखते हैं, लेकिन कभी भी वे ग्रामीण विकास पर या गरीब पर लेख नहीं लिखते हैं, वे केवल राजनीति पर या इधर-उधर का लेख लिख लिखते हैं हमारी इनसे प्रार्थना है कि ये दैंनिक जागरण में जो लिखते हैं, उसमें कुछ गरीबों कि बात भी लिखा करें हम बराबर ढूंढ्ते है कि शायद इन्होंने गरीब की बात उसमें लिखी होगी ।

श्री बलबीर पुंज : मैं मंत्रि जी के सुझाव को मानता हूं, लेकिन उसमें एक बात जोडना चाहता हूं कि जिन लोगों की वजह से गावों का विकास नहीं होता है, मैं उसके बारे में लिखता हूं । जिन लोगों के कारण भ्राष्टाचार पनपता है, मैं उनके बारे में ज्यादा लिखता हूं।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: आपसे हमारी अपेक्षा है कि आप ग्रामीण विकास और गरीब की बात भी लिखेंगे।

श्री एस.एस.अहलुवालिया: रघुंवश बाबू, आप बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, लेकिन डांटिए मत।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: हम डांट नहीं रहे है, हम प्रार्थना कर रहे हैंकि आप कृपा करके गरीब के विषय में लेख लिखिए। उन्होंने Power and Empowerment की बात कहीं थी, तो ग्रामीण विकास की 6 योजनाओं में से हमने बता दिया है कि 3 योजनाओं में यह हो रहा हैं एक बिजली से संबंधित हैं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। वर्ष 2009 तक हर गांव में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को बिजली का कनेक्शन मुफ्त में मिलेगा, उनको कनेक्शन के लिए फीस नहीं लगेगी। बिजली आगे जलाएगा तो लगेगा, लेकिन लाईन लेने में उसको नहीं लगेगा और 2012 तक घर-घर बिजली, 2015 तक 24 घंटे बिजली मिलेगी ...(**व्यवधान**)....।

श्री उदय प्रताप सिंह(उत्तर प्रदेश): महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जिन गांवों में बिजली है, उनमें से 80 प्रतिशत गांव में सिर्फ तार लगे हैं, एक बल्ब भी नहीं जलता हैं, यदि जलता भी है तो जैसे बीड़ी जलती है, वैसे कभी आ जाता है तो आ जाता हैं। यह बात भी स्वीकार कर लीजिए।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: इससे हम कहां इंकार करते हैं, इतना बड़ा देश है, ग्रामीण बिजली आपूर्ति में तार काटता हैं, हम लोग नीतीश कुमार को कहते हैं कि सिर्फ आप तार कट्टी बचवा दीजिए, तो बड़ा भारी काम जो जाएगा। समस्याएं तो है, पर उसका समाधान करने से होगा, सिर्फ यथार्थवादी दृष्टिकोण देने से, सिर्फ पोस्टमार्टम करते चलें, उससे काम नहीं चलेगा, हमको आगे क्या करना हैं, इसके लिए हम इस सदन से अपेक्षा करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना हैं। हम सुझाव ग्रहण करने को, आपकी रोशनी पर हम चलने को तैयार हैं और चल भी रहे हैं। अभी पिलानिया साहब कह रहे थे कि सूरत बदलनी चाहिए, हम तो कहते हैं कि "आप यूं ही अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमें लुटाता रहूं"। महोदय, भारत निर्माण का तीन विभाग हमारा हुआ, एक पावर वाला हुआ टेलीफोन कनेक्शन और इरिगेशन। सब मिला करके 1,74,000 करोड़ रूपए खर्च करना हैख् बाकी हमको लगता है कि इसमें भी पहले से जो प्लान आउट-ले तैयार हुआ है, उससे ज्यादा ही खर्चा होगा। खर्चा करना पड़ेगा, कम से काम नहीं चलेगा। इसी तरह से, गरीबी हटाने के लिए सब लोग बड़ी रूचि लेते है, निर्मला देशपाण्डे और सुप्रिया सुले जी, इन सभी लोगों ने कहा कि Self Employment प्रोग्राम में ऐसा काम हो, इसमें हम wage employment फिजीकली लेबर का unskilled लेबर के लिए हैं। इन लोगों का जो सुझाव हैं, उसके लिए Self Employment Programme हैं। अर्थशास्त्री लोग तो यहां पर सरल बात को ऐसा उलझन पैदा करके लिखेंगे कि सारे गरीब लोग समझ नहीं सकते हैं। महोदय, गरीबी हटाने का सिम्पल फार्मूला है, गरीबी इसलिए है, क्योंकि बेरोजगारी है। इसको कोई कोटे। हर एक गरीबी रेखा के नीचे के परिवार को या तो एक नौकरी या रोजगार, placement या स्वरोजगार, कहने का मतलब हैं कि उसको तीन हजार रूपए महीना एडिशनल इनकम का प्रावधान हो जाए, तो वह बीपीएल एपीएल हो जाएगा। यह साधारण बात है, इसको कोई काटे। आज देश भर के लोग, बुद्विजीवी, ज्ञानी, वैज्ञानिक सभी लगे हुए हैं, आज सभी लोग मल्टी नेशनल कंपनी,उद्योगपति या प्राईवेट पार्टनर्शिप में लगे हुए हैं। चार-पांच करोड़ रोजगार पैदा करके उनके लिए Self Employment Programme में लक्ष्य तैयार किया हैं। अभी तक हमारी मिनिस्ट्री में 29 लाख स्वंय सहायता समूह है, नबार्ड भी बनाती है, सिडबी भी बनाती है, महिला कामाख्या, चिल्ड्रेन डेवलपमेंट में है, वह भी करती है, लेकिन सबसे ज्यादा 29 लाख स्वंय सहायता समूह का गठन हुआ। यदि हर एक परिवार को अनिवार्य करें कि प्रत्येक गरीबी रेखा के नीचे के परिवार का कम से कम एक सदस्य स्वंय सहायता समूह का सदस्य जरूर हो जाए, तो जितना स्वंय सहायता समूह का सदस्य अभी है, उतना और हमको बनाना पड़ेगा। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक हमने यह लक्ष्य रखा हैं। यह तो एक बात हुई। दूसरी बात यह हैं कि उनका बैंक में खाता खुल जाए। बैंक में खाता खुलने के बाद उसमें दो धाराएं आती हैं, एक धारा हैं कि देश और दुनिया में डिमाण्ड का पता लगाया जाए, किन बातों की मांग है, कैसे व्यक्तियों की खोज है, उस तरह की ट्रेनिंग उनको दी जाए। क्वालिटी वाली ट्रेनिंग के तहत स्कील्ड डेवलपमेंट मस्ट प्लेसमेंट हो, प्लेसमेंट जरूरी हैं। ट्राइसेम से हम सीखे हैं, वह सीखने के लिए नहीं आया, वह पैसा लेने के लिए आ गया, सीखा नहीं और फिर वैसा ही बैठा रह गया। इसलिए प्लेसमेंट के साथ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने शुरू किया है और इसमें भी हम सफलता की ओर जा रहे हैं। दूसरा उसका स्वरोजगार उसकी इच्छा के मुताबिक, चाहे यह डेयरी हो, फिशरी हो, गोटरी हो, पॉल्ट्री हो या कोई दुकानदारी हो या जो भी काम हो, या अपने से कोई निर्माण कार्य हो, हमारा गांव में कोई कारीगर, लोहे का, कागज का, लकड़ी का, मिट्टी का, पत्थर का, भोजन का, फूड items के रंग-बिरंगी चीजें बनाते हैं। लेकिन उनकी मार्केटिंग का प्रावधान नहीं है, इसलिए मार्केटिंग का प्रावधान हमने किया हैं।

सुप्रिया सुले जी बोल रही थीं, मार्केटिंग का कैसे प्रबंध होगा ? प्रगति मैदान में, राजीव गांधी भवन जो खड़क सिंह मार्ग पर है, जसोला और पीतमपुरा में, दिल्ली में चार जगहों पर भारत सरकार की ओर से राज्य सरकारों को हमने दुकानें आवंटित की हैं कि यहां आप अपने सैल्फ हैल्प ग्रुप के marketing of rural products कीजिए और उसको बेचने का प्रबंध कीजिए और बड़ी मांग हैं उसकी । लोग जान जाते हैं, लेकिन पैकेजिंग, डिज़ाइनिंग और उसकी ब्रांडिंग वगैरह की कमी है, इसीलिए ....(**व्यवधान**)...

श्री अमर सिंह: आप रेल मंत्री जी से भी बात कीजिए ।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: अभी मैं विभिन्न माननीय सदस्यों के नाम से बात करूंगा, अभी तो हम जनरल चला रहे हैं । अभी हम उसके बारे में बताएंगे, उसका जवाब देंगे । तो इसलिए यह self help employment programme हुआ । फिर हुआ Land Resource Management, जो जमीन के लिए लड़ाई चली आ रही है, जमीन खामोश पड़ी हैं । हमारे मुल्क में एक से एक राजे-रजवाड़े आए, जमीन की कितनी भारी समस्या है टोडरमल से लेकर अभी तक, इसलिए National land Resource Management Programme, सात वर्षो में Time bound tangeted, Computerisation of land records and strengthening of revenue administration, and updating of land record, इन सभी का करके डिजिटल मैप के साथ, किसी जिले का सर्वे नहीं हुआ, कहीं नक्शे नहीं हैं, किसी के नाम से कोई जमीन जोत रहा हैं, दाखिल नहीं हुआ हैं, mutation नहीं हुआ है, ये सभी तरह की समस्याएं है, इसके लिए, land reforms के लिए भी और land resource management के लिए Rehabilitation and Resettlement Policy....SEZ को जो झगड़ा है, जो मार-काट चल रही है, यह खत्म हो जाएगा जब National Rehabilitation & Settlement Policy को statute का दर्जा मिल जाएगा। भारतीय संविधान की धारा 73 के मुताबिक उसको statute का दर्जा दिया है, वह कानून लागू हो गया है, इसके enactment के लिए वह हमारी स्टैंडिंग कमेटी में लंबित हैं । उससे संबंधित Land Acquisition Act का अमेंडमेंट और Settlement Policy का कानून बनाने का, दोनों प्रस्ताव स्टैडिंग कमेटी में है और शायद अगले सत्र में वे पास होंगे और फिर unfinished agenda land reforms के लिए दो कमेटियां- एक प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में और दूसरी हमारी अध्यक्षता में- बैठकें शुरू हो गई, काम शुरू हो गया, इसलिए जमीन संबंधी विवाद को भी हम हल कर पाएंगे और जमीन की समस्या का, लैंड पॉलिसी, लैंड यूज़ पॉलिसी और सभी तरह की समस्याओं का समाधान होगा । तो इस तरह से जो मोटी-मोटी ग्रामीण विकास की योजनाओं का काम हैं, उसका हमने ज़िक्र किया है, लेकिन माननीय सदस्यों ने जो विभिन्न अमूल्य सुझाव दिए हैं और जो सवाल उठाएं हैं-श्रीमती वृंदा कारत ने सवाल उठाया हैं self help group federation का । हम स्वीकार करते हैं, हम लगे हुए है, हमने सभी राज्य सरकारों को कहा हैं कि self help group federation को बनाया जाए और उसको हमने स्वीकार किया हैं । फिर home state landless, दो तरह के landless हैं देश में कन्फ्यूज़ करके रखा था- landless, landless, and landless. ऐसे भी लोग हैं जिनके पास एक धूर ज़मीन नहीं हैं । कहीं सड़क के किनारे, कहीं बाड़ पर, कहीं, ठकुरबाड़ी की ज़मीन पर, कहीं स्कूल की ज़मीन पर, इंदिरा आवास उनके लिए मंजूर हुआ, लेकिन अफसर कहता है कि ज़मीन ही नहीं है, कहां बनेगा ? कुछ राज्य सरकारें अपनी तरफ से ज़मीन खरीदकर उपाय कर रही है, इसलिए फर्स्ट टाइम, इस साल 2008-09 के बजट में, वृंदा कारत जी, 100 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया है । Home state landless वालों को इंदिरा आवास देने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए सौ करोड़ रूपया बजट में प्रावधान इस साल प्रथम किया है । जब उसको ज़मीन मिलती नहीं है, कैसे कहेगा वह कि यह हमारा हिंदुस्तान हैं ? इसलिए उसको भी एक-दो हाथ ज़मीन चाहिए, इसलिए यह प्रावधान हमने प्रथम किया है और उनकी मांग थी, उनका सवाल था, इसलिए उसका हम तुंरत उत्तर दे रहे हैं ।

फिर आंगनवाड़ी शौचालय के लिए उन्होंने कहा कि 9 हज़ार से घटाकर 5 हज़ार..नहीं, अब 10 हज़ार पर हमने उसके लिए लिखा पढ़ी की है और जा रहे है, इसलिए भी आपकी मांग को हमने स्वीकार कर लिया । Minimum wages का सवाल श्री प्रवीण राष्ट्रपाल और श्रीमती वृंदा कारत ने उठाया । इसमें wage employment और उधर से अनुसूइया जी ने कहा, वे चली गई हैं । उन्होंने अंत में एक लाइन में कह दिया कि सौ दिन से ज्यादा बढ़ा दीजिए । हम भी मध्य प्रदेश और राजस्थान में गए हैं । महोदय, हिन्दुस्तान में खेती पर हम कोई कुप्रभाव नहीं डालना चाहते । चूंकि खेती हमारी आर्थिक प्रगति की रीढ़ है । अभी हमारे यहां मकैनिकल खेती नहीं हुई है । यहां पर मजदूरों की जरूरत होती हैं । अब सारा दिन अगर हम सरकारी काम ही दे देंगे तो किसान के खेत में मजदूर नहीं जाएगा । फिर खेती का क्या होगा ? इसलिए सौ दिन का सोच-विचार करके दिया गया । लीन पीरियड में, जिस समय खेत में काम नहीं होता, लोग पलायन करते हैं, उस समय वे पलायन नहीं करे, वहीं पर रहें, यही सोच कर सौ दिन किया गया हैं । लेकिन यह भी हम खारिज नहीं करते । बाद में जब शोध पर रिपोर्ट आ जाएगी कि एक पैसा हेराफेरी नहीं है, तो उस पर भी विचार होगा । इसमें विस्तार की बहुत संभावना हैं । मिनिमम वेज के संबंध में अर्थशास्त्री लोग हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि देश भर में एक मिनिमम वेज कर दीजिए ।

महोदय,जिस समय हम रोजगार गारंटी कानून लागू करने चले थे, एग्रीकल्चरल मिनिमम वेज नागालैंड में 25 रूपए था। केरल में 125 रूपए, बीच में 40,45,47,55,60,70 और 80 था। हमने कहा कि एक करने के लिए कितना करें। मान लीजिए, वृंदा कारत जी का था Central Government should fix not less than 50. हमने मान लिया तो हम साफ करेंगे जो स्टेट गवर्नमेंट्स कम दे रही हैं, वे कहेंगी कि आप बढ़ाने वाले कौन हैं? हमारी जो डोमैस्टिक योजना है, उसका क्या होगा ? हमारा किसान मरेगा। आप मजदूरी बढ़ा रहे हो, लेकिन किसान की आमदनी नहीं बढ़ी। इसी प्रकार जहां ज्यादा दे रहे हैं, वे कहेंगे कि हम ज्यादा दे रहे हैं तो आप घटाने वाले कौन हैं? महोदय, स्टेट का मिनिमम वेज़िज एक्ट-1948, सेक्शन-3, के अनुसार मिनिमम वेजिज़ एक्ट में सभी तरह के हिसाब से अपना वेज तय करता हैं। इसलिए हम राज्य सरकारों से सहयोग लेने के लिए उनसे कोई confront नहीं कर सकते। यह भी जरूरी हैं किसानों पर इस स्कीम से कुप्रभाव न डाला जाए। हम गांव में गए तो कहा गया कि आपने मजदूरों को रोज़गार गारंटी दे दिया, किसानों के लिए मजदूर गारंटी करिए, हमें मजदूर नहीं मिल रहे हैं

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL: Wages are paid by the Central Government. That is why we want that it should be reformed. I will give you one example. The biggest public sector company in the country, i.e. ONGC is giving Rs. 225 to unskilled, Rs. 250 to semi-skilled and 300 to skilled. Wages are not paid by the State Government. They **are** paid by the Central Government.

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: यह बात ठीक हैं कि मिनिमम वेजिज़ का जो वेज कम्पोनेंट हैं, वह सैंट्रल गवर्नमेंट देता हैं। इसीलिए राज्य सरकारें कुछ नासमझी से क्रांतिकारी बनने लगीं। एक्ट में यह हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का मिनिमम वेजिज़ एक्ट-1948, सेक्शन-3 का जो एग्रीकल्चरल वेज हैं, यही वेज रोजगार गांरटी में भी तब तक रहेगा, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट अपना मिनिमम वेज नोटिफाई न कर दें। सवाल उठा कि गुजरात में पचास रूपए हैं। गुजरात में पचास हैं लेकिन वहां पर प्रोडिक्टिविटी, जितना काम करना है- जो देश भर में जितना काम हो रहा है- उसका आधा हैं। पचास रूपया एक दिन में मिनिमम वेज हैं लेकिन काम सौ धन फीट नही, पचास घन फीट हैं। यह सब भी चल रहा है। दिखता था कि देश भर में कम है, पचास रूपए हैं लेकिन उसका जो माटी काटने का माप है, वह भी 50 परसेंट हैं। वह घटा दिया है। इधर कुछ बढ़ा दिया। इसलिए रीज़नेबल मानकर हमने स्टेट गवर्नमेंट्स को यह सुझाव दिया था कि आप जो अपना एग्रीकल्चरल वेज़ देते हैं, उसी को रखिए। खेती पर कुप्रभाव न डाला जाए क्योंकि किसान को बचाना जरूरी है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की जगह सेंट्रल गवर्नमेंट ने मजदूरी का ले लिया है इसलिए वे क्रांतिकारी बन रहे हैं और किसी-किसी राज्य से हाइपर इनफ्लेशन की शिकायत आयी। इसलिए उसके लिए भी हमने सबकी राय से उच्चस्तरीय बैठक निर्धारित की है, वह हम करेंगे। लेकिन एक जैसी मिनिमम वेज के संबंध में यदि देश भर के सभी राज्यों में कंसेंसस हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं हैं। महोदय, इसी रोजगार गांरटी कानून का कमाल हैं कि मिनिमम वेज पर बहस हो गयी। टाइम ऐंडमोशन श्रीमती वृंदा कारत जी कहती हैं। मजदूर अब कहता हैं कि एक सौ घन फीट माटी काटेंगे तो इसका कितना दाम दोगे। इसी माटी मूढ़ी पर लेकर सौ गज तक जाएंगे तो उसका कितना दाम मिलेगा। इसलिए यह सब कांशियसनेस रोजगार गांरटी का कमाल हैं, मजदूरों की बारगेनिंग कैपेसिटी बढ़ गयी हैं। उनको एहसास हो रहा है कि हम भी कुछ हैं। पहले श्रम का कोई महत्व नहीं था, अब श्रम का महत्व होने लगा है, दिखने लगा हैं। यह रोजगार गांरटी की क्रांतिकारिता के चलते ऐसा हुआ हैं। 9 घंटे के बारे में अलग से चल रहा है, जो भी सहमति होगी हम करेंगे। स्कीम की फलेक्सिबिलिटी में भी स्टेट गवर्नमेंट को छूट हैं। आप बताइए कि आपके यहां कोई अन्य काम-वाटर कंजरवेशन, लैंड डवलपमेंट या फोरेस्ट या रूरल कनेक्टिविटी या इसके अलावा और काम हो तो बताइए, उस पर भी हम लोग विचार करने के लिए तैयार हैं श्रीमती वृंदा कारत जी के सवाल पर लैंड रिफार्मिग कमेटी बन गई है, उसको हम लोग देख रहे हैं कि कैसे जमीन के भूदान का, वेस्ट लैंड वाला और वेस्ट लैंड में 6 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर जमीन माना जाए। उसमें करीब एक करोड़ जमीन ऐसी हैं जिसमें पत्थर हैं। वह कल्चरेबल नहीं हैं। साढ़े पांच करोड़ हेक्टेयर जमीन कल्चरेबल हैं, ऐसा लोगों ने बताया हैं। उस पर हम काम कर रहे हैं और एक कमेटी का गठन हुआ है और एक गाइड-लाइंस भी तैयार हुई हैं। उसमें जो प्रोग्राम होगा वह टेक्नीकल और प्रोफेशनल सहयोग के बाद देश के राज्यों के साथ पंचायती राज औरसभी को भागीदार बनाकर के टाइम बाउंड प्रोग्राम किया जाएगा। चूंकि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा, तेल के लिए नहीं होगा। इसलिए टारगेटेड प्रोग्राम से हम लोग उस काम को करने जा रहे हैं। नाच्चीयप्पन साहब और अन्य ने वर्णन किया है और श्रीमती सोनिया गांधी जी की प्रशंसा की हैं। बलबीर पुंज साहब ने प्रधान मंत्री के सवाल पर बहस शुरू की तथा राहुल गांधी जी का भी वर्णन किया। लोग

अपने नेता की प्रशंसा करते हैं। महोदय इसमें हमको कहना है, यह कभी-विपक्ष में तुलना की जाती है। यू. पी. ए. की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा था कि प्रधान मंत्री का पद हमें नहीं दूसरे को दिया जाए और उधर बिना पोस्ट के ही आडवाणी जी वेटिंग प्रधान मंत्री हो गए। महोदय, फिर हम में और इनमें क्या तुलना की जा सकती है। हम लोगों के पास ऐसी नेता है, जो प्रधान मंत्री की पोस्ट को ठुकरा देने वाली है, और उधर तैयार है कि हमारा जल्दी करिए। हम में तुम में फर्क बहुत है क्यों आजमाना चाहते हो। हमारे पास गद्दी छोड़ने वाले हैं और आप गद्दी के लिए ललचाए हो। उन्होनें जो एन. आर. ई. जी. एस. का सवाल उठाया। आप अगर एन. आर. ई. जी. एस. की आलोचना करिएगा तो पार्टी में शो कॉज दीजिएगा कि बी. जे. पी. रूल्ड स्टेट्स ही कर रहे हैं, लाभ उठा रहे है।श्रीमती वृंदा कारत जी और अन्य सदस्यों ने सवाल उठाया कि गरीबी रेखा से नीचे कौन है। उसमें सेलरी वाला है, पर-केपिटा इंकम वाला पहले से है, और इसमें बारह हजार सालाना की आमदनी होगी और अगर उनसे कम हुआ तो बी. पी. एल. होगा। महादेय, यह दो हजार का बीस हजार हुआ। यह तो 2002 में, इन्हीं के समय में हुआ था। जब एक एक्सपर्ट ग्रुप बैठा तथा प्लानिंग कमिशन के सब विद्वान लोग थे। जिसमें 13 पैरामीटर्स निश्चित थे जिसके अनुसार, उनको जमीन है या नहीं, वे भोजन क्या करते हैं, उनको वस्त्र है या नहीं, उनकी पढ़ाई-लिखाई है या नहीं मैं उसको एकदम एकुरेट और फूलप्रुफ नहीं मानता। पहले का जितना भी इंडीकेटर्स था, पैरामीटर था अब उससे बैटर और वेरीफाएबल है। परिवार का नाम लिखा हुआ है, उसको जांचा जा सकता है कि उसकी क्या स्थिति है। इसलिए मैं इसको पहले की तमाम चीजों से ज्यादा एकुरेट मानता हूं। लेकिन अभी फिर से योजना आयोग ने कोई तेंदुलकर विद्वान आदमी है, उनकी अध्यक्षता में एक्सपर्ट ग्रुप की बैठक करा दी है, चूंकि यह 2002 का सर्वे है। उसकी बैठक हुई है, उसमें सब लोगों की, आप लोगों की जो भावना है, उनके बारे में हम एक्सपर्ट ग्रुप को और कमेटी को बतायेंगे कि इन लोगों का यह कहना है। इसीलिए 2000 बीपीएल सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, हमने प्रार्थना की कि हमको दीवार पर टांगना है, ट्रांसपेरेंट करना है, तो उन्होनें छोड़ दिया है, तेरह चौका 52 में जो अकांउट नम्बर होगा, पूअरेस्ट दि पूअर जीरो नंवर ऑफ वाला ऊपर, एक नम्बर वाला, दो नम्बर वाला, तीन नम्बर वाला, महोदय, इस तरह से करना है। इसीलिए पावर्टी और बीपीएल का सवाल है। श्री शारद जी चले गये, वह हम लोगों के साथी थे, नेता थे। लोहिया जी के सिंद्वात कम, भाषण ज्यादा कर रहे हैं भ्रष्टाचार से मुकाबले के लिए। डा. लोहिया कहते थे कि भ्रष्टाचार की तीन जड़ें है। जहां आमद से ज्यादा खर्चा होगा, वहां भ्रष्टाचार होगा। इसको कोई रोक नहीं सकता है, नम्बर एक। नम्बर दो, जहां एक पक्ष ताकतवर होगा और एक पक्ष कमजोर होगा, वहाम भी भ्रष्टाचार होगा। तीसरा होता है। जात-पात, हीत-कुटुम्ब, नजदीक भाई-भतीजा के लिए भ्रष्टाचार। इन तीन के अलावा कहीं भ्रष्टाचार नहीं होता है। इसलिए इन तीन पर नियंत्रण हो जाये, नहीं तो अभी तो फैशन, दिखावटी, आडम्बर में, आम आदमी, ईमानदार आदमी पैदल चलेगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आमदनी से ज्यादा जहां पर खर्चा है, वहां पर भ्रष्टाचार है। इसमें जांच की क्या जरूरत है। ...(**व्यवधान**)...

श्री बलबीर पुंज : उन्होनें भ्रष्टाचार की गंगोत्री के बारे में बताया थ, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। देश में भ्रष्टाचार की गंगोत्री कहां है ? आप तो लोहिया जी की अच्छी तरह से पढ़े हैं।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : गंगोत्री हिमालय के ऊपर में हैं। वहां से उत्तराचंल से पानी चलता है और नीचे सब साफ होता है, फिर भी नदियां साफ नहीं हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री बलबीर पुंज : लोहिया जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री इस देश में है। आप इसके बारे में बताइये।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : डा. लोहिया ने कहा था कि जब ऊपर से भ्रष्टाचार चलेगा, तो नीचे छलनी लगाने से सफाई नहीं होगी। ...(**व्यवधान**)... सहमत है, सहमत है इसीलिए तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ऊपर से निर्मल धारा ला रहे हैं कि नीचे से सब भ्रष्टाचार खत्म हो जाये। हम उस पर कायम है। उन्होनें भ्रष्टाचार से सावधान रहने और उसका मुकाबला करने के लिए कहा है। भ्रष्टाचार से मुकाबला सब लोग मिलकर करें और उसमें हम हर एक का सुझाव और सहयोग लेने के लिए, शामिल करने के लिए हम सहमत है। तिवारी जी बोल रहे थे कि पहले सम्पन्न्ता और फिर समता। अब तिवारी जी बोल दिए कि पहले समता तब सम्पन्नता। यह दो तरह के बोल लोहियावादी आपस में कंट्राडिक्ट करेगा, तो सबसे कमजोर आदमी हम बीच में क्या करेंगे। ...(**व्यवधान**)...

श्री अमर सिंह : शरद जी आजकल एनडीए में हैं।

उपसभाध्यक्ष (प्रो.पी.जे.कुरियन) : आप प्लीज बैठ जाइये। ...(**व्यवधान**)... एक घंटा हो गया। ...(**व्यवधान**)...

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : सर, तिवारी जी ने सीएजी की रिपोर्ट का जिक्र किया। महोदय, एनआरजीए की शुरू में ही ...(**व्यवधान**)... अहलुवालिया जी, मैं अब खत्म ही कर रहा हूं। जहां कहीं भी सरकार का पैसा खर्च होगा, वहां सीएजी पहुंचेगी। वह तीन-चार वर्ष बाद पहुंचता, वह जांच बहुत व्याहारिक और उपयोगी नहीं होती है। हमने शुरू में कहा- हमने 200 जिलों में लागू किया, सीएजी से तुरंत जांच कराई, जांच करके हमको रिपोर्ट आयेगी और राज्य से तथा सभी से हम कहेंगे कि इसमें सुधर किया जाये, इम्पूवमेंट किया जाये। इसीलिए उसकी जो रिपोर्ट आई है, उसके बारे में सभी राज्यों को कहा है कि जहां के बारे में रिपोर्ट आई है, उसकी छानबीन करिए, उस पर कार्यवाही करिए। इस तरह की शिकायतें अन्य जगहों से प्ारप्त न हों और फिर 130 जिलों में भी जांच करने के लिए कहा है। हम हर तरह से चाहते है कि करप्शन को खत्म किया जाये और जीरो टालरेंस करप्शन की स्थिति ...(**व्यवधान**)... अन्ना डीएमके SHRI S. ANBALAGAN ने सुश्री जयललिता जी की प्रंशसा की, उन्होनें अपने नेता की तारीफ की, क्योंकि बढ़िया तरीके से स्कीम को लागू किया था ...(व्यवधान)... श्रीमती सुप्रिया सुले जी ने बहुत सवाल उठाया था। इन्होनें बहुत से सुझाव भी दिये हैं। वहां से गांव का गरीब आदमी आता है, दिल्ली वाला चला आता है वैट को सुनने के लिए, अब हम संकट में पड़ते, हमने श्रीमती शीला दीक्षित जी को लिखा कि सैल्फ ग्रुप के लिए वैट माफ कर दीजिए। वह कहती है कि इसके लिए कानून में प्रावधान ही नही है। उन्होने कहा कि वैट हमको भारत सरकार को देना पडेता है उन्होनें सवाल उठाया कि जो रूरल प्रोंडक्ट्स है, उनको वैट और सब टैक्सों से छूट दी जाये, हम इससे सहमत है। लिखा पढ़ी करें, सदन के लोग हमारा साथ देंगे, तो इस पर भी हमारा काम हो जायेगा। महोदय, इन्होनें और कई सदस्यों ने बैंक का सवाल उठाया है। महोदय, बैंक के तीन नियम है। जहां अनबैंक्ड एरिया है अर्थात् जिस एरिया में बैंक नहीं हैं, तो वहां पर गरीबी कैसे हटेगी ? बिना बैंकों के सहयोग से गरीबी कैसे हटेगी, नम्बर-एक और नम्बर दो, इंटरनेट रेट, हमने फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा है कि इंटिरेस्ट रेट 12 परसेंट लगेगा, तो उन्होने कहा है कि ज्यादा नही लगेगा। अभी भी गरीब आदमी पर 11,12 और 13 परसेंट इंटिरेस्ट रेट लग रहा है। फिर हमने लिखा पढ़ी की, 42 बैंकों की शाखाएं zero lending अथवा below 25 percent lending पर-तो महोदय, हमारा बैंकों से तीन तरह का झंझट और सवाल है। कहीं-कहीं उसके सहयोगी बैंक अच्छा काम भी कर रहें हैं, इसलिए उच्चकोटि का इंस्टिट्यूट बैंक की तरफ से self-employment Institute बनना चाहिए। इसमें 23, 23 जगह पर अच्छा काम हो रहा है। इससे लोगों को रोजगार मिल जाएगा, त्वरित काम मिल जाएगा और गरीबी हट जाएगी। ...(**व्यवधान**)... श्रीमती वृंदा कारत जी ने मार्केटिंग का सवाल उठाया था। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (प्रो.पी.जे.कुरियन) : मंत्री जी, अभी और कितने मिनट चाहिंए ?

श्री रघुवंश प्रसार सिंह : हम रेल मंत्री की सरकार में, भारत सरकार में और राज्य सरकार में, सभी जगह लिखा-पढ़ी करेंगे कि मार्केटिंग ऑफ रूरल प्रोडक्ट ...(**व्यवधान**)... उनको खरीदकर के इस्तेमाल किया जाए। हम रेल मंत्री जी को तुरंत लिखेंगे। ...(**व्यवधान**)... हमने श्री प्रवीण राष्ट्रपाल जी के वेरिएशन इन मिनिमम वेज का जवाब दे दिया है और जो उनका सुझाव है कि एकाउंट से भुगतान हो, हमने वह भी मान लिया है। आप लोग भी जाकर देखिए और unemployment allowance के बारे में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्य ने बताया है कि वहां भी कहीं-कहीं मिला है। यह बात ठीक है राज्यों के साथ नाम चेंज की बीमारी है कि वे नाम चेंज की हेराफेरी कर देते हैं, तो हम राज्य से कितना झंझट करेंगे। डा. ज्ञान प्रकाश पिलानिया ने बड़े प्रोत्साहन और ग्रामीण विकास पर काफी जोर लगाया है, इससे हमको बड़ा हौंसला मिला है। पिलानिया साब बोल रहे हैं कि ग्रामीण विकास के बिना देश का विकास नहीं होगा और महात्मा गांधी जी का सपना – देश की आत्मा गांवो में बसती है, इस तरह से सबका सहयोग मिलेगा तो काम हो सकता है। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्षता (प्रो.पी.जे.कुरियन) : मंत्री जी, अभी एक घंटा हो गया है।

श्री रघुवंश प्रसार सिंह : महोदय, कुमारी निर्मला देशपांडे जी ने जानकारी के लिए कहा है कि हमने स्व्ंा सहायता समूह के लिए, स्वंयसेवी संस्थाओं के सहयोग से civil society से, रोजगार नागरिकता पुरस्कार का एलान किया है।

उपसभाध्यक्ष (प्रो.पी.जे.कुरियन) : मंत्री जी, अभी और कितने मिनट चाहिएं।

श्री रघुवंश प्रसार सिंह : बस खत्म किया, खत्म किया। इसलिए हम उनके सुझाव को मानते है और लागू कर रहे हैं और जैसा कि माननीय सदस्य श्री राजनीति प्रसार जी ने sanitation के बारे में कहा है, तो total sanitation campaign

में 2012 तक निर्मल भारत होगा और फिर हम बिहार के लिए प्रयत्न करेंगे। श्रीमती ठाकुर विप्लव तथा शिवा ने बॉयाड़ीजल का सवाल उठाया है। हमने पिछले साल 50 करोड़ रूपया राज्यों को दिया है बहुत सी राज्य सरकारों ने अपनी तरफ से बॉयोडीज़ल, जेट्रोफा की खेती शुरू की है, तो हमने उनकी सहायता के लिए पिछले साल तथा उससे पिछले साल, दो साल तक 50-50 करोड़ विभिन्न राज्यों को दिए हैं। हम इस साल राज्यों को पैसे नहीं दे सकें, क्योंकि 11वीं योजना की शुरूआत हो गई थी। हम जो बॉयोड़ीज़ल मिशन को कैबिनेट में ले गए थे, तो ग्रुप आफॅ मिनिस्टर्स की बैठक हुई है, जब यह बैठक पूरी हो जायेगी, तो तब होगा। यह 1500 करोड़ का है, लेकिन वह अभी ...(**व्यवधान**)...

श्री अमर सिंह : किसानों का क्या होगा, पैसा नहीं दिया तो ...(**व्यवधान**)... आप बोलें हैं कि पिछलें साल दिए थे, इस साल नहीं दिए हैं।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : वह किसानों के लिए नहीं था। वह शुरू में दिया था कि जो मिशन है, उसमें ढ़ाई लाख हैक्टेयर वनभूमि हैं ।...(**व्यवधान**)... वनभूमि में ढ़ाई लाख हैक्टेयर गैर वनभूमि, जो वेस्टलैंड है, जहां पर कुछ नहीं होता, उसमें बॉयोडीज़ल की, जेट्रोफा की खेती की शुरूआत थी। उसमें राज्य सरकारें कर रही है, हमने राज्य सरकार को seedling plant लगाने के लिए, खरीदकर लोगों को देने के लिए दिया था। उससे आगे का काम राज्य सरकारें स्वयं कर रही हैं। माननीय सदस्यों की इच्छा होगी तो हम उनको बता देंगे कि सभी राज्यों में क्या स्थिति है, लेकिन जब हमें मिशन की मंजूरी मिल जाएगी तो हम बॉयोडीज़ल पर हम ...(**व्यवधान**)...

श्री अमर सिंह : यह मिशन की मंजूरी कब तक हो जाएगी ?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : अब यह बैठक क्या हमारे हाथ में हैं ?

श्री अमर सिंह : सर, आप कैबिनेट मंत्री है।...(**व्यवधान**)...

श्री रघुवंश प्रसादसिंह : रेल मंत्री है, हम सदस्य है और चेयरमैन बैठक बुला लेंगे, तो उसकी एक बैठक हो जाएगी और एक बैठक हो चुकी है। श्री राम नारायण साहु जी ,ने श्रीमती जया बच्चन जी ने accountability के लिए लिए कहा। उन्होनें स्कूलों में पानी और पाखाना का बड़ा बढ़िया सवाल उठाया है। हमारा लक्ष्य था कि 31 दिसम्बर 2007 तक स्कूलों में पानी और पाखाना, दोनों की व्यवस्थ कर दी जाए। कुछ राज्य पीछे हो गए और कुछ राज्यों ने पूरा कर लिया है। इसलिए अब 31 मार्च तक या हमें लगता है कि जून तक सभी राज्य इसको पूरा कर लेंगे। कुछ राज्य इसमें आगे-पीछे चल रहें हैं। इसलिए इसमें भी हमने सफलता प्राप्त की है। अनुसुईयसा जी का जवाब हम दे सकें। श्री गिरिश कुमार सांगी जी ने नलगोंडा में फ्लोराइड का सवाल उठाया था, हमने उसका जवाब दे दिया।

इसलिए जो भी माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया और अभी तक बैठ कर उन्होनें रूचि ली, हम उनके प्रति मंत्रालय की ओर से आभार प्रकट करते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि इसी तरह से सभी लोगों का सहयोग होगा, तो अपने हिन्दुस्तान के माथे पर गरीबी और बेरोजगारी का जो कलंक है, वह कलंक मिट जाएगा और 2020 तक हिन्दुस्तान को दुनिया की अगली पंक्ति के देशों में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ, सभी माननीय सदस्यों के प्रति और आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। ग्रामीण विकास जिन्दाबाद, ग्रामीण समृद्धि जिन्दाबाद।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. RJ. KURIEN): The House is adjourned to meet tomorrow at 11.00 A.M. on 22nd April, 2008.

The House then adjourned at thirty-six minutes past six of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 22nd April, 2008.